

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 1991

खण्ड 1, अंक 11

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भुक्तवार, 15 मार्च, 1991

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	(11)1
तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर	(11)26
विभिन्न विशयो का उठाया जाना	(11)26
वाक आउटस	(11)34
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव— गायो के वध के लिए उत्तर प्रदेश में ले जाने संबंधी	(11)36
वक्तव्य— पुपालन राज्य मंत्री द्वारा उर्पयुक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(11)36
घोशणा— सचिव द्वारा	(11)38
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(11)39

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(11)39
समितियों की रिपोर्टस पे ा करना	
(1) कमेटी औन पब्लिक अंडरटेकिंगज की 31वीं रिपोर्ट	(11)40
(2) कमेटी औन ऐस्टीमेट्स की 23वीं रिपोर्ट	(11)40
(3) कमेटी औन गवर्नमेंट अ योरेंसिज की 22वीं रिपोर्ट	(11)40
(4) कमेटी औन दि वैलफेयर आफ ि ाडयूल्ड कास्ट्स एण्ड ि ाडयूल्ड ट्राइब्ज की 16वीं रिपोर्ट	(11)41
बिलज—	
(1) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 1) बिल, 1991	(11)41
(2) दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 2) बिल, 1991	(11)46
(3) दि हरियाणा एण्ड पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज (हरियाणा अमैडमेंट) बिल, 1991	(11)50
(4) दि हरियाणा रुल्ज डिवैल्पमेंट (अमैडमेंट) बिल, 1991	(11)53
(5) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एण्ड डिवैल्पमेंट) अमैडमेंट बिल, 1991	(11)55

(6) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले इन एण्ड डिवैल्पमेंट) अमैडमेंट बिल, 1991	(11)57
(7) दि पंजाब टाउन इम्पूवमेंट (हरियाणा अमैडमेंट) बिल, 1991	(11)61
(8) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैडमेंट) बिल, 1991	(11)64
(9) दि हरियाणा पब्लिक वक्फस (ऐक्सटैन् इन आफ लिमिटे इन) बिल, 1991	(11)65
(10) दि हरियाणा मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्ज (टोल) बिल, 1991	(11)67
(11) दि पंजाब विपेज कौमन लैण्डज (रैगुले इन) हरियाणा अमैडमेंट बिल, 1991	(11)73
(12) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैडमेंट) बिल, 1991	(11)78
(13) दि हरियाणा श्री माता मनसा देवी भाराइन बिल, 1991	(11)82
(14) दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एण्ड पैन् इन औफ मैम्बर्ज) अमैडमेंट बिल, 1991	(11)84
(15) दि पंजाब सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर्ज	(11)86

(हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 1991	
सरकारी संकल्प— जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) सं गोधन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 53) को ग्रहण करने सम्बन्धी	(11)88
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव— (1) वर्ष 1989-90 के लिए हरियाणा राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट (बहस हुई)	(11)89
(2) वर्ष 1987-88 के लिए हरियाणा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक वित्तीय लेखे (पे 1 नहीं हुआ)	(11)91
(3) हरियाणा पिछडा वर्ग आयोग, 1990 जिसकी अध्यक्षता न्यायाधी 1 गुरनाम सिंह ने की थी की रिपोर्ट (बहस हुई)	(11)92
(4) वर्ष 1987-88 के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट (पे 1 नहीं हुआ)	(11)100

(5) वर्ष 1988-89 के लिए हरियाणा कृषि उद्योग लिमिटेड की 22वीं वार्षिक रिपोर्ट (पे 1 नहीं हुआ)	(11)100
<p>वक्तव्य—</p> <p>गृह मंत्री द्वारा मंडल आयोग विरोधी आंदोलन के दौरान श्री सूरज भान, एम0 एल0 ए0 के घर पर हुए हमले संबंधी</p>	(11)100
अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद	(11)102

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 15 मार्च, 1991

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 9.30 बजे हुई। (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्र न संख्या 1276

यह प्र न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, कैप्टन अजय सिंह यादव, सदन में उपस्थित नहीं थे।

Government Schools Withut Floormats in the State

***1285. Shrimati Kamla Verma:** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether the Government is aware of the fact that most of the Governmnet schools in the villages and cities in the State are without floormats; if so, the time by which the floormats are likely to be provided in these schools?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह): सरकार को विदित है कि कुछ राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में फ्लोरमेट (टाट-पट्टी) पर्याप्त नहीं है। टाट-पट्टी नष्ट होने वाली वस्तु होने के कारण,

सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को नियमित तौर पर टाट-पट्टी उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्न मिल रही है।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो पब्लिक स्कूलों की पढाई बड़ी महंगी हो रही है और आम आदमी का बच्चा वहां जा नहीं सकता लेकिन दूसरी ओर गावों के प्राइमरी स्कूलों की बात तो मैं क्या करूँ, भाहरों के मिडिल स्कूलों या प्राइमरी स्कूलों के अन्दर बच्चों के बैठने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। बच्चे बिना टाट-पट्टी के जमीन पर ही बैठते हैं। इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार गावों व भाहरों के स्कूलों के अन्दर बच्चों की आम सुविधाओं के लिए कोई प्रयास करेगी ताकि लोगों की रुचि पब्लिक स्कूलों से हटकर सरकारी स्कूलों की ओर ही रहे क्योंकि पब्लिक स्कूलों के अन्दर अपने बच्चों को पढ़ाना एक साधारण आदमी के बस की बात नहीं है?

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं बहन जी को यह बता देना चाहता हूँ कि इस साल साढ़े 27 लाख रुपये की टाट-पट्टी खरीदी जा रही है और यह काम हाई पावर्ड कमेटी द्वारा जेल विभाग को टाट-पट्टी सप्लाई करने के लिए सौंपा गया है।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि शिक्षा विभाग ने सारी ऐसटेबलिमेंट के लिए कुल कितना रुपया रखा हुआ है?

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय इसके लिए सैपरेट नोटिस दें।

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, स्कूलों में टाट-पट्टी नहीं, अस्पतालों में बट्टी नहीं। सरकार इस दयनीय स्थिति से कब उपर उभरेगी? क्या इसके लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है?

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, प्रयास तो हो ही रहे हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि इस साल साढ़े 27 लाख रुपये की टाट-पट्टी खरीदी जा रही है। मैं उन से यह जानना चाहता हूँ कि वे साल के आखिर में साढ़े 27 लाख रुपये किस प्रकार से खर्च कर रहे हैं और सारा साल ये क्या करते रहे? पहले दिनों में इन्होंने यह खर्चा क्यों नहीं किया? साथ में यह भी बतलाए कि यह जो टाट-पट्टी मंगवा रहे हैं, कितने स्कूलों के लिये मंगवा रहे हैं?

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): अध्यक्ष महोदय, टाट-पट्टी के लिए जेल विभाग को सरकार ने बहुत पहले से ही आर्डर दे रखा है। कुछ तो जेल विभाग ने सप्लाई की है और बाकी के लिए

उन्हे हिदायते दे रखी है कि वे जल्द से जल्द सप्लाई करे ताकि उस टाट-पट्टी को जल्द से जल्द स्कूलों में भिजवा दिया जाए।

श्री कैला । चन्द्र भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बतलाया कि यह टाट-पट्टी वाली आइटम समाप्त होने वाली आइटम है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि स्कूलों में टाट-पट्टी बदले जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है कि इतने समय के अन्दर यह टाट-पट्टी बदली जाएगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, टाट-पट्टी की एक साल के अन्दर अन्दर डिमांड कर लेते हैं। 1990-91 में प्राइमरी स्कूलों की 11 लाख 33 हजार 332 मीटरज टाट-पट्टी की डिमांड थी जिसके विरुद्ध हम 4 लाख 3 हजार 661 मीटरज जेल विभाग से लेकर सभी जिलों को भिजवा रहे हैं।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, अकसर बजट के पहले दस महीनों में पैसा खर्च न करके पिछले दो महीनों में खर्च पर जोर दिया जाता है और उन्हीं दो महीनों में इधर उधर से टैण्डर काल कर लिये जाते हैं और काम पूरा करने का यत्न किया जाता है जो कई बार ठीक नहीं हो पाता। क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि इसके क्या कारण हैं?

श्री हुकम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं बहन जी को यह बता देना चाहता हूँ कि इधर उधर से टैण्डर काल नहीं किये जाते। यह आइटम केवल जेल विभाग से ही खरीदी जाती है न

कि किसी प्राइवेट आदमी से खरीदी जाती है। वहां से टाट-पट्टी आने पर स्कूलों में भेजने का प्रबन्ध किया जाता है।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब है कि जितना भी सरकारी कार्यालयों का व्यय होता है, वह पहले 10 महीनों तक तो नहीं किया जाता लेकिन पिछले दो महीनों में पैसे को खर्च करने के लिए जोर दिया जाता है ताकि यह पैसा लैप्स न हो जाए। क्या सरकार अपनी इस नीति को सुधार लाने का प्रयास करेगी ताकि पैसा सही समय पर और सही कामों पर खर्च किया जा सके?

श्री हुकम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि यह आर्डर हमने बहुत पहले से जेल विभाग को दे रखा था।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस समय कितने ऐसे स्कूल हैं जिनमें टाट-पट्टी नहीं है?

श्री हुकम सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह तो नहीं कहा जा सकता कि कितने स्कूल हैं जिनमें टाट-पट्टी नहीं है लेकिन मैं सदन को विवास दिलाता हूँ कि हमने जेल विभाग को कह दिया है कि वह पूरी सप्लाई जल्द से जल्द करे।

यह प्र न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री परमा नन्द, सदन में उपस्थित नहीं थे।

Construction of Roads

***1368. Shri Sita Ram Singla:** Will the Minister for P.W.D (B&R) be pleased to state the number of roads constructed in Gurgaon Assembly Constituency during the year 1989-90 together with the details thereof?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जगन नाथ): गुडगांव विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 300 मीटर लम्बी एक पहुंच सड़क गुडगांव फारुखनगर सड़क से गांव धनकोट के राजकीय उच्च विद्यालय तक बनाई गई है।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, गुडगांव में दिन बदिन आबादी बढ़ रही है। ऐसी सूरत के अन्दर सारे साल में केवल तीन सौ मीटर सड़क बनी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गुडगांव से इनके पास कितनी प्रपोजल आई और उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल कितनी की हुई?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, इन्होंने पूछा था कि इस साल कितनी सड़कें बनी हैं। हमने एक सड़क बना दी है। इसके अलावा आठ सौ मीटर की सड़क गांव बालुपुर से नानक हेडी तक बनाई है। तीन और सड़को पर काम चल रहा है। इसके अलावा 12 सड़को की मुरम्मत की गई है। गुडगांव में तो बहुत काम हो

रहे हैं क्योंकि वहां हुडडा के काम भी चल रहे हैं, वहां स्टेट हाईवे भी है और नेशनल हाईवे भी वहां से जाता है।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, ये अपने विभाग के बारे में बात करे, दूसरे विभाग की बात मत करे। मैं जानना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से कितनी प्रपोजल आई और इन्होंने कितनी की ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल दी?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, इन्होंने प्रपोजल के बारे में नहीं पूछा था। मैंने बताया है कि इसके अलावा तीन और सड़को पर काम चल रहा है। वे हैं गुडगांव से फरुख नगर, वजीराबाद से धाटा ओर बजगोडा से जहाज पुर। इसके अलावा हमने 12 सड़को की मुरम्मत का काम भी किया है।

श्री सीता राम सिंगला: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बता दे कि इस सड़क की ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल 1987 से पहले की है या इस सरकार ने दी थी?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, इसकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल 9-12-1985 को हुई थी।

श्री रामविलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, गुडगांव चुनाव क्षेत्र का यह सवाल है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वर्ष 1990-91 के दौरान इनके विभाग ने इनके पास कितनी नई सड़के बनाने के प्रस्ताव भेजे और उनमें से कितनों पर विचार किया गया, अगर नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया?

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, जो मेन सवाल है उसमें यह नहीं पूछा गया था कि वहां पर कितनी सडके बनाने का प्रस्ताव था और उनमें से कितनी सडके बना दी गई है और कितनी बाकी रहती है। फिर भी मैंने बता दिया है कि दो सडको पर काम पूरा हो चुका है, तीन सडको पर काम चल रहा है और 12 सडको की मुरम्मत की गई है।

Science & Technology Park at Ambala

***1319. Shri Anil Kumar Vij:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a science & Technology Park at Ambala Cantt; and

(b) if so, the time by which the aforesaid park is likely to be opened?

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह):

(क) हां।

(ख) उपरोक्त प्रस्ताव भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) को विचारार्थ भेजा हुआ है। अभी कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

श्री अनिल कुमार विज: स्पीकर साहब, इस प्रोजैक्ट को बनाने की घोशणा वर्ष 1987 के आखिर में या वर्ष 1988 में भुरु की गई थी। चार साल बीत जाने के बाद भी यह कहा जा रहा है कि यह प्रस्ताव भारत सरकार को विचारार्थ भेजा हुआ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव भारत सरकार को कब भेजा गया और अब उस पर फालोअप ऐक्शन क्या हो रहा है?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, यह प्रस्ताव फरवरी महीने में भेजा गया था। जब तक भारत सरकार और आई० डी० बी० आई० पैसा नहीं देंगे तब तक इस पर काम भुरु नहीं हो सकता।

श्री अनिल कुमार विज: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस प्रोजैक्ट पर कितने पैसे खर्च होने की सम्भावना है और इस प्रोजैक्ट पर जितना पैसा खर्च होगा उसमें से भारत सरकार, हरियाणा सरकार और आई० डी० बी० आई० की तरफ से कितना कितना पैसा दिया जाएगा?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, यह प्रोजैक्ट 10 एकड जमीन पर बनना है और इस पर 1करोड 67लाख रुपए खर्च होंगे जिसमेंसे हारटोन साढे 24 लाख रुपए, हरियाणा सरकार 21 लाख 25 हजार रुपए, भारत सरकार 38 लाख रुपए और आई० डी० बी० आई० 83 लाख 75 हजार रुपए देगा।

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, इस प्रोजैक्ट को बनाने के लिए कुछ पैसा केन्द्रीय सरकार ने खर्च करना है। यह मामला तीन साल से लटका हुआ है। अब उन्होंने उसकी प्रोजेक्ट फरवरी के महीने में इसलिए भेजा है क्योंकि यह क्वै चन माननीय सदस्य ने फरवरी में ही आपकी सेवा में दिया है। मैम्बर साहब ने क्वे चन फरवरी में दे दिया इसलिए उसकी प्रोजेक्ट भेज दी वरना पता नहीं भेजी जाती या नहीं भेजी जाती। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्रोजैक्ट की प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेजने में डिले के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया है?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, इसमें कोई किसी प्रकार की डिले नहीं हुई है। इसकी प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं हुई थी। इसकी प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही यह प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

श्री अनिल कुमार विज: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने बताया कि यह प्रोजैक्ट 10 एकड़ जमीन पर बनना है। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह जमीन ऐक्वायर कर ली गई है?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, अभी तो उस प्रोजैक्ट के बारे में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। यदि भारत सरकार और आई० डी० बी० आई. मान जाएंगे तो उसके बाद ही

जमीन ऐक्वायर की जा सकती है। पहले जमीन ऐक्वायर करने का क्या फायदा है?

डा० रघुबीर सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो इस साईंस एण्ड टैक्नोलोजी पार्क की प्रोपोजल बनी है वह किन औब्जेक्ट्स को सामने रख कर बनाई गई थी? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या इस साईंस एंड टैक्नोलोजी पार्क और डिजनीलैंड (अम्यूजमेंट पार्क) में सिमीलैरिटी है?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, कादियान साहब पी० एच० डी० है इसलिए उनको खुद ही इस बारे में जानकारी होनी चाहिए।

श्री सीता राम सिंगला: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार के साईंस एण्ड टैक्नोलोजी पार्क किसी और जिले में भी बनाने की प्रोपोजल सरकार के पास आई है?

श्री हुकम सिंह: स्पीकर साहब, भिवानी और कुरुक्षेत्र जिले से आई है।

Recruitment of Drivers and Conductors in Transport Deptt.

***1341. Shri Muni Lal:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) the district-wise number of Drivers and Conductors recruited in the Transport Department during the last three and a half years togetherwith the number of persons belonging to Scheduled Csters and Backward Classes amongst them; and

(b) whether the posts for the persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes have been filled up according to the prescribed quota?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री वेद सिंह मलिक):

(क) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध 'ए' मे दी गई है जोकि विधान सभा के पटल पर रखी जाती है।

(ख) जी नहीं, इसमें थोडी सी कमी है।

अनुबन्ध 'ए'

क मां क	डिपो नाम	का चाल को की कुल संख्य T	अनु- सूचित जाति से संबंधित	पिछडे वर्ग से संबंधित	परिचाल को की कुल संख्या	अनु- सूचित जाति से संबंधित	पिछडे वर्ग से संबंधित
1	अम्बाला	75	13	6	79	16	8
2	जीन्द	125	85	9	71	12	10

3	कैथल	74	5	6	32	7	4
4	सोनीपत	97	0	11	95	18	8
5	चण्डीगढ	146	20	17	132	23	15
6	करनाल	112	2	12	116	25	12
7	यमुनानगर	84	3	10	73	12	11
8	कुरुक्षेत्र	36		3	35	6	4
9	गुडगांव	76	3	6	46	7	4
10	रेवाडी	73	5	5	53	8	3
11	भिवानी	166	14	14	38	7	5
12	फरीदाबाद	74	12	6	32	6	3
13	रोहतक	144	6	13	97	30	12
14	हिसार	70	1	7	91	8	7
15	सिरसा	92	3	17	52	14	11
16	दिल्ली	48		5	10	1	1
17	फतेहाबाद	70	2	8	51	7	7

कुल संख्या	1562	104	155	1103	207	125
---------------	------	-----	-----	------	-----	-----

श्री मुनी लाल: स्पीकर साहब, इस विभाग में 1562 चालको की भर्ती की गई है जिनमें से 104 चालको की पोस्टो पर रिजर्वेड कास्टस कैंडिडेट लगाए है जबकि रिजर्वेड इन के हिसाब से 306 लिए जाने चाहिए थे। वैलफेयर ऑफ रिजर्वेड कास्टस एंड रिजर्वेड कास्टस कमेटी का मैम्बर होने के नाते मुझे यह पता है कि भिन्न-भिन्न विभागो में रिजर्वेड इन का कोटा पूरा नहीं है, बहुत बैकलौग है और हर साल बैकलौग बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो 202 चालको का बैकलौग है क्या इसकी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा और यह बैकलौग किन कारणो से रह गया?

श्री वेद सिंह मलिक: स्पीकर साहब, ड्राईवर के लिए लाइसेंस और तजुर्बे की जरूरत होती है और उस समय रिजर्वेड कोटे के हिसाब से रिजर्वेड कास्टस कैंडिडेट यह योग्यता पूरी नहीं करते थे इसलिए यह बैकलौग रह गया।

श्री मुनी लाल: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हजारो बेरोजगार ड्राईवरो के नाम रोजगार कार्यालयो में दर्ज है। क्या उनको ये लगाने की कृपा करेंगे?

श्री वेद सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मैं इन्हे बताना चाहता हूँ कि एस० एस० एस० बोर्ड के अलावा एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से हमने एस० सी० के 51 और बी० सी० के 66 ड्राइवर लिए हैं। इसी प्रकार से एस० सी० के 42 और बी० सी० के 29 कन्डक्टर्स भी रोजगार विभाग के जरिए लिए हैं।

श्री भाग मल: स्पीकर साहब, 28-2-91 को सरकार की तरफ से एक स्पेशल गजट नोटिफिकेशन निकाला गया है जिसके पैरा 1 के सब पैरा 2 में यह लिखा है कि जनरल कैटेगरी से ज्यादा भर्ती कर ली जाये और जो रिजर्व कोटे की वैकेंसी बचेंगी उनको बाद में भर लिया जायेगा। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या एस० सी० और बी० सी० के लोगों के साथ ये भेदभाव करके उनको डिबार तो नहीं करना चाहते क्योंकि ये उनका कोटा पूरा नहीं करना चाहते? इस बारे में मंत्री महोदय कृपया स्थिती स्पष्ट करें?

श्री वेद सिंह मलिक: स्पीकर साहब, रिजर्व कोटे को भी अब य पूरा किया जायेगा। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि ड्राइवर्स के लिए लाइसेंस और 5 साल का तजुर्बा होना जरूरी है। हमें एस० सी० के ऐसे कम लोग मिलते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एस० सी० की खाली पडी पोस्टो को भी जल्दी से जल्दी भर लिया जाये।

श्री उदय भान: स्पीकर साहब, जो संख्या चालको ओर परिचालको की इन्होने अपने लिखित जवाब में दिखाई है उसमें से एस0 एस0 एस0 बोर्ड और दूसरी जगहो से कितने लोग लिए गए है। लिस्ट में दी गई सूचना के आधार पर तो ड्राइवर्ज की यह संख्या सिर्फ साढे छः प्रसेंट बैठती है। मै जानना चाहता हूं कि इनको क्या एस0 सी0 के लडके नही मिल रहे या और किसी कारण से इन खाली पडी पोस्टो को नही भरा जा रहा है। मै यह भी इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले सै ान में इन्होने कन्डक्टर्ज की संख्या 1503 दिखाई थी और अब जवाब में 1103 दिखा रहे है, इसलिए मै मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसमें से कौन सी फिगर ठीक है?

श्री वेद सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, एस एस एस बोर्ड से एस सी के 53 और बी सी के 89 ड्राइवर्ज लिए है। इसी तरह से एस सी के 165 और बी सी के 96 कन्डक्टर्ज लिए गए है।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो भर्ती इन्होने की है क्या यह सारी एस0 एस0 एस0 बोर्ड और रोजगार कार्यालय के माध्यम से की है या किसी और प्राइवेट एजेन्सी के जरिए भी की है?

श्री वेद सिंह मलिक: स्पीकर साहब, हमने यह भर्ती एस0 एस0 एस0 बोर्ड और रोजगार कार्यालय के माध्यम से की है।

श्री दुर्गा दत्त अत्री: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एस एस एस बोर्ड के द्वारा जो लिस्ट निकाली गई थी उन सभी को नौकरी पर रख लिया गया है। (विध्वन्) मैं यह इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि जो भर्ती की गई है उसमें चण्डीगढ़ और दिल्ली के लोग कहां से आ गए?

श्री वेद सिंह मलिक: स्पीकर साहब, एस० एस० एस० बोर्ड से जो लिस्ट आई थी उसके अनुसार हमने सारे लोग तो नहीं लगाये। लेकिन मैं स्थिति स्पष्ट करते हुए बताना चाहूँगा कि पहले एक व्हीकल के पीछे चार आदमियों का नाम फिक्स किया हुआ था। हमने ओवर टाईम कम करने के लिए और रोजगार देने के लिए यह नाम 1-4 से बढ़ाकर 1-7 कर दिया था लेकिन बाद में श्री बनारसी दास गुप्ता जी ने अपने मुख्य मंत्री काल में यह नाम फिर 1-7 से घटाकर 1-4 कर दिया। इस वजह से जो लिस्ट वहां से आई थी उस हिसाब से हम इन्हें नहीं लगा पाये।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, एस० सी० और बी० सी० के काफी कम लोग लगाये हैं जिसकी वजह से इनका बैकलॉग भी चला आ रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जब एस० एस० एस० बोर्ड के माध्यम से इनके पास बी० सी० के कैंडीडेट्स मिल सकते हैं तो फिर इनको क्यों नहीं लगाया जाता? एक तरफ तो कहते हैं कि मिलते नहीं ओर दूसरी तरफ मिलते हैं तो लगाते नहीं। मैं एक ऐसे बी० सी० कंडक्टर का रोल नम्बर

आपको दे सकती हूं जिसको एस0 एस0 एस0 बोर्ड ने चुन लिया पर नियुक्ति नहीं की। क्या ये बताएंगे कि उसका क्या कारण है?

श्री वेद सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, बी0 सी0 के कैंडीडेट्स तो हमने पहले ही ज्यादा रखे हुए हैं, उनमें कोई बैकलॉग नहीं है।

श्री योगे । चन्द भार्मा: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एस0 एस0 एस0 बोर्ड से जिन नामों की सिफारिश की गई थी क्या उन नामों की सिफारिश में कमी रह गई थी जिसकी वजह से इनको बाद में बजाये एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के भी डायरेक्ट भर्ती करनी पड़ी?

श्री वेद सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, एस0 एस0 एस0 बोर्ड से हमारे पास ड्राईवर्स की 1527 की लिस्ट आई थी। इसमें से 305 एस0 सी0 के और 153 बी0 सी0 के ड्राईवर्स थे।

श्री भगवान सहय रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने योग्य मंत्री जी से स्पेसिफिकली यह जानना चाहता हू कि 1562 चालक तथा 1103 कंडक्टर जो भर्ती किए गए हैं उनमें से कितने अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा और कितने अन्य साधनों से लिए गए और जो एस0 एस0 एस0 बोर्ड द्वारा उम्मीदवार सिफारिश किए गए हैं क्या उन सभी को सेवा में लेने बारे सरकार विचार करेगी?

श्री वेद सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि हमारे पास स्टाफ पहले की सरप्लस है, अगर जरूरत होगी तो बाद में उनको लिया जाएगा।

कामरेड हरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि चण्डीगढ़ डिपो के लिए 146 और करनाल डिपो के लिए 112 ड्राईवर्ज भर्ती किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि जो रिक्रूटमेंट की गई है वह जिलावाइजकी गई है या कि जैसे श्री धर्मवीर सिंह जी के समय एक ही हलके से भर्ती की गई थी, वैसे ही एक ही हलके से भर्ती की है?

श्री वेद सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, जहां तक एस0 सी0 का कोटा पूरा करने का ताल्लुक है इसमें दो आर्डर जारी हुए हैं। माननीय सदस्य, श्री भागमल जी ने 28 फरवरी का नोटिफिके इन का जिक किया है जिसमें एक आर्डर में यह कहा गया है कि भर्ती में बैकलॉग पूरा कर लिया है और दूसरे आर्डर में कन्ट्राडिक्ट किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ यह कानट्राडिक्ट इन क्यों है?

श्री वेद सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री उदय भान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जो कण्डक्टर्ज और ड्राईवर्ज भर्ती किए गए हैं उनमें एस० सी० का जो बैकलॉग है उसका क्या कारण है, क्या इन योग्यताओं के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए अथवा उनको जानबूझ कर नहीं लिया गया?

श्री वेद सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को यह बताना चाहूँगा कि योग्यताएं पूरी करने वाले एस० सी० कैंडिडेट्स उपलब्ध नहीं थे और जो बैकलॉग है उसको जल्दी ही पूरा किया जाएगा।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि ड्राइवरो के जो खाली पद हैं। (विघ्न)

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, 'खालिस्तान' कही नहीं है। (हंसी)

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, खालिस्तान की मांग तो इन्हीं के नेता ने की है हमने कभी खालिस्तान की मांग नहीं की है। यह मांग तो इनके नेता ने खुद ही की हुई है। (हंसी)

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, खालिस्तान किसी भी सूरत में नहीं बनने दिया जाएगा। हमारे किसी नेता ने भी खालिस्तान की मांग नहीं की है ये तो इन्हीं के नेता हैं जो ऐसी मांग करते हैं। (हंसी)

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि एस० एस० एस० बोर्ड की जो लिस्ट है उसमें जो कैंडिडेट्स हैं क्या उन सभी को नौकरी में लेने पर सरकार विचार करेगी?

श्री वेद सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पास स्टाफ सरप्लस है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी इस लिस्ट में से उम्मीदवारों को लिया जाएगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो ड्राइवर्ज और कण्डक्टर्ज भर्ती किए गए हैं उनमें से कितने सीधी दरखास्त ले कर भर्ती किए गए हैं, कितने एस० एस० एस० बोर्ड के जरिये भर्ती किए गए हैं और कितने अन्य साधनों से भर्ती किए गए हैं?

श्री वेद सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, एस एस एस बोर्ड से ड्राइवर्ज एस० सी० के 53 लिए गए हैं और बी० सी० के 89 लिए गए हैं।(तोर एवं व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब आप बैठिए।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, हम तो आपके आदे 1 को मानकर बैठ जाते हैं लेकिन आप इन सत्तापक्ष वालों को भी तो बैठने को कहिए।

Mr. Speaker: I request every body to take his seat please.

श्री िव प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि कब और कितने पद खाली पडे है?

श्री वेद सिंह मलिक: कोई स्थान खाली नही पडा है।

Electricity Sub-Station in Thanesar Constituency

***1303. Shri Ashok Kumar:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up Electricity Sub-Station in Thanesar Constituency during the year 1991&92; and

(b) if so, the location thereof togetherwith the time by which it is likely to be set up?

गृह मंत्री (प्रे० सम्पत सिंह):

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) पोपली के पास 132 के० वी० उप बिजली घर (सब-स्टे ान) स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह सब-स्टे ान (उप बिजली घर) वर्ष, 1992-93 के दौरान चालू होना सम्भावित है।

श्री अ गोक कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि यह सब-स्टे इन कब मंजूर हुआ था और इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर सर, अब तक हुडडा से इसके लिए जमीन ईयरमार्क करा दी गयी है। इसी वर्ष के अन्दर उस पर काम भुरु हो जाएगा और वर्ष 1992-93 के अन्दर यह काम समाप्त हो जायेगा।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या 132 के० वी० का सब-स्टे इन सीवन, जिला कैथल, के अन्दर अन्डर कंस्ट्रक् इन है, अगर है तो कब तक वह बन जायेगा?

श्री अध्यक्ष: यह सवाल सीवन के बारे में नहीं है। आप सवाल तो पढिये।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, मंत्री जी भायद जवाब दे रहे हैं। वे अपने कागज देख रहे हैं।

Mr. Speaker: No, I would not permit. it is not possible to reply off hand. He has a human brain and is not a computer (Interruptions).

श्री राम विलास भार्मा: स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में 132 के० वी० कितने सब स्टे इन बनाने का प्रस्ताव बिजली बोर्ड के पास पडा हुआ है?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, 132 के० वी० के सब-स्टे इन इस साल जो हम बनाने जा रहे हैं, वे चार हैं। हम इनको इस साल में पूरा कर लेंगे। बाकी कुछ 192-93 में भी बनायेगे। एक साल के अन्दर तो ये सारे पूरे नहीं हो पाएंगे इसलिए इस साल में हम 132 के० वी० के चार ही सब-स्टे इन पूरे कर सकेंगे।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ। (विधन्)

श्री अध्यक्ष: आज तो आप टौर में हैं। लगता है कुछ रंग दिखाओगे।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, अभी कुछ सदस्यों ने पगडी का जिक्र कर दिया। मैं जरा इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ (व्यवधान एवं भाोर)

Mr. Speaker: Please put a supplementary.

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, जहां तक पगडी के बारे में बात है, मैं इस महान सदन के सदस्यों को वि वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर यह पगडी लोक सभा में गयी तो यह सिर कट जायेगा लेकिन गज्जक और रेवडियां बांधकर कभी राजीव गांधी के चरणों में झुकेगी नहीं। (व्यवधान एवं भाोर) मैं इसमें रोहतक से गज्जक और रेवडियो बांध कर नहीं ले जाऊंगा। मैंने

लोगो को वि वास दिलाया है। यह पगडी उन लोगो की है जिन्होने मेरे सिर पर इसे बांध रखा है। (व्यवधान एवं भाोर)

Mr. Speaker: Mr. Kataria, please put a supplementary.

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मै अपने साथी महोदय से यह जानना चाहता हूं कि मेरा रादौर हल्का जो रिकार्ड तोड गेहूं, जीरी और गन्ना पैदा करता है, क्या इस क्षेत्र के अन्दर 132 के 0 वी 0 के सब-स्टे 1 न खोलने की इस साल या अगले साल में कोई प्रोपोजल है?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, सबसे ज्यादा अहमियत कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की हम दे रहे है क्योकि वहां पर बिजली की ज्यादा आव यकता है और वहां पर ओवर लोडिंग भी है। इसके अलावा उन्होने पगडी की बात छेड दी है तो मै समझता हूं कि रेवडियो का जिक भी जरुरी है। इसमें कोई दो राय नही है कि जब भी कोई ऐग्रीमेंट होता है, चाहे वह पोलीटीकल ऐग्रीमेंट हो, चाहे सो ाल ऐग्रीमेंट हो या कोई भी किसी किस्म का ऐग्रीमेंट हो तो उसमें निभानी पडती है। जिस मैरिज का इन्होने जिक किया, उसका सब को पता है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को भी रेवडियां दी थी। हमने इनको खुब रेवडियां खिलाई। बैड-रुम ऐग्रीमेंट था। बकायदा स्पीकर साहब, हमने इनको रेवडियां खिलाई और मलाई वाला दूध भी पिलाया लेकिन स्पीकर साहब, जो छाछ हुआ करती है, वह जैसे ठहरती नही है ऐसे ही ये भी नही ठहरे।

जब नही ठहरे तो हमने दूसरी पार्टी को आजमाना चाहा। जब वह भी किल्ले से भाग गयी तो हमने उसको भी परे किया और पब्लिक के सामने आ गये। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री राम विलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी को भागने वाली बात याद आ रही है। मैं एक महिला की बात बताना चाहता हूं। उसके बच्चे जब स्कूल में पढने गए तो वहां पर पूछा गया कि तुम्हारी जाति, बिरादरी क्या है। वे कहने लगे कि पहले तो थे हम जुलाहे, फिर हुए राजपूत और अब हुए दर्जी और आगे मां की मर्जी। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: कृप्या बैठिए। नैक्सट क्वै चन।

Vacant Post in Schools/Colleges

***1374. Shri Balir Singh Chaudhri/Capt. Ajay Singh Yadav:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) the year wise total number of posts of teachers/lecturers lying vacant in the Primary, Middle, High Senior Secondary Schools and Colleges in the State during the period from 1988 to-date; and

(b) the steps, if any, taken or proposed to be taken to fillup these posts?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह):

(क) सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ख) स्कूलों में रिक्त पद भीघ्न भरे जाने की संभावना है। कालेज प्राध्यापकों की भर्ती का मामला भी विचाराधीन है।

सूचना

राजकीय विद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों में वर्षवार रिक्तियों का विवरण

पद	दिसम्बर 1988	दिसम्बर 1989	दिसम्बर 1990
प्राध्यापक (विद्यालय)	118	221	596
मास्टरज / मिस्ट्रैसिज	193	809	1252
अध्यापक (सी० एंड बी०)	348	471	672
जे० बी० टी० अध्यापक	1562	1872	2982
महाविद्यालय (प्राध्यापक)			
1988		241	
1989		92	

10:00 बजे

श्री बलबीर सिंह चौधरी: स्पीकर साहब, पिछले सै ान में सरकार ने कहा था कि जल्दी टीचर्ज की सारी रिक्तियां भर देंगे लेकिन वे रिक्तियां भरी नहीं गईं और इस कारण विद्यार्थियों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मंत्री महोदय ने सदन के पटल पर जो स्टेटमेंट रखी है उससे पता लगता है कि हर साल रिक्तियां बढ़ती ही गईं हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है और ये रिक्तियां कब तक भर दी जाएंगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि इस सरकार का सत्ता में आने के बाद निरन्तर प्रयास रहा है कि ये रिक्तियां जल्दी से जल्दी भर दी जाएं। इसलिए हमने सरकार के माध्यम से एस एस एस बोर्ड को रिक्तियां भेजी, सी० एण्ड बी० टीचर्ज की 1200 के करीब वेकेंसीज भेजी और जे० बी० टी० टीचर्ज की 3 हजार के करीब भेजी। जिसमें से 1988 के बाद 360 मिस्ट्रसिज लगा दी है और उनको ज्वायन करवा चुके हैं। 611 सी० एंड वी० टीचर्ज को ज्वाइन करवाया है। स्पीकर साहब, एस० एस० एस० बोर्ड ने दो साल तक मास्टर्ज की सिलेक् ान नहीं की और न ही जे० बी० टी० टीचर्ज को सिलैक्ट किया। इस कारण सरकार ने इस पर विचार किया

और एस० एस० एस० बोर्ड के परव्यू से ये पोस्ट्स निकाल ली। कैबिनेट ने फैसला किया कि डिपार्टमेंट के थ्रू इनको डायरेक्ट भरा जाए। इन पोस्ट्स के लिए ऐडवरटाइजमेंट की गई। एस० एस० मास्टर्ज ओर जे० बी० टी० टीचर्ज के लिए ऐडवरटाइजमेंट की गई। जे० बी० टी० टीचर्ज के इन्टरव्यू हो चुके हैं और लैक्चरार के इन्टरव्यू चल रहे हैं और उनको भी जल्दी ही भर लिया जाएगा।

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, जो स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखी गई है उससे पता चलता है कि लैक्चराइज की पोस्ट्स 1988 में 118 थी, 1989 में 221 थी और 1990 में 596 हो गई। इसका मतलब यह है कि हर साल वैकेंसीज बढ़ती ही गई है। इसी तरह से कालेजिज में 1988 में 241 थी, 1989 में 92 थी और 1990 में 117 थी। मंत्री महोदय ने बताया है कि जे० बी० टी० टीचर्ज और एस एस मास्टर्ज की वैकेंसीज को बोर्ड के परव्यू से निकाल दिया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कहीं बोर्ड के परव्यू से निकालने का कारण यह तो नहीं कि बोर्ड में और सरकार में कोई मतभेद पैदा हो गया हो और इसलिए ये रिक्तियां बोर्ड नहीं भर पाया?

Mr. Speaker: Comrade Sahib, you put a specific supplementary, otherwise I will call the other man.

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मेरी सप्लीमेंटरी यह है कि कुछ कालेजिज तो ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल ही नहीं है।

मेरा अपना कालेज है वहां पर मैं पिछले दो तीन साल से देख रहा हूं कि कोई प्रिंसिपल नहीं है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है?

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि सरकार में और बोर्ड में कोई मतभेद नहीं था। एस० एस० एस० बोर्ड द्वारा सारी वेकेन्सीज मैरिट पर भरी जाती है लेकिन एस० एस० एस० बोर्ड के पास दूसरे डिपार्टमेंट की वेकेन्सीज भरने का काम बहुत ज्यादा है इसलिए उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई। एस० एस० एस० बोर्ड के पास ज्यादा लोड होने के कारण समय लग जाता है। अब एस० एस० एस० बोर्ड के परव्यू से ये वेकेन्सीज निकाल ली है। कालेजिज में 1990 में 117 वेकेन्सीज थी और ये अधिकतर रिजर्वड कैटेगरी की है और सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं।

श्री रण सिंह मान: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि शिक्षकों के जो विभिन्न पद खाली पड़े हैं, उनको भरने का सरकार का क्या क्राइटेरिया है? उनको भरने के लिए मैरिट के कितने और इंटरव्यू के कितने नम्बर रखे जाते हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह गोपनीय होता है लेकिन फिर भी सदस्य महोदय की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। कुल नम्बर 100 जिसमें से 15 नम्बर इंटरव्यू के और 50 नम्बर

ऐजूके 1न क्वाल्लफिके 1न के होते है। इनमें लैक्चरर्ज जो कि फर्स्ट डिवीजन हो, उसको पूरे के पूरे 50 नम्बर। सैकिण्ड डिवीजन वाले को 45 और बी0 एड0 फर्स्ट डिवीजन हो, उसको पांच, बी0 एड0 सैकिण्ड वाले को 3, थर्ड डिवीजन वाले को 2। हायर ऐजूके 1न के लिए 5ए एम0 फिल0, पी0 एच0 डी0 के लिए 5, और सैकिण्ड के लिए 3, स्पोर्टस के 10 और दो साल से उपर के टीचिंग ऐक्सपीरिऐन्स के लिए 10 व कल्चरल ऐक्टिवीटीज के लिए 5। ये टोटल नम्बर बनते है 100।

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, इस समय 1196 पद स्कूलो में व 450 नइ रिक्त पडे है कालेजिज में। एक तरफ तो पढे-लिखे नौजवान बेरोजगार है और दूसरी तरफ स्कूलो व कालेजो मे टीचर्ज न होने की वजह से बच्चो की पढाई का नुक्सान हो रहा है। मै मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो टीचर्ज रिटायर्ड है और जिनका रिकार्ड वगैरह भी ठीक है, एम0 फिल0 भी है, क्या उनको एक एक साल के लिए सरकार खाली पडे पदो के विरुद्ध लगाने का विचार रखती है ताकि बच्चो की पढाई का नुक्सान न हो?

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्लास थ्री 54000 एम्पलाईज को सरकार ने अभी रैगुलर किया है। उनमें से 10 हजार के करीब टीचर्ज, मास्टर्ज व लैक्चरर्ज है। आज की तारीख में जितनी वेकेन्सीज पडी है उनके लिए हम इंटरव्यू ले रहे है और उन पदो को भीघ्र ही भर दिया जाएगा।

श्री भगवान सहाय रावत: अध्यक्ष महोदय, एक तो एस0 एस0 एस0 बोर्ड से सिलैव इन पेंडिंग पडी है और दूसरी और नौजवानो में बेरोजगारी है। क्या सरकार ने इस मामले में कोई परमानेंट पालिसी बनाई है ताकि रिक्तियों को भरा जा सके। क्या मंत्री महोदय यह बतलाने का प्रयत्न करेगे कि आज की तारीख में कितनी रिक्तियां है और उन रिक्तियों को कब तक भर दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: इस बारे में पहले ही बताया जा चुका है।

श्रीमती कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, यहां पर कालेजिज व स्कूलो की रिक्तियों के बारे में बताया गया कि इतनी इतनी रिक्तियां स्कूलो और कालेजो में पडी है जिनको इंटरव्यू लेकर जल्दी ही भर दिया जाएगा। मैं इनसे यह जानना चाहती हूं कि जो गवर्नमेंट ऐडिड स्कूलज है उन में जो स्वीकृत पोस्टे थी, वे आज तक क्यों भरी नहीं गई है? इस के क्या कारण है? फिगरज इनके पास होंगी। क्या ये यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन दो वर्शों में गवर्नमेंट ऐडिड स्कूलो में कितनी रिक्त पडी पोस्टे स्वीकृत की गई है?

श्री सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसके लिए यदि ये सैपरेट नोटिस दे तो हम बता देंगे।

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो 7000 के करीब टीचर्ज की पोस्टें स्कूलो व कालेजो में रिक्त पडी

है और दूसरी और बेरोजगारी भी है। तीसरे, छात्र पिछले तीन महीनों से रिजर्वे इन वाले भागे भाराबे के कारण पढाई से बिल्कुल अनटच रहे है और उनकी पढाई का काफी नुक्सान हुआ है। तो मै सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे विधार्थियों को किसी तरह से कम्पनसेट करने का विचार रखती है?

Mr. Speaker: This is no supplementary, Please take your seat.

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताएंगे कि कालेजो के अन्दर जो अध्यापक 15-15 साल से ऐडहॉक पर लगे हुए है उनको पक्का करने पर विचार किया जाएगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, ऐसे केसिज पर विचार कर रहे है।

Mini Secretariat at Rohtak

***1350. Dr. Raghuvir Singh:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Mini Secretariat at Rohtak; and

(b) if so, whether the land for the purpose has been acquired so far?

राजस्व मंत्री (श्री सचदेव त्यागी):

(क) जी हां।

(ख) कोई प्राइवेट भूमि अभिग्रहित नहीं की गई है। यह 15.26 एकड़ सरकारी भूमि पर बनाया जा रहा है।

डा० रघुवीर सिंह: स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताएंगे कि ये मिनि सैक्रेटरिएटस बनाने की प्रपोजल जिन उद्दे यो से भारु की गई थी क्या ये उनको पूरा करते है? रोहतक के मिनि सैक्रेटरिएट की ऐस्टीमेटिड कास्ट कितनी है?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, जनता की सुविधा के लिए, राज्य सरकार प्रत्येक जिला मुख्यालयो पर सभी सरकारी कार्यालयो को एकत्रित करने के लिए संयुक्त कार्यालय भवन बना रही है। इन भवनो को लघु सचिवालय कहा जाता है। इन भवनो का निर्माण कार्य फेजिज में किया जाता है। इनको पांच ब्लाको में बनाया जाता है। ब्लाक-1 में कार्यकारी न्यायालय तथा कार्यालय तथा उपायुक्त का मुख्य कार्यालय ब्लाक होता है। ब्लाक-2 में प्रशासकीय ब्लाक होता है। ब्लाक-3 में अन्य जिला कार्यालयो को स्थान उपलब्ध करवाने के लिए पांच मंजिला भवन होता है। ब्लाक-4 न्यायायिक ब्लाक होता है तथा ब्लाक-5 लिटीगेंट्स ब्लाक होता है। इसके अलावा ब्लाक 2,4 व 5 का निर्माण कार्य फेज-1 के अन्तर्गत किया जाता है। ब्लाक नम्बर 1 और 3 दूसरे फेज में कवर होते है। रोहतक के मिनि सचिवालय में फेज 1 के

प्र शासकीय ब्लॉक के एक भाग का निर्माण हो चुका है। रोहतक में लघु सचिवालय 15.26 एकड़ सरकारी भूमि पर बनाने का निर्णय जून, 1984 में लिया गया था। इसके फेज-1 के प्र शासकीय ब्लॉक का निर्माण करने बारे 4671700 रुपए की प्र शासकीय स्वीकृति दिनांक 9 अगस्त, 1984 को जारी की गई थी। दिनांक 26 मई, 1989 को दुबारा फिर 2589000 रुपए की प्र शासकीय स्वीकृति लघु सचिवालय, रोहतक का विस्तार करने के लिए जारी की गई। स्पीकर साहब, 1991-92 में न कामों के लिए दो सौ लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं जिसमें से 6 लाख रुपए रोहतक के लिए हैं।

चौधरी सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताएंगे कि पानीपत जिले के अन्दर मिनि सैक्रेटेरिएट पर कब काम शुरू होगा और वह कब तक बन जाएगा?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, पानीपत में 66 एकड़ जमीन कैम्पिंग ग्राउंड की है, उसका डिस्प्यूट है। केन्द्रीय सरकार तो कहती है कि वह जमीन उसकी है और हरियाणा सरकार कहती है कि यह जमीन हमारी है। इसका फैसला होते ही वहां पर काम शुरू करवा देंगे।

डा० रघुवीर सिंह: स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। मैंने पूछा था कि रोहतक का मिनि सैक्रेटेरिएट उन रिक्वायरमेंट्स या कंडी शर्तों को पूरा करता है जिन आबजैक्ट्स को लेकर यह योजना शुरू की गई थी?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, हमने 16 के 16 जिलो में मिनि सैक्रेटेरिएट बनाने का निर्णय लिया हुआ है। ये रिक्वायरमेंट को देख कर ही बना रहे है?

श्री राम विलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताएँ कि सब डिवीजन लेवल पर भी ऐसे मिनि सचिवालय बनाए जाएंगे, अगर हा, तो क्या महेन्द्रगढ में भी बनाया जाएगा?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, पहले डिस्ट्रिक्ट लैवल पर बनेगे उसके बाद इस पर विचार करेंगे।

श्री िव प्रसाद: स्पीकर साहब, अम्बाला के लघु सचिवालय का केवल एक ही ब्लोक बना है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का उस लघु सचिवालय का दूसरा ब्लोक बनाने का विचार है?

श्री सचदेव त्यागी: स्पीकर साहब, अम्बाला के लघु सचिवालय के फेज-1 के प्र तासकीय ब्लोक का निर्माण कार्य हो चुका है और बाकी का काम इन प्राग्रैस है। इस साल वहां पर 6.60 लाख रुपए खर्च किए गए है। उन मिनि सैक्रेटेरिएट का वर्क इन प्रोग्रैस है।

श्री सीता राम सिंगला: स्पीकर साहब, गुडगांव के अंदर हाई सैकेण्डी स्कूल, आई टी आई की बिल्डिंग और सरकारी कार्यालय पंचायत भवन मंचल रहे है जिससे जनता को बहुत परे ानी हो रही है।

Mr. Speaker: Mr. Singla, this question relates to Rohtak. Therefore, you can put supplementary regarding Rohtak only.

सेठ लछमन दास बजाज: स्पीकर साहब, मै आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या करनाल में मिनि सैक्रेटैरिएट बनाया जाएगा, अगर बनाया जाएगा तो उसका काम कब तक भुरु हो जाएगा?

Mr. Speaker: Mr. Bajaj, as I have said earlier, this question relates to Rohtak and I will allow supplementaries relating to Rohtak only. Please take your seat.

श्री मुनी लाल: स्पीकर साहब, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रेवाडी नया जिला बना है वहां पर लघू सचिवालय कब बनना भुरु होगा?

Mr. Speaker: Mr. Muni Lal, I would not permit to put supplementary on this question like this. Please take your seat. Next question.

50 Bed Hospital at Dabwali Mandi

***1359. Shri Mani Ram:** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a 50 bed Hospital at Dabwali Mandi?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री औम प्रकाश भारद्वाज): जी नहीं।

श्री मनी राम: स्पीकर साहब, भारद्वाज जी के महकमे से संबंधित चाहे कोई भी सवाल हो इनकी तरफ से यही जवाब होता है कि 'जी नहीं' या 'सवाल ही पैदा नहीं होता'। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मंडी डबवाली में 50 बैड का अस्पताल बनाने में क्या दिक्कत है? जी नहीं कहने से तो काम नहीं चलेगा।

श्री औम प्रकाश भारद्वाज: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने उनके साल का जवाब जी नहीं में दिया है लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मंडी डबवाली में पहले से ही एक 30 बैड का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चल रहा है। यह बात ठीक है कि हम वहां पर 50-60 लाख रुपया खर्च करके सी0 एच0 सी0 को बिल्डिंग जरूर बनाएंगे लेकिन 50 बैड का हास्पिटल बनाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री मनी राम: स्पीकर साहब, डबवाली की 50 हजार की आबादी है और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसकी बिल्डिंग की खस्ता हालत है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मंडी डबवाली की आबादी को देखते हुए वहां पर 50 बैड का होस्पिटल कब बन जाएगा, क्या उसके लिए जमीन की कोई दिक्कत है या कोई और दिक्कत है?

श्री औम प्रका । भारद्वाज: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य मनी राम जी का यह कहना ठीक है कि जिस बिल्डिंग में सी० एच० सी० काम कर रहा है वह काफी पुरानी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की खस्ता हालत है। हमने वहां पर सी० एच० सी० बनाने के लिए हुड्डा से जमीन लेनी है और हुड्डा ने हमारे विभाग को दो एकड जमीन अलॉट भी कर दी है जिसकी कीमत 15911 रुपए 40 पैसे है। हुड्डा जब भी उस जमीन का पोजै इन हमारे विभाग को दे देगा उसके बाद फौरन उसके लिए एस्टिमेटस बना कर बिल्डिंग बनाने का काम चालू कर दिया जाएगा।

श्री मनी राम: स्पीकर साहब, भारद्वाज साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: भारद्वाज साहब, आप मनी राम जी की सप्लीमेंटरी नहीं समझ पा रहे हैं। जिस समय हमारे विभाग को उस जमीन का पोजै इन मिल जाएगा तो हम फौरन उस बिल्डिंग का एस्टिमेट बना कर काम शुरू कर देंगे। इस बारे में मनी राम जी भी अपनी तरफ से एफर्ट्स करे ताकि उस जमीन का पोजै इन जल्दी मिल जाए।

श्री मनीराम: स्पीकर साहब, हुड्डा की जो जमीन है वह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर होनी है। उसमें दिक्कत क्या है?

श्री औम प्रकाश भारद्वाज: स्पीकर साहब, हम उस सी0 एच0 सी0 की बिल्डिंग बनाने का काम जल्दी शुरू करने की कोशिश करेंगे।

डा0 हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस साल हरियाणा प्रान्त में कितने हास्पिटल बनने जा रहे हैं?

श्री औम प्रकाश भारद्वाज: स्पीकर साहब, मैं अपने साथी को बताना चाहूँगा कि इस समय 11 हस्पतालो पर काम चल रहा है।

श्री बलबीर सिंह चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि सी0 एच0 सी0 बनाने के लिए क्या नार्म्ज है और उसके लिए कितना एरिया होना चाहिए? क्या इन्होंने सारे हरियाणा में उचित जगहो पर सी0 एच0 सी0 बनाने के लिए सर्वे करवा लिया है? इसके साथ साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि हिसार जिले में कितनी जगहो पर सी0 एच0 सी0 चल रही है?

श्री औम प्रकाश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा में 41 सी0 एच0 सी0 चल रही है ओर इसमें से 5 हिसार में है।

श्री उदय भान: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि मण्डी डबवाली में हस्पताल बनाये जाने के लिए हुड्डा को जमीन की पेमेंट करनी है और उसके बाद वह जमीन हैल्थ विभाग

को ट्रांसफर हो जाएगी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि वह जमीन लेने के लिए हुड्डा को कब तक पेमेंट कर देंगे?

श्री औम प्रकाश भारद्वाज: यह पेमेंट जल्दी ही कर दी जाएगी।

श्री मोहम्मद असलम खां: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि इस समय 11 स्थानों पर हस्पताल बनाये जा रहे हैं। क्या मंत्री महोदय इन 11 हस्पतालों के नाम बताने का कष्ट करेंगे।

श्री औम प्रकाश भारद्वाज: स्पीकर साहब, जहाँ जहाँ पर ये बनाये जा रहे हैं उनके नाम मैं आपके बता देता हूँ। ये हैं—

1. General Hospital, Karnal.
2. B.K. Hospital, Faridabad.
3. T.B. Isolated Ward, Sirsa.
4. Repair of Krishna Lal Eye Hospital, Bhiwani
5. General Hospital, Ambala City.
6. General Hospital, Adampur Extension.
7. T.B. Isolated Ward, Ambala City.
8. General Hospital, Sonapat.
9. Lok Nayak Jai Parkash Hospital, Kurukshetra.
10. General Hospital Charkhi Dadri.

AIDS

*1363. Dr. Brij Mohan Gupta: Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether it is a fact that cases of Aids disease have been detected in the State of Haryana; and

(b) if so, total number of such cases detected so far and the preventive action taken by the Government to control the disease?

Health Minister (Shri Om Parkash Bhardwaj):

(a) Yes.

(b) Three cases of AIDS were detected. One case detected in Panchkula who is under regular treatment in P.G.I. Chandigarh. Two foreign students had developed AIDS during the year 1988. One was deported to his native village and the other committed suicide in Karnal Jail. In order to control menace of the dreaded disease, the following measures have been taken:-

(i) All the Civil surgeons and incharge of blood banks have been instructed to collect blood samples of all donors and send these to screening centre at Medical College, Rohtak, for testing against AIDS.

(ii) Testing of blood for high risk groups which include:-

1. Professional Blood Donors.
2. Prostitutes, Homosexuals and drugs addicts.

3. Foreign Studetns.

4. Sexually transmitted disease cases.

(iii) Instructions are to use single autoclaved/disposable needles and syringes.

(iv) There is a separate monitoring cell at Health Directorate.

(v) Doctors are imparted training at P.G.I. Chandigarh.

(vi) Health Education related to AIDS is imparted and World Day was celebrated on 1-12-1990 and an advertisement given in the press to create awareness in the people.

(vii) There is a proposal to establish two more screening centres at Karnal and Hissar with Central assistance.

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, हैल्थ मिनिस्टर महोदय ने अभी बताया है कि इस रोग के िाकार 2 विदे ि छात्र थे तथा एक केस पंचकूला में डिटेक्ट हुआ है। मैं आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पंचकूला मे हमारे कान्ति प्रका ि भल्ला जी को इस बीमारी से बचाने के लिए क्या सुरक्षा प्रबन्ध किये गये है? (हंसी)

स्थानीय भासन राज्य मंत्री (श्री कान्ति प्रका ि भल्ला):
स्पीकर साहब, मैं आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री बनारसी दास गुप्ता

को बताना चाहूंगा कि घूमने फिरने के दौरान हो सकता है कि उन्हें भी ऐड्ज हो गई हो इसलिए उनकी भी जांच करवा ली जाएगी। (हंसी)

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, करनाल से एक अखबार में खबर छपी है कि हरियाणा के एक मंत्री 'ऐड्ज' से ग्रस्त है। मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे उस मंत्री का नाम बताएंगे ताकि बाकी के हाउस को इस भयंकर रोग से बचाया जा सके? (हंसी)

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि वे मंत्री अब भूतपूर्व हो गए हैं। (हंसी)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, यह बड़ा गम्भीर सवाल है जिसके कारण बड़ा भारी आतंक फैला हुआ है। यह विदे की बيمारी है। कई मंत्री गाहे-बगाहे विदे आ जाते रहे हैं और अदनान खा गोगी से भी मिलते रहे हैं। अदनान खागो की दूसरे कई लोगो से भी मिलते रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो मंत्री या सदन के दूसरे सदस्य उनसे मिलते रहे हैं क्या उनकी जांच करवा ली गई है कि कहीं उन्हें ऐड्ज तो नहीं है? (हंसी)

श्री औम प्रकाश भारद्वाज: स्पीकर साहब, मेरे आदरणीय साथी श्री राम बिलास भार्मा जी बहुत चिंतित हैं कि ऐड्ज का निरीक्षण करवा लिया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं

इनकी जानकारी के लिए तथा सारे सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि चिन्ता की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे सभी साथी बिल्कुल ठीक हैं। (हंसी)

लोक निर्माण मंत्री (श्री जगन नाथ): स्पीकर साहब, हमारे माननीय साथी राम बिलास जी बड़े चिन्तित हैं। विदे 1 की बात नहीं, दे 1 के अन्दर भी मद्रास और बम्बई में ऐसी बीमारी फैल गई है। हमें इसकी काफी चिन्ता है। हमारे कुछ साथी जब घुमने के लिए गए हुए थे तो हमने डा० महासिंह को इसी काम के लिए भेजा था ताकि अगर कहीं कोई ऐसी बात हो जाए तो फौरन ईलाज किया जा सके। (हंसी)

डा० रघुबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस बीमारी से ग्रस्त जो व्यक्ति है उनमें से कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं और वे किस एज ग्रुप के हैं?

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित

प्र न का लिखित उत्तर

Road from Prithipur to Gadwali

***1413. Shri Bhag Mal:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state the date on which the road from Prithipur to Gadwali is district Yamuna Nagar was constructed

alongwith the number of culverts/bridges constructed thereon?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जगन नाथ): 52 पुलियो सहित इस सडक का निर्माण जुलाई 1980 मे किया गया था।

विभिन्न विशयो का उठाया जाना

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मेरा एक प्रिबिलेज मोान है। इस महान सदन को भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की सव्रेलैन्स करने वाले सी० आई० डी० कर्मचारियो की गिरफ्तारी के मामले के बारे में स्टेटमेंट देते हुए गृह मंत्री ने 7 तारीख को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने गलत ब्यानी की है। उसके सम्बन्ध में मैने रूल 262 के तहत आपकी सेवा में एक ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोान दिया है। उसके साथ ही प्रमाण के रूप में मैने कटिंग भी आपकी सेवा में पेस की है। इस महान सदन की बडी बडी परम्पराएं बनी रहे, इसके लिए मै आपसे यह जानना चाहता हूं कि उसका आपने क्या किया है?

श्री अध्यक्ष: वह सुबह ही मुझे सवा नौ बजे मिला है।

That is under consideration. I have to verify the facts from the official record of the day. I have not merely to reply on what has appeared in the press. (Noise and interruption) Mr. Sharma, as you know, whatever is stated in the newspaper may not be correct but whatever is stated in the House is correct. So I have to verify this from the record.

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैने आपकी सेवा में उसे आज सुबह पौने नौ बजे दिया है। उसके साथ मैने इस बात का प्रमाण भी दिया है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने कर्मचारियों के बारे में दी है, वह गलत दी है। स्पीकर साहब, मैने रजिस्टर और रोजनामचे के हवाले से आपसे बात कही है। स्पीकर साहब, आज यह सदन की आखरी बैठक है। (व्यवधान एवं भाोर)

Mr Speaker: Mr. Sharma, as I said earlier, this is under consideration.

डा० रघूवीर सिंह: स्पीकर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब होम डिवलैपमेंट को कन्ट्रोल करने में कुछ कठिनाई महसूस कर रहे हैं। यह बड़ा गम्भीर मामला है। (व्यवधान एवं भाोर)
Speaker Sir, if you permit me, I want to submit one thing.

Mr. Speaker: No, Doctor Sahib, not on this subject now as I have already said that this is under consideration.

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, आज सदन के आखिर तक क्या आप उस पर अपना निर्णय दे देंगे?

Mr. Speaker: Sharma Ji, cannot promise.

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, इस सदन की गरीमा की बात है जो इससे जुड़ी हुई है।

Mr. Speaker: Sharma Ji, I know that but I cannot promise.

श्री राम बिलास भार्मा: आज सदन उठने से पहले तो आप बता ही देंगे, ऐसा तो आप कह सकते हैं।

Mr. Speaker: Sharma Ji, I would not say so as I have said earlier. I cannot promise as the matter is still under consideration.

श्री राम बिलास भार्मा: मैंने उसमें बकायदा रुल कोट किया है। आप आज हाउस उठने से पहले उसको एडेमिट कर लें।

Mr. Speaker: No, it is not possible to say anything about it at this stage. मैं तो अभी हाउस में बैठा हूँ। आप लोग मुझे हाउस से उठने देंगे तभी तो मैं फैसला करूँगा। अगर आप मुझे उठने ही नहीं देंगे तो मैं कैसे फैसला करूँगा। यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप मुझे उठने भी देते हैं या नहीं उठने देते हैं।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैं इन द्वारा सदन में कह गयी बात को चैलेंज करता हूँ।

Mr. Speaker: Sharma Ji, that is right but I cannot promise anything about it. You please take your seat.

श्री कैला । चन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, रेवाडी के अन्दर सफाई कर्मचारियों की हडताल के बारेमें मेरा कालिंग अटैं ।न मो ।न था। उसका आपने क्या फैसला किया है? वहां पर 15-20 दिन से कोई सफाई नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: वह तो डिस-अलाउ हो गया है।

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, इन चुनावों में बिल्कुल सफाई कर देंगे। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री कैला 1 चन्द भार्मा: सफाई तो आपकी होने वाली है। आपका तो जनाजा भी निकलने वाला है। सर, वहां पर 28 तारीख से हडताल चल रही है और बहुत बुरा हाल है।

श्री अध्यक्ष: वह तो डिस-अलाउ हो गया है। आप बैठिये।

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि जो प्र न राम बिलास भार्मा जी ने उठाया है, उसको भाोर- 1राबे में नही दबाना चाहिए। यह एक ऐसी बात है जो बड़ी गम्भीर है। इस सदन के अन्दर गलत इन्फर्मे 1न दी जाये तो वाकई यह ब्रीच आफ प्रिवेलज का मामला बनता है। इसके लिए या तो होम मिनिस्टर साहब कोई जवाब दें अध्यक्ष महोदय, आप हमारी तसल्ली करा दें। (व्यवधान एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: मैं तसल्ली करवाने के लिए नहीं हूँ। मैंने हाउस को बताया है कि वह मामला अन्डर कंसिड्रेशन है।

श्री बनारसी दास गुप्ता: यह इस तरह से टलने वाली बात नहीं है। (व्यवधान एवं भाोर)

Mr. Speaker: Gupta Ji, I am very sorry. I have said earlier, that the matter is under consideration. Now I would not permit any-body to speak like this. (Interruption)

श्री बनारसी दास गुप्ता: इसका फैसला तो आप को देना ही चाहिए।

Mr. Speaker: I am not going to bow down before you. You please take your seat.

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, यह बात चलने वाली नहीं है। भाोर भाराबा करने से यह मामला दबाया नहीं जा सकता। इस बात का माकूल जवाब दिया जाए। हाउस को गलत इंफरमे ान दी गई है। फ़ैक्ट्स एण्ड फिगरज़ के साथ यह सूचना प्रकाशित हुई है। (व्यवधान एवं भाोर)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, हाउस में जो कुछ कहा गया है, वह सही...

Mr. Speaker: I have not yet admitted it. Please take your seat.

श्री रण सिंह मान: स्पीकर साहब, मैने आपकी सेवा में एक काल अटैन् ान मो ान जींद के ढोला गांव में जमीन के अनअथोराइज्ड पोजै ान के बारे में दी है। वहां पर हजारो लोगो ने प्रद ान किया है। (व्यवधान एवं भाोर)

* * * * *

श्री अध्यक्ष: ये भाब्द रिकार्ड न किए जाएं।

श्री रण सिंह मान: स्पीकर साहब, मेरी काल अटैन्शन मोशन का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: वह मैंने गवर्नमेंट को कमेंट्स के लिए भेजी है। I have not received the comments as yet.

श्री रणसिंह मान: स्पीकर साहब, मैंने कल एक ऐडजर्नमेंट मोशन, हिसार जिले के भट्टा मजदूरों पर भट्टे के मालिकों द्वारा कातिलाना हमला करने संबंधी, दी थी। उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: वह मैंने डिस-अलाउ कर दी है। (विघ्न)

श्री रण सिंह मान: स्पीकर साहब, यह तो बड़ा जरूरी मामला था।

Mr. Speaker: How can I allow you to discuss a murder case. It is a House and not a session court.

श्री रण सिंह मान: स्पीकर साहब, मेरी बात तो आप सुन लीजिए।

Mr. Speaker: No when a murder has been committed and a case registered, how can I allow it to be discussed here. (interruption) I would request everybody to please take his seat except the leader of the Opposition, who wants to say something.

श्री सूरज भान: स्पीकर साहब, मैने डा0 कमला वर्मा के बारे में एक प्रिविलिज मोशन दी थी। मुझे उसके बारे में बताया जाए।

श्री अध्यक्ष: सूरज भान जी, उसके बारे में गवर्नमेंट का जवाब आ गया है। मैने बहिन जी को चिट्ठी लिख दी है। मैने बहिन जी और आपको बुलाया है and we will discuss the matter.

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी बात यह है कि प्रोसीजर के मुताबिक आदरणीय गृह मंत्री 7 तारीख को दी गई अपनी स्टेटमेंट करैक्ट करना चाहे तो कर सकते है। अगर वे नहीं करना चाहते तो आप इसका फैसला कर दें। (गोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जो कुछ मैने कहा है वह सौ परसेन्ट सही है। (थम्पिंग)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, आप हमारे संरक्षक है। आप कृप्या हमें सही जवाब दिलाएं। मेजे थपथपाने से काम नहीं चलेगा। ये सही जवाब दे या तो कहे कि जो अखबार में छपा है वह गलत है। (गोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह: यह गलत है (विघ्न)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, हम आप पर छोड देते है। आप इसका फैसला कर दें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह बात तो खत्म हो चुकी है। आपने उसको फिर भुरु कर दिया। (गोर एवं व्यवधान) इस समय सात अपोजी इन के मैम्बर खडे है। ऐसी हालत में हाउस कैसे चल सकता है?

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, सदन मे यदि गलत रिपोर्ट दी जाए, गलत इंफरमे इन दी जाए तो यह ब्रीफ आफ प्रिविलिज बनती है। (गोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप हमारे संरक्षक है। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा? हमारे अधिकारो की रक्षा कौन करेगा? (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Gupta Ji, I have already said that it is under consideration. So please take your seat.

(इस समय जनता दल के बहुत से मैम्बर्ज बोलने के लिए खडे हो गये।)

श्री अध्यक्ष: गुप्ता साहब, आप अपने मैम्बर्ज को तो देखें, वे किस तरह से बोल रहे है दूसरो को आप क्या कहते है? (गोर) No Interruptions please.

डा० हरनाम सिंह: स्पीकर साहब, चौधरीवास में गोली चली है। आदमी मरे है। परसों मैने मुख्य मंत्री महोदय को इस बारे में लिख कर भी दिया था ओर उन्होंने फैंक्टस जानने के लिए टैलिफोन करने के लिए कहा था। लेकिन आज हमें टैलिफोन आई

है कि वहां पर आदमी मरे है। यह बडा ही सीरियस मामला है।
(गोर एवं व्यवधान)

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यह सरकार गुण्डो को पनाह दे रही है। ऐसी लाठी गोली की सरकार नही चलेगी, नही चलेगी। इस बारे में मैं ऐडजर्नमेंट मो इन दिया था लेकिन आप हमारी बात नही सुन रहे है। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I have disallowed that.

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खडे हुए)

Mr. Speaker: Please listen everybody. I won't allow anybody to speak without my permission.

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यह बडा ही सीरियस मामला है लेकिन आप हमें इस पर बोलने नही दे रहे है। मैं प्रोटैस्ट के तौर पर हाउस से बैल मे बैठने जा रहा हूं। जब तक इस मामले पर डिस्क इन नही होती, मैं यहां से नही उठूंगा।
(गोर)

(इस समय कामरेड हरपाल सिंह अपनी सीट से उठकर सदन के बैल में बैठ गये)

श्री अध्यक्ष: हरपाल सिंह जी, आप अपनी सीट पर जाईये (गोर एवं व्यवधान)

कामरेड हरपाल सिंह: जब तक आप मेरी बात नहीं सुनते तब तक मैं यही बैठा रहूंगा। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कामरेड साहब पहले आप अपनी सीट पर जाएं।

(इस समय कामरेड हरपाल अपनी सीट पर चले गए।)

श्री दुर्गा दत्त अत्री: स्पीकर साहब, आज हरियाणा में आदमी मरवाए जा रहे हैं और लोगों को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मुझे भी जान से मारने की धमकी मिली है और आप हम सब की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Attri Ji, please take your seat. Let me reply first. मैं कहता हूँ कि एक कत्ल हुआ होगा या दो कत्ल हुए होंगे but when the case has been registered, the trial will be in the Sessions Court and not in the Vidhan Sabha. I won't permit this procedure. This is wrong procedure being followed. जब एक मर्डर हो गया और पर्चा भी दर्ज हो गया, Then it is for the court to decide the matter (Noise).

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, यदि सदन के किसी साथी के साथ कोई ज्यादाती हो जाए तो उसके बारे में हम यहां कह सकते हैं। अत्री जी को एस0 पी0 ने धमकी दी है, उनकी जान को खतरा है। इस बारे में एक प्रिविलेज मोशन दिया गया है। कामरेड हरपाल सिंह जी ने भी एक विरोध घटना के बारे में

एक ऐडजर्नमेंट मोान दिया है। लेकिन इतना होते हुए भी आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। (गोर)

श्री अध्यक्ष: दुर्गा दत्त अत्री जी के साथ कल बात हो गई है और हरपाल सिंह जी का जो मोान था, वह मैंने डिस-अलाउ कर दिया है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बहज कमला जी के साथ भी हुआ था। उनको पकड कर ले गये और दूर सुनसान जगह पर जाकर उनको राम के डेढ बजे छोडा गया। इस तरह से मामलो में आनरेबल मैम्बर्ज की ओर से आपको प्रिविलेज मोान दिया गया हो, एक मंत्री इस सदन में गलत बात बोले कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है और आप हमें यहां पर बोलने का अवसर न दे तो फिर हाउस के सदस्य उत्तेजित न होंगे तो और क्या करेंगे? (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Sharma Ji, this is not the way. When you do not respect the Chair, what can the Chair do?

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, कम से कम कामरेड साहब व अत्री जी को अपनी बात कहने का यहां हाउस में अवसर तो मिलना ही चाहिए (गोर)

Mr. Speaker: I do not agree.

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, आज यह कोई इू नहीं है, ये जानबूझ कर तमाा कर रहे हैं। (गोर) इन लोगो ने

मजदूरो को मरवाया है। इन्होंने चार लाख रुपया इकट्ठा किया है। (गोर)

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गए)

Mr. Speaker: Hon Members, please take your seat. I will try to clinch the issue. वैसे तो यह मोशन डिस्-अलाउ हो चुका है लेकिन फिर भी आनरेबल होम मिनिस्टरी यदि इस बारे में कुछ बताते हैं, कोई ब्यान देना चाहे तो दे सकते हैं।

गृह मंत्री(प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर साहब जिस केस का हरपाल सिंह जी ने जिक्र किया उसके बारे में निवेदन है.....

श्री किरपा राम पुनिया: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आपने इस इशू को बड़े अच्छे ढंग से क्लिच किया और होम मिनिस्टर साहब को स्टेटमेंट देने के लिए कहा। लेकिन पहले श्री हरपाल सिंह जी की बात सुन लें। (गोर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, रण सिंह जी मान ने इसी इशू पर कालिंग अटेंशन मोशन को नोटिस दिया था। अगर उसका जवाब दे दिया जाता तो ये आदमी न मरते।

श्री अध्यक्ष: वह तो डिस्-अलाउ हो चुका है लेकिन मैंने फिर भी कहा है कि अगर होम मिनिस्टर स्टेटमेंट देना चाहे तो दें।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, इन लोगो को सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। कल एक मजदूर मारा गया था और बकायदा स्पीकर साहब, एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई। उसमें चार आदमियों के नाम लिए गए। हमने दो आदमी तो फौरन अरैस्ट कर लिए और दो जो और थे उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। ये कहते हैं कि मजदूर मारा गया, हमें भी पता है। ये लोगो को ि ि करते हैं 31 मार्च तक अपने सैंट्रल दफ्तर में सूचना भेजने की कि कहां कहां पर कितने लोग मरवाए। (विघ्न) हिसार के अन्दर इन लोगो ने मजदूरों से चार लाख रुपया इकट्ठा किया है। चार लाख रुपया इकट्ठा करके इन्होंने उनको भडका कर भट्ठे बन्द करवाने की को ि ि की। (विघ्न) लेकिन स्पीकर साहब, सरकार किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देगी। चाहे वह भट्ठा का मालिक हो और चाहे भडकाने वाले कामरेड हो। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। (गोर)

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, ये हाउस को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैं एज ए प्रोटैस्ट तब तक हाउस की बैल मे बैठूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनते।

(इस समय कामरेड हरपाल सिंह जी सदन की बैल में बैठ गए)

Mr. Speaker: Harpal Singh, I warn you to go to your seat. (Noise and interruption)

कामरेड हरपाल सिंह: मैं नहीं जाऊंगा।

Mr. Speaker: Alright then the procedure we have to be followed.

(इस समय कामरेड हरपाल सिंह जी अपनी सीट पर चले गए)

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, हमारी सभी की जिंदगी को खतरा है। (गोर) आपने मेरी ऐडजर्नमेंट को इन रिजैक्ट कर दी और गृह मंत्री को बिना मेरे वॉर्न सुने जवाब देने की इजाजत दे दी। आप मेरा वॉर्न भी तो सुने। (गोर)

(इस समय श्री सूरज भान और बहुत से सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

Mr. Speaker: I would request all the Members to take their seats. Let me hear the Leader of the Opposition.

श्री सूरज भान: अध्यक्ष महोदय, हाउस में यह गर्म माहौल न रहे इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कामरेड साहब का ऐडजर्नमेंट को इन तो रिजैक्ट कर दिया लेकिन अब कम से कम उनकी ग्रिवेंसिज तो सुन लें। उनको अपनी बात तो कहने दें। आपने होम मिनिस्टर साहब को जवाब देने के लिए इजाजत दे दी जबकि आपने कामरेड साहब का ऐडजर्नमेंट को इन रिजैक्ट कर दिया था। गृह मंत्री का जवाब तो हमने सुन लिया है लेकिन इनका वॉर्न क्या है वह भी रिकार्ड पर आना चाहिए। इसलिए आप इनको अपनी बात कहने का मौका दें।

Mr. Speaker: I am sorry. No rule permits such discussion when I have disallowed the adjournment motion. I askes the Government to make the statement, if it wanted to because it was being insisted by members from your side.

वाक आउटस

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी संजीदगी के साथ सदन को चलाया है और आज सदन का आखिरी दिन है। आप माननीय सदस्य कामरेड हरपाल सिंह जी का वॉर्नि सुन ले इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। एक तरफ तो आपने गृह मंत्री जी को जवाब देने के लिए कह दिया और दूसरी तरफ आपने माननीय सदस्य कामरेड हरपाल सिंह जी का ऐडजर्नमेंट मोशन रिजेक्ट कर दिया। उनकी आप ग्रिवेंसिज नहीं सुन रहे हैं। आप उनका वर्जन सुन लें। यह उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। आप उनको भी अपना वॉर्नि कहने के लिए अलाऊ कर दें। (गोर)

Mr. Speaker: I am sorry, I would not permit. I have disallowed this notice. I askes the Government to clarify the matter and the Government has done it. Now you again want to raise it. but I am sorry, I would not permit it. Please take your seat and let the House proceed further.

कामरेड हरपाल सिंह: स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष: आप कृप्या बैठिए।

कामरेड हरपाल सिंह: फिर हम प्रोटैस्ट के तौर पर वाक आउट करते हैं।

(इस समय कामरेड हरपाल सिंह सदस्य सी० पी० एम०, डा० हरनाम सिंह, सदस्य सी० पी० आई० तथा सदन में उपस्थित जनता दल के सभी सदस्य सदन से वाब आउट कर गए)

श्री राब बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा बडा विनर्म निवेदन है। आपने इस सदन को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट किया है। इस सरकार की जैसी परफौरमेंस रही है वह आपके सामने रही है, उसमें हमें क्या लेना देना है। इस समय सदन में जो बदमजगी हुई है यह नहीं होनी चाहिए थी। हमने आपकी सेवा में एक प्रिविलेज मो एन बडे स्पैसिफिक इ पू पर दिया था पर वह आपने रिजैक्ट कर दिया। (गोर) अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री इस सदन को लगातार गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने गलत ब्यानी की है। (गोर)

Mr. Speaker: Ram Bilas Ji, please take your seat. I would not permit it now.

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। विपक्ष के नेता पर हमला हुआ उसका कोई जाब नहीं दे सके। मैंने और श्री सूरज भान ने आपको सूरज भान जी पर जो हमला हुआ उसके बारे में एक प्रिविलेज मो एन दी थी, वह आपने रिजैक्ट कर दी। आप उसको एडमिट करते और इनकी तरफ से उसका जवाब आता।

लेकिन एक ही आदमी बार बार इस सदन को गुमराह कर रहा है, पूरे हरियाणा की जनता को गुमराह कर रहा है। (गोर)

गृह मंत्री(प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, इनको कांटा चुभ रहा है इसका इनको दर्द तो होता ही रहेगा। उसका कोई इलाज नहीं है। (गोर) हमने इनकी सब बातों का जवाब ठीक ढंग से दिया है।

मुख्य मंत्री (श्री हुकम सिंह): स्पीकर साहब, मेरे विपक्ष के भाईयो ने हाउस का चलने नहीं देना है क्योंकि ये सुबह यह मन बना कर आए थे कि हाउस को नहीं चलने देना। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हास को आगे चलाएं।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, हमने हाउस को ठीक तरह से चलाने के लिए लगातार कोर्नर की है। हमने अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन किया है। (गोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, जो प्रिविलेज मोशन हमने दी है उसको आप ऐडमिट किजिए। (गोर एवं व्यवधान) हम आपसे गुजारि कर रहे हैं कि आप हमारी बात को सुनिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हम तो पंडितों की बात को सुनते हैं। (हंसी) आप तो महा पंडित हैं। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा तो और किस की सुनूंगा? (गोर)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, अच्छी बात है कि आप पंडितों की बात को सुनते हैं। लेकिन यह सरकार तो पंडितों

की बात नहीं सुन रही। हमारे एक पंडित भाई को भी इनकी सरकार से जान का खतरा है। (गोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, जो पंडितों की बात को सुनेगा वह मार भी नहीं खाएगा लेकिन यह सरकार पंडितों की बात नहीं सुन रही। (विघ्न) स्पीकर साहब, जो बात हम कह रहे हैं वह इस सदन के साथियों से जुड़ी हुई है और यह सदन की गरिमा का भी सवाल है। (गोर)

Mr. Speaker: Pandit Ji, please take your seat and let me proceed with the business of the day.

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, आप अगर हमारी बात नहीं सुनना चाहते ओर जो प्रिविलेज मो एन मैने होम मिनिस्टर के खिलाफ दी है उसे ऐडमिट नहीं करते तो हम वाक-आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य श्री रतन लाल कटारिया को छोड़कर सदन से वाक आउट कर गए)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

गायो को वध के लिए उत्तर प्रदेश में ले जाने संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion No. 35 from Shri Rattan Lal Kataria, M.L.A. regarding taking of cows in Uttar Pradesh for slaughtering through the banks of Yamuna River adjacent to the Haryana state. I admit it. अब श्री रतन लाल कटारिया अपना

नोटिस पढ दे और उसके बाद कंसन्ड मिनिस्टर यदि स्टेटमेंट देना चाहे तो दे दें।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि दे 1 में गरु वा पर कानूनी तौर से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। फिर भी असामाजिक प्रवृत्ति के कुछ लोग हरियाणा राज्य के साथ लगते यमुना नदि के तटों से उत्तर प्रदेश में गरुओं को वध के लिए ले जाते हैं जिसके कारण हरियाणा के इन गावों के लोगों में बड़ा रोश व्याप्त है जो ऐसी वारदातों को देखते हैं। अतः मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार सदन में एक वक्तव्य दे कर इस दि 11 में की गई कार्यवाही से इस महान सदन को अवगत कराए।

वक्तव्य—

प 10 पालन राज्य मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

प 10पालन राज्य मंत्री(श्री कुलबीर सिंह मलिक): गजट अधिसूचना 1972 के द्वारा, हरियाणा राज्य में लागू पंजाब गोवध नियन्त्रण अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत हरियाणा राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर किसी गाय को वध या वध हेतु निर्यात नहीं कर सकता। इस अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने हेतु हरियाणा सरकार ने अप्रैल, 1979 में इससे संबंधित हिदायतें जारी की हैं। हरियाणा से दूसरे राज्यों को

गायो का निर्यात तुरन्त बन्द होना चाहिए। बाद में, राज्य सरकार ने, भारत के राष्ट्रपति की ओर से हिदायतें प्राप्त होने पर 26 नवम्बर, 1979 को एक अध्यादेश जारी किया जिसे "पंजाब गोवध नियंत्रण अधिनियम 1955" में संशोधन करते हुए अप्रैल, 1980 में अधिनियम में बदल दिया गया। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अपने एजेंट के द्वारा, या नौकर या उसके निहित कोई अन्य व्यक्ति इस अधिनियम की अवहेलना में यह यह जानते हुए कि इनका वध होगी या वध होने की सम्भावना हो, गायों के वध के उद्देश्य से निर्यात नहीं करेगा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि गायों को निर्यात करने का इच्छुक व्यक्ति गायों की संख्या तथा राज्य का नाम जिसमें निर्यात किये जाने हैं, कारणों का उल्लेख करे हुए परमिट के लिए ऐसे अधिकारी को जिसे अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया गया है, आवेदन करेगा। वह व्यक्ति एक घोशणा पत्र भी प्रस्तुत करेगी कि गायों, जिनके लिए निर्यात परमिट की आवश्यकता है, को वध नहीं करेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने जिला उपनिदेशकों को गायों के निर्यात हेतु ऐसे परमिट जारी करने के लिए प्राधिकृत किया है। उपबन्ध-1 के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी, आवेदक की प्रार्थना की वास्तविकता के बारे में अपनी तसल्ली करते हुए, प्रार्थना पत्र में निर्दिष्ट गायों के निर्यात हेतु उसे परमिट जारी करेगा।

11:00 बजे

गोधन के अनप्राधिकृत निर्यात को रोकने हेतु पंजाब पुलिस विभाग ने अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं पर 15 चौक पोस्ट स्थापित की है। ऐसी छः चौक पोस्टें विशेष तौर से यमुना नदी के साथ-साथ स्थापित की गई हैं। ये चौक पोस्टें उन्हीं स्थानों पर स्थापित की गई हैं। जहां आयकर एवं कराधान विभाग के साथ-साथ पुलिस विभाग की चौक पोस्टें स्थित हैं। गोधन के अनप्राधिकृत निर्यात की बिल्कुल आज्ञा नहीं है। वर्षवार निर्यात का विवरण निम्न है:—

वर्ष 1988—89	40166
वर्ष 1989—90	52823
वर्ष 1990—91	33390

(1/9 तक)

फिर भी समय-समय पर स्थिती की समीक्षा करते हुए, राज्य सरकार ने वर्ष 1985 में करनाल में मुख्यालय स्थापित करते हुए एक उडन दस्ते की स्थापना की। यह दस्ता विभाग के एक प्रथम श्रेणी अधिकारी के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में है। उडन दस्ते द्वारा पुलिस की सहायता से बहुत सी कठिनाईयों के बावजूद काफी सराहनीय कार्य किया है। कुल मिलाकर, इसने 245 छापे मारे, 2321 पंजाब पकड़े तथा 98 प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसकी सफलता को देखते हुए सरकार द्वारा उडन दस्ते को और मजबूत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

यह यकीनी बनाने के लिए कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम को दुरुपयोग नहीं कर रहा है, राज्य सरकार ने गायो/बहडियो/बैलो, जिनकी कीमत 2000 से कम तथा बछडा जिसकी कीमत 1000 रुपये से कम है, के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। फिर भी प्रजनन साण्डो की किताबी कीमत पर निर्यात की आज्ञा है।

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत गायो के निर्यात की आज्ञा केवल उन्ही राज्यों को दी जा सकती है जो गौवध नियन्त्रण अधिनियम लागू करें।

श्री रतन सिंह कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सत्य है कि पुलिस की मिली भगत के कारण गऊओं को यमुना पार उत्तर प्रदेश में ले जाया जाता है? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या किसी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ मिलीभगत से गऊओं के भेजने के बारे में कोई केस दर्ज किया गया है?

श्री कुलबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आदरणीय साथी को बताना चाहता हूँ कि पुलिस की मिलीभगत की कोई बात नोटिस में नहीं आई है। पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा जो गाएँ पकड़ी गई हैं उनका ब्यौरा इनको दे देता हूँ। वर्ष 1985-86 में 266, वर्ष 1986-87 में 324, वर्ष 1987-88 में 611, 1988-89 में 147, 1989-90 में 106 और वर्ष 1990-91 में अब तक 96 गाएँ

यानि कुल 1560 गाएं पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा पकडी गई है। जो गाएं हमारे डिपार्टमेंट द्वारा पकडी गई है वे इससे अलग है।

घोशणा—

श्री अध्यक्ष: अब सैकेटरी साहब एक अनाऊंसमेंट करेंगे।

सचिव: मान्यवर, मैं उस विधेयक को दाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने सितम्बर सत्र, 1989 में पारित किया था तथा जिस पर राष्ट्रपति महोदय ने अनुमति दी है, सादन सदन की मेज पर रखता हूँ।

विवरण

पंजाब कृषि उपज मण्डी (हरियाणा संशोधन) विधेयक,
1989

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब मंत्री जी नियम 15 के अधीन मोशन मूव करेंगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move-

That the proceeding on the items of business fixed for today be exempted at this day sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly indefinitely.

Mr. Speaker: Motion Moved-

That the proceeding on the items of business fixed for today be exempted at this day sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly indefinitely.

Mr. Speaker: Question is-

That the proceeding on the items of business fixed for today be exempted at this day sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the assembly at its rising this day shall adjourned sine-die.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the assembly at its rising this day shall adjourned sine-die.

श्री हीरा नन्द आर्य(लोहारु): स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपने देखा है कि आज का जो एजेन्डा है, उसमें 15 तो अमैडिंग बिल है ओर आधा दर्जन के करीब रूल 84 के तहत रिपोर्ट्स पर डिस्कान होनी है।

प्र० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इस मो आन में तो इसका कोई जिक्र नहीं है। यह बात तो पहली मो आन के तहत ये कह सकते थे लेकिन उस समय तो इनको मो आन लगी हुई थी। (हसी)

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि 15 तो बिलज रखे हैं, उन पर डिस्क आन है। अगर उन पर डि आन नहीं कराना चाहते तो कह दें हम वैसे ही टाल कर देते हैं वरना इसके लिए दो दिन का सै आन बढ़ा दिया जाता तो कोई गलत बात नहीं होती।

Mr. Speaker: Please take your seat. Question is-

That the assembly at its rising this day shall adjourned sine-die.

The motion was carried.

समितियों की रिपोर्टस पे आ करना—

(i) कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की 31वीं रिपोर्ट।

श्री अध्यक्ष: अब पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी के चेयरमैन, श्री रिसाल सिंह, कमेटी की ईयर 1990-91 के लिए थर्टी-फर्स्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे।

Shri Risal Singh (Chairman Committee on Public undertakings): Sir I beg to present the Thirty First Report of the Committee on Public Under takings for the year 1990-91

on the Repors of the Comptroller & Auditor General of India for the years 1980-81, 1981-82 & 1982-83 relating to Haryana State Electricity Board.

(ii)कमेटी आन ऐस्टीमैट्स की 23वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब कमेटी आन ऐस्टीमैट्स के चेयरमैन, श्री मनी राम, कमेटी की ईयर 1990-91 के लिए 23वीं रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे ।

Shri Mani Ram (Chairman Committee on Estimates): Sir I beg to present the Twenty Third Report of the Committee on Estimates for the year 1990-91.

(iii)कमेटी आन ऐस्टीमैट्स की 22वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब कमेटी आन अ योरेंसिज के चेयरमैन, श्री मोहम्मद असलम खां, कमेटी की ईयर 1990-91 के लिए 22वीं रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे ।

Shri Mohammad Aslam Khan (Chairman Committee on Government Assurances): Sir, I beg to present the Twenty Second Report of the Committee on Government Assurances for the year 1990-91.

(iv) कमेटी आन दि वैलफेयर आफ ि डयूल्ड कास्टस एंड

ि डयूल्ड ट्राइब्ज की 16वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब कमेटी औन दी वैल्फेयर आफ रिडयूल्ड कास्ट्स एंड रिडयूल्ड ट्राईब्ज के चेयरमैन, श्री सूरज भान, कमेटी की ईयर 1990-91 के लिए 16वीं रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे।

श्री सूरज भान (सभापति अनुसूचित जातियो तथा जन जातियो के कल्याण के लिए समिति): अध्यक्ष महोदय, मै वरश 1990-91 के लिए रिडयूल्ड कास्ट्स एंड रिडयूल्ड ट्राईब्ज के कल्याण के लिए समिति की 16वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

बिलज—

(i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं0 1) बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब फाइनेंस मिनिस्टर हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं0 1) बिल, 1991 को इन्ट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसीडर करने के लिए मो ान मूव करेंगे।

Finance Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1991.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल वित्त मंत्री महोदय ने पेश किया है, मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विरोध मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी किसी का बजट का पैसा गवर्नमेंट को दिया जाता है तो आप देखेंगे कि वह सारा ही साल आखिर में खर्च किया जाता है। साल के शुरू के 10 महीने तक तो सारा बजट यूँ ही पड़ा रहता है। भासन और प्रशासन ढीला पड़ा रहता है। आखिर के दो महीनों में सारा पैसा खर्च कर दिया जाता है।

श्री तैयब हुसैन: प्वायंट आफ आर्डर, सर यह जा तो सप्लीमेंटरी के लिए एप्रोप्रिएशन बिल है। आर्य जी को भायद इस बात का पता ही नहीं है। (व्यवधान एवं भाोर).....

श्री हीरा नन्द आर्य: मुझे पता है कि आप 31 मार्च तक के खर्च के लिए बिल पेश कर रहे हैं। स्पीकर साहब, अब तक तो ये बैठे रह और अब आखिरी दिनों में इस बिल को पेश कर रहे हैं। इनको दससे पहले पेश करना चाहिए था। (गोर एवं व्यवधान)

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, पहले आर्य जी ही फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये तो खुद इसे पेश नहीं कर पाए लेकिन तैयब हुसैन जी जो अब नए फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं उन्होंने इसे पेश किया है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, कोई न कोई सिस्टम बनाया जाना चाहिए क्वार्टरली खर्च का जायजा लिया जाना चाहिए। क्वार्टरली यह देखना चाहिए कि कितना बजट अलौट किया गया और कितना खर्च हुआ। अगर वह बजट खर्च नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? किसकी जिम्मेवारी है जिसने समय पर खर्च नहीं किया। स्पीकर साहब, बहुत सी ग्रांट्स केन्द्रीय सरकार से संबंधित होती हैं। कई बार केन्द्रीय सरकार की ग्रांट समय पर नहीं आती। समय पर केन्द्रीय सरकार की ग्रांट न मिलने के दिक्कत आती हैं। उस दिक्कत को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार को एप्रोच करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने जो पैसा खर्च करना होता है उसका क्वार्टली पैसा तय करना चाहिए कि एक क्वार्टर में इतना पैसा खर्च करना है और उसको देख लिया जाए कि वाकई वह पैसा खर्च हुआ है अथवा नहीं। होता यह है कि एक दिन या दो दिन में करोड़ों रुपया खर्च कर लिया जाता है। स्पीकर साहब, इस तरस से एप्रोप्रिएशन की बजाए डिसेप्रोप्रिएशन होती है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, ये ठीक कह रहे हैं कि भारत दस दिन के दौरे पर तीन चार दिन में करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं। (हंसी)

श्री हीरा नन्द आर्य: इन भावों के साथ मैं इस बिल का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लोज बाई क्लोज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय, यह जो ऐप्रोप्रिएशन बिल है इसके बारे में मेरा निवेदन है कि जो भी रुपया खर्च किया जाता है उसका एक प्रासिजर है। उसको हिसाब से खर्च किया जाता है। वित्त के जो मामले हैं उनके पिछे एस्टेबलिशमेंट कंवैन्स है और प्रैसीडेंट्स है। विनस मंत्री महोदय ने जो ऐप्रोप्रिएशन बिल सदन में रखा है उसमें से हमारी जानकारी के मुताबिक चौदह करोड़ रुपया दडबा कलां में एक खास राजनैतिक मकसद से खर्च किया जाता है। यह पैसा खर्च कही हुआ है और दिखा कही और रहे है। इस तरह से ये पेसा मिसऐप्रोप्रिएट हुआ है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, मे आनरेबल मैम्बर से पूछना चाहता हूं कि क्या वे वाकई में कोई ख्वाब देख रहे है या सो रहे है? किस मद में पैसा खर्च कर दिया ये कुछ बताए तो सही।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, दडबां कलां वह जगह है जहां इन सब की जमानत जब्त हुई थी।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, इस सदन में सडको के बारे में एक सवाल था और उसके बाद मैंने एक सप्लीमेंटरी पूछी थी जिसके जवाब में जगन नाथ जी ने कहा था कि दडबा कलां में एक किलोमीटर सडक बनी है। यह बात इन्होंने सदन में एक सवाल के जवाब में कही थी कि वर्ष 1990-91 में वहां पर सडको के उपर दो करोड रुपया खर्च हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ये सडक तो दडबा कलां में बताने लें और दिखाते हैं कहीं और। गलत इंफरमे न देने की परम्परा बन गई है। इन लोगो के मन में सदन की गरिमा का कोई ध्यान नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐप्रोप्रिए न बिल में कम से कम आंकडो की जादूगरी तो न दिखाया करें।

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, माननीय सदस्य सवाल तो ठीक तरह से पूछ नहीं पाए। इन्होंने पूछा कि कितनी सडक पूरी हुई है तो जवाब में बताया कि एक किलोमीटर सडक पूरी हुई है। पूछना तो ये चाहिए था कि कितनी किलोमीटर सडक पर काम चल रहा है और कितना पैसा खर्च हुआ लेकिन ये वह पूछ नहीं पाए। (और एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण मंत्री महोदय ने अपने सवालो के उत्तर में कहा कि दडबा कलां में

केवल एक किलोमीटर सडक का ही काम हुआ है लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार दडबा कलां में सडको के ऊपर लगभग 14 करोड रुपया खर्च किया गया है। मिनिस्टर महोदय ने हाउस में गलत कह कर इस हाउस को मिसलिड किया है। इसलिए मैंने रूल 265 के तहत आपको लिख कर भी दिया है कि इस पैसे का बजट वगैरह में भी प्रोविजन नहीं है। इनहोने हाउस को मिसलिड करने की कोशिश की है। यह केवल भाब्दो की जगलरी सी ही मालूम पडती है। इसकी आवेक जांच होनी चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री तैयब हुसैन): स्पीकर साहब, मेरे मोहतरिम मैम्बर जो यह बात कह रहे हैं, वह सही नहीं है। उनका सवाल था कि how many roads have been constructed? जो सडके पूरी हो चुकी हैं उनके बारे में हमारे काबिल वजीर साहब ने बडी तफसील के साथ बता दिया है। जहां तक ऐप्रोप्रिएशन बिल का सवाल है, इसमें कोई भाब्दो की जगलरी वाली बात नहीं है। हमने बिल्कुल सीधे सीधे आंकडे इस हाउस के सामले स्पष्ट रूप से बतलाये हैं। इसलिए मेरा कहना है कि मेरे मोहतरिम मैम्बर कही सपने की बात तो नहीं कर रहे थे? हमने सारी बातों को स्पष्ट कहा हुआ है।

डा० हरनाम सिंह(गहबाद): अध्यक्ष महोदय, ऐप्रोप्रिएशन बिल द्वारा 12 करोड 75 लाख रुपये नैचुरल कलेमिटी रिलीफ फण्ड के लिए सरकार ने मांगे हैं। हम तो यह कहते हैं कि नैचुरल कलेमिटी के लिए और ज्यादा फण्डज का

प्रोवीजन होना चाहिए लेकिन जो पैसा सरकार इस काम के लिए दे, उस पैसे का सही और समय पर उपयोग भी होना चाहिए। उस पैसे का सही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरे हलके का एक गांव है जहां से आठ दस किसानों की जमीन फ्लड में आई हुई थी और उनका बहुत नुकसान हुआ है। सरकार के पास उनके नुकसान का सारा केस बनाकर भी भेजा गया है लेकिन उन गरीब किसानों को आज तक उनके इस नुकसान का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। जब लोग जाते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि अब पैसा नहीं है तो फिर इस रिलिफ फण्ड का मतलब ही क्या है अगर किसी को इससे फायदा नहीं होना है?

अब मैं डिमांड 9 जोकि ऐजूकेशन से संबंधित है, पर अपने विचार रखूंगा। 55 परसेंट पंजाबी लोग हरियाणा के अन्दर रहते हैं और यहां पर ये लोग पंजाबियों की बातें भी करते हैं कि हम पंजाबी समर्थक हैं लेकिन मैं आपके यह बताना चाहता हूँ कि स्कूलों के अन्दर पंजाबी के टीचर्स ही नहीं हैं। आप ही बताएं कि फिर पंजाबी बोली को किस प्रकार से प्रोत्साहन मिल सकेगा? इसलिए मेरी आपके द्वारा सरकार से विनती है कि स्कूलों में पंजाबी टीचर्स की जल्दी से जल्दी अप्वायंटमेंट की जाए ताकि हमारे पंजाबी भाईयों के बच्चों को जिनको पंजाबी पढ़ने की लालसा है, पंजाबी का ज्ञान भी दिलाया जा सके। अगर सरकार की यही नीति रही तो पंजाबी लोगों के साथ यह एक किस्म का

खिलवाड होगा। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों को 95 परसेंट एड देती है लेकिन वहां की हालत इतनी खराब है कि टीचर्स को तन्खाहे नहीं मिलती है, न ही उनका जी० पी० फण्ड ही काटा जाता है और न ही उन टीचर्स को गवर्नमेंट स्कूलों की तरह छुट्टियां ही मिलती है। मेरा सुझाव है कि सरकार यदि 5 परसेंट और इन स्कूलों को एड देकर के इनको अधिग्रहण कर ले तो बेहतर रहेगा। ऐसा करने से इन स्कूलों की हालत में काफी सुधार होगा। वहां के टीचर्स व स्टाफ को इससे लाभ होगा। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। आता है कि सरकार अब यही मेरे सुझावों पर ध्यान देगी।

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Finance Minister will move
that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir, I beg
to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिए ान (नं० २) बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब फाइनेंस मिनिस्टर हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं० २) बिल १९९१ को इन्ट्रोड्यूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे।

Finance Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1991.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य(लोहारु): अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है इसमें विशेष रूप से पुलिस के लिए अधिक धन का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, भासन और प्रशासन को ठीक चलाने के लिए पुलिस का होना आवश्यक हुआ करता है लेकिन आज प्रदेश में आप देखेंगे कि डी० आई० जी०, एस० पी० और यहां तक कि हमारे माननीय साथी गृह मंत्री महोदय के खिलाफ भी ३०२ के पर्चे दर्ज हैं। (गोर)

गृह मंत्री (प्र० सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, यह बात सच नहीं है। मेरे खिलाफ कोई पर्चा दर्ज नहीं है। (गोर)

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, चाहे मेहम की बात हो, कोसली की बात हो, यह गोहाना की बात हो। आज सारे प्रदेश में पुलिस का राजनीतिकारण और राजनीति का अपराधीकरण किया गया है। सवाल यह है कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या किया जाए? आपने देखा होगा कि हमने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था कि भट्ठे वालों ने मजदूरों को गोलियों से उड़ा दिया.....

Mr. Speaker: That case is pending in the court. The accused have been arrested. please do not refer to that, try to understand the position and do not convert the House into Sessions Court.

श्री हीरा नन्द आर्य: आपने हमारा वह प्रस्ताव सरकार को भेजा होगा। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन सावधानी बरतता तो हमारी पुलिस ठीक से काम करती और इस बात को बढ़ने न देती तो निश्चित रूप से इस प्रकार के कत्ल न होते। आज पुलिस का मिसयूज किया जा रहा है, इसको रोक कर ठीक प्रकार से काम लिया जाए। जींदमें एक डेरे के बाबे की 66 एकड़ जमीन है जिस पर सत्ता धारी लोगों ने पुलिस के संरक्षण में कब्जा कर लिया। इस बात को लेकर वहाँ के लोगों में बड़ा भारी रोश है। बादली में भी इसी प्रकार के नाजायज कब्जे हुए हैं। एक तरफ तो पुलिस का मिसयुज कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसके लिए पैसा बढ़ा रहे हैं, उसकी भर्ती के लिए पैसा बढ़ा रहे हैं। यह प्रजातंत्र में एक खतरनाक बात है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि

पुलिस के रहन सहन के लिए और खान पान के लिए ठीक इंतजाम करे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज उनसे 24 घंटे की ड्यूटी ली जाती है जबकि मीन भी 24 घंटे नहीं चल सकती। ऐसी व्यवस्था की जाए कि आठ घंटे से ज्यादा उनको थाने में न बैठना पड़े। उनका गलत इस्तेमाल न किया जाए और पुलिस का लोगो की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाए।

श्री रतन सिंह कटारिया(रादौर—अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से इस विधेयक के बारे में यह कहना चाहूंगा कि सरकार हर वर्ष कंसोलीडेटिड फण्ड से करोडो रुपया निकालती है। हमारे जैसे कार्यकर्ताओ को जनता ने चूंकि इस महान सदन में बड़े प्यार से चुन कर भेजा है इसलिए मैं अपने हलके के बारे में थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा (गोर)

Mr. Speaker: Please don't go to Ladwa and Radaur. If you go to Ladwa and Radaur, You will not be allowed to speak. (interruptions)

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, बोलूंगा तो मैं लाडवा और रादौर के बारे में ही।

Mr. Speaker: Then please take your seat.

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, आर्य जी ने बड़ी बातें उठाई है और मैं बड़ा धीरज रख रहा था। आर्य साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे रिले ांज है। इनके साथ मेरे पारिवारिक रिले ांज है। लेकिन जब एक 60 साल का आदमी धीरज नहीं रख

सकता तो 40 का भी नहीं रख सकता उसका भी सब्र टूट जाता है और मेरा वह सब्र टूट गया है। अब मैं इनकी बातों का जवाब दूंगा। एक तो इन्होंने मर्डर का जिक्र किया। वह बात सुबह आ चुकी कि बकायदा केस कोर्ट में चला गया है। बकायदा एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई है और दो आदमी अरैस्ट भी हुए हैं। मैं इस बारे में भी इनका कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन ये अपराधीकरण और राजनीतिकरण का जिक्र करते हैं। ये अपराधीकरण और राजनीतिकरण का जिक्र करके उस मर्डर का बहाना लेकर सरकार को बदनाम करते हैं। स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 15-20 दिन से इन लोगों ने उन भट्ठा मजदूरों से भी पैसा इकट्ठा किया। इन लोगों ने वहां से 6-7 लाख रुपया इकट्ठा किया। इन लोगों ने वहां मजदूरों और मालिकों का आपस में झगडा करवाया। वहां पर ओर भी दो तीन एफ0 आई आर दर्ज हुई हैं। इन लोगों ने प्रिवेंटिव मैयर्ज लेकन पुलिस पहुंचने से पहले मजदूरों और भट्ठा मालिकों से पैसा लिया ओर उन्हें आपस में लडा दिया। वहां पर गोली चली उसमें एक आदमी मरा। इस सरकार ने कोई कोताही नहीं कि बकायदा सरकार ने उसी वक्त ऐकान लिया और दो आदमियों को पकड कर अन्दर कर दिया। स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि नाजायज कब्जे हुए हैं। स्पीकर साहब, राजनीतिक प्रवृत्ति ही ऐसी रही है, आपके सामने हरियाणा प्रदेश का इतिहास रहा है। चौधरी हीरा नन्द आर्य कितनी बार एम0 एल0 ए0 बनकर आए हैं और इनसे यह भी पूछा जाए कि इन्होंने एक एक दिन में कितनी बार पल्टियो खाई हैं। इन्होंने एक

एक दिन में सैकड़ों पल्लियां खाईं होंगी। इन्होंने हरियाणा का नाम आया राम गया राम के नाम से सारे हिन्दुस्तान में दनाम कर दिया। (भोम भोम) जहां तक आर्य जी कब्जे की बात करते हैं, मैं इनको उसके बारे में भी बता देता हूँ। स्पीकर साहब, मैं आन आथ कहता हूँ और उधर से चौधरी हीरा नन्द आर्य जी आन आथ कह दे, कोई इन्कवायरी की जरूरत नहीं, कि इन्होंने भिवानी के अन्दर करोडीमल पार्क में दो मकानों पर खुद कब्जा कर रखा है। यदि इन्होंने वहां पर दो मकानों पर खुद कब्जा न कर रखा हो तो ये आन आथ कह दे मैं हाउस छोड़ दूंगा। स्पीकर साहब, ये कह दे मैं इसी वक्त हाउस छोड़ कर चला जाऊंगा। (गोर) स्पीकर साहब, नाजायज कब्जा ये लोग करते हैं और इल्जाम सरकार पर लगाते हैं। सरकार कोई कब्जा नहीं करती अगर इस सरकार को यह पता लगता है कि कहीं पर कोई नाजायज कब्जा है तो उसको उसी वक्त बकायदा हटाती है। (गोर)

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मेरे खिलाफ जो बात कही गई है वह बिल्कुल गलत बात कही गई है। उस मकान पर मेरा कब्जा किरायेदार के रूप में है। मैं बकायदा उसका किराया देता हूँ। मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वह गलत और निराधार लगाया गया है। (गोर)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इन्होंने एक कोठी नहीं बल्कि दो कोठियों पर कब्जा कर रखा है। (गोर)

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं इस बात से इंकार नहीं करता। मैं वहां पर उन दोनो मकानो मे किराएदार के रुप के रहता हू। उन मकानो का मैं किराया देता हूं। यह सरकार इस बारे में इन्कवायारी कर ले यदि कोई गलत बात हो तो मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। (गोर)

(इस समय बहुत से सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

Mr. Speaker: Everybody should take his seat and the Finance Minister may please give his reply.

वित्त मंत्री (श्री तैयब हुसैन):मोहतरिम स्पीकर साहब, इन्होने इस पर कोई नयी बात नहीं कही है। जो गलत बात कही है उनका जवाब हो मिनिस्टर साहब ने दे दिया है।ये बेकार में हाउस का समय बर्बाद कर रहे है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि हाउस के अगले बिजनैस को टेक अप किया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into considerationat once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is-

That schedule be the schedule of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा एंड पंजाब ऐग्रीकल्चर युनिवर्सिटीज (हरियाणा अमैडमेंट) हबल 1991

Mr. Speaker: Now the Agriculture Minister will move the motion for consideration of the Haryana and Punjab Agriculture Universities (Haryana Amendment) Bill, 1991.

Agriculture Minister (Shri Kishan Singh Sangwan): Sir, I beg to move-

That the Haryana and Punjab Agriculturel Universities (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana and Punjab Agriculturel Universities (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana and Punjab Agriculturel Universities (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Honble Members, I have received a notice of an amendment to this clause from Dr. Harnam Singh, M.L.A. He may please move his amendment.

Dr. Harnam Singh: Sir, I beg to move-

That after clause (d), the following clauses be added, namely:-

“(e) Two members of the Legislative Assembly belonging to farming class elected by the members of the Legislative Assembly;

(f) One member of the Legislative Assembly belonging to Agricultural labour class elected by the members of the Legislative Assembly; and

(g) One nominee of Indian Council of Agricultural Research.”

Mr. Speaker: Motion moved-

That after clause (d), the following clauses be added, namely:-

“(e) Two members of the Legislative Assembly belonging to farming class elected by the members of the Legislative Assembly;

(f) One member of the Legislative Assembly belonging to Agricultural labour class elected by the members of the Legislative Assembly; and

डा० हरनाम सिंह(गाहबाद): स्पीकर साहब, मेरी अमैडमेंट यह है कि अनैक चर मे जहां कान्सटीच्यू इन पावर्ज एण्ड ड्यूटीज औफ दि बोर्ड आफ ए कौरस्पोंडिंग यूनिवर्सिटी है, उसमें इस हाउस के दो मैम्बर्ज जो प्रोग्रेसिव ऐग्रीकल्चर हो, का मो इन होना चाहिए। ये मैम्बर्ज यहां से इलैक्ट हो कर जाये चाहे

वे कोई भी हो जैसे कि दूसरी युनिवर्सिटीज में जाते हैं। दूसरी बात मैं यह चाहता हूँ कि एक एग्रीकल्चर वर्कर होना चाहिए जिसका अभी तक इस बिल में प्रावधान नहीं है। क्योंकि एग्रीकल्चर वर्कर को खेती का ऐक्सपीरियंस होता है उसे पता होता है कि बड़े बड़े फार्मों पर कैसे खेती होती है और वहाँ की क्या क्या समस्याएँ हैं। उनका अपना तजुर्बा खेती के बारे में होता है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसमें एक एग्रीकल्चरन वर्कर का भी प्रावधान किया जाये। यह भी हमारे विधायकों में से ही इलैक्ट हो कर जाये। तीसरी बात मैं यह चाहता हूँ कि इण्डियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च का भी एक नौमिनी होना चाहिए ये मेरा अमैडमेंट है। मैं समझता हूँ कि हाउस के सभी साथी इसका समर्थन करेंगे।

Mr. Speaker: Question is-

That after clause (d), the following clauses be added, namely:-

“(e) Two members of the Legislative Assembly belonging to farming class elected by the members of the Legislative Assembly;

(f) One member of the Legislative Assembly belonging to Agricultural labour class elected by the members of the Legislative Assembly; and

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the
Bill be passed.

**Agriculture Minister (Shri Kishan singh
Sangwan):** Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही अच्छी अमैडमेंट है। चौधरी चरण सिंह के नाम पर युनिवर्सिटी के नाम का हम स्वागत करते हैं। मैं नहीं सारा दे । और प्रदे । इसका स्वागत करेगा।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि हरियाणा रुरल डिवैल्पमेंट (अमैडमेंट) बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब डिवलैपमेंट मिनिस्टर हरियाणा रुरल डिवलैपमेंट (अमैडमेंट) बिल, 1991 को इंट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मो । न मूव करेंगे।

विकास मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा ग्रामीण विकास (सं ।ोधन) विधेयक, 1991 को प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि हरियाणा ग्रामीण विकास (सं ।ोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

The Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

The Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

विकास मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

श्री राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ): स्पीकर साहब, माननीय सुभाश कटियाल भी बडा अच्छा अमैडमेंट लाए है। मैं चाहूंगा कि इसमें एक और प्रोवाइजी जोड दी जाए। (विधन्) जो सदस्य ये नियुक्त करे अच्छा होगी कि 'जिस पंचायत के सदस्य का निधान हुआ हो उस पंचायत की सिफारि । से ही उसकी जगह सदस्य बनाये' यइ प्रोवाइजी जोड दी जाए।

विकास मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, इस की कोई जरूरत नही है।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि हरियाणा रिलीफ आफ ऐग्रीकल्चरल इनडैटिडनेस (अमैडमेंट) बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब रेवेन्यू मिनिस्टर हरियाणा रिलीफ औफ ऐग्रीकल्चर इनडैटिडनेस (अमैडमेंट) बिल, 1991 को इन्ट्रोड्यूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिये मोान मूव करेंगे।

Revenue Minister (Shri Sachdev Tyagi): Sir, I beg to introduce the Haryana Relief of Agricultural indebtedness (Amendment) Bill, 1991.

I also beg to move-

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य(लोहारु): अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह कानून जिस वक्त बना था, उस वक्त यह एक अच्छा कानून था। मैं केवल इसमें एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पिछले दो वर्ष से यह कानून बना है लेकिन जो प्रगति इस से होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई है। जो राहत गरीब आदमी को दी जानी चाहिए थी, वह नहीं दी गयी है। स्पीकर साहब, डैट कांसिलिएान बोर्ड के चेयरमैन डी० सी० या

ए० डी० सी० होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इनकी जगह पर किसी लायर को या प्रौमिनेन्ट पर्सन का प्रोवीजन कर दिया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगी अगर वहाँ पर कोई लायर हो या वहाँ का प्रौमिनेन्ट व्यक्ति हो, उसकी यदि चेयरमैन लगा दिया जाएगा तो वह होल टाईम इस काम को देख सकता है। इसके लिये इसमें प्रोवीजन किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों को जो कर्जा माफी की राहत थी, वह दे नहीं पाये हैं। कई कारणों से उनको यह राहत नहीं मिल पायी है। अभी तक तो कई लोगों को ज्ञान ही नहीं है। वह तभी होगा जब हम उनसे ऐप्लीके टन्त वगैरह इन्वाइर्ट करेंगे। प्रगति कभी भी इस बारे में ठीक नहीं होगी जब तक यह कानून कागजों पर ही रहेगा। यह बात दूसरी है कि भुरु में जब यह कानून बनाया गया, उस समय यह एक अच्छा कानून था लेकिन सरकार को इससे होने वाली प्रगति की ओर ध्यान देना चाहिये। धन्यवाद।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Relief of Agricultural Indebtedness (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: I have received notice of an amendment to this clause from Shri Parmanand, M.L.A. He may move his amendment.

(The Hon. Member was not present and the amendment was not moved).

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3 to 9

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 to 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the bill be passed.

Revenue Minister (Shri Sachdev Tyagi): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

श्री राम बिलास भार्मा(महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही अच्छा बिल है, जो कानून बनने जा रहा है। इसमें उन कैटेगरीज को यह सूविधा दी जा रही है जिनको ये पिछले तीन साढ़े तीन साल पहले से ऋणी मानते है अगर 'रिट्रौसपैक्टिवली' भाब्द इसमें जोडने का प्रावधान और कर दिया जाए तो इससे गरीब आदमी का काफी फायदा हो जायेगा।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vi) दि फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले ान एण्ड डिवैल्पमेंट)

अमैडमेंट बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर औफ स्टेट फार लोकल गवर्नमेंट फरीदाबाद कम्पलैक्स (रैगुले इन एंड डिवैल्पमेंट) अमैडमेंट बिल, 1991 को इन्ट्रोडयूस करेंगे तथा उस कंसिडर करने के लिए मो इन मूव करेंगे।

Minister of State for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir, I beg to introduce the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill, 1991.

Sir, I also beg to move-

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clauses 2 & 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clauses 1 stand part of the Bill.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

The Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Minister of State for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारु): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने फरीदाबाद कोम्पलैक्स के संबंध में जो यह बिल पेश किया है उसके बारे में मैं दरखास्त करना चाहूंगा कि फरीदाबाद कोम्पलैक्स के चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर की खर्च करने की पावर चाहे आप पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख कर दें या पन्द्रह लाख कर दें लेकिन वहाँ पर जो चुनाव का प्रावधान कर रखा है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। वहाँ का जो ऐडमिनिस्ट्रेटर है वह वहाँ का सब से बड़ा अधिकारी है। उसके खिलाफ मकानों को गिराने के बारे में काफी एलिंगे न लगाए गए थे। पिछले दिनों अखबारों में भी आया था कि लोगों की उसने वहाँ पर बड़ी तबाही की। वहाँ से विधान सभा के हमारे आदरणीय जो विधायक उस वक्त थे उन्होंने भी कृपि कुछ कहा था। उन्होंने इस बारे में गिरफ्तारी भी दी थी और काफी संघर्ष भी किया। लोगों को वहाँ पर काफी परेशानी रही है। अगर यह सरकार प्रजातंत्र में विवास रखती है तो इसको वहाँ प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव कराने चाहिए और चुनाव करवाकर वहाँ पर कोई समिति, म्यूनिसिपल कमिटी या कोई और संस्था बनानी चाहिए ताकि वह प्रजातांत्रिक तरीके से लोगों की तकलीफों को दूर कर सके। कई सालों से यह मामला पेंडिंग है। मैं समझता हूँ कि एक अधिकारी को हमें इसके लिए अधिकार देना अच्छी बात नहीं है और यह

प्रजातंत्र के खिलाफ है। इसलिए मैं फिर से सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि वहाँ पर जल्दी से जल्दी चुनाव कराएँ जाएँ ताकि वहाँ की समस्याओं का समाधान ठीक तरीके से हो सके।

श्री योगे । चन्द भार्मा (वल्लभगढ): स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि फरीदाबाद कॉम्प्लैक्स के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर की खर्च की सीमा को चाहे आप पांच से बढ़ाकर दस लाख कर दें या बीस लाख कर दें लेकिन वहाँ पर चुनाव न करवाना लोगों के साथ यह सबसे बड़ा धोखा है जब हम चुनाव जीतकर आए थे तो चौधरी देवी लाल ने कहा था कि मैं डैमोक्रेटिक तरीके से काम करूँगा। उन्होंने म्यूनिसिपल कमिटीज के चुनाव करवाए लेकिन वे अधूरे छोड़ दिए। स्पीकर साहब, फरीदाबाद कॉम्प्लैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स में बड़ी भारी धांधली मची हुई है। वहाँ भ्रष्टाचार पूरे तौर पर फैला हुआ है। लोगों के मकान दुकान बनते हैं तो वहाँ के अफसर उन्हें तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि दस हजार रुपया दो वरना मकान तोड़ देंगे। अब जिस आदमी ने दो तीन लाख रुपया खर्च किया होता है वह दस हजार रुपया देकर अपना मकान बचा लेता है। वहाँ के लोग मकान बनाते हैं और दूसरे ही दिन अधिकारी उसे तोड़ने पहुंच जाते हैं। स्पीकर साहब, इस बात से ही उन की कठिनाईयों का अंत नहीं होता। वहाँ पर तीन जोन बने हुए हैं। जब एक अफसर पैसा ले लेता है तो वह बदलकर दूसरे जोन में चला जाता है और उसके बाद दूसरा अफसर आ जाता है उस

आदमी का खून पीने के लिये। वह दूसरा अफसर मकान पर पहुंच जाता है और मकान मालिक से रि वत मांगता है। इस तरह से वहां पर धांधली मची हुई है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि यह सरकार भयोर करे कि पार्लियामेंट के चुनाव के साथ ही वहां पर भी चुनाव करायेगी। वहां पर लोगो ने करोडो रुपये लगाकर होटल मकान और दुकाने बनाई है लेकिन वहां पर अफसर उनको तोडने चले आते है और फिर मकान मालिक से सौदेबाजी करते है। आप दस लाख कर दे या बारह लाख कर दे लेकिन ऐसा करके आप उस अफसर को खुली छूट दे रहे है कि वह ताना गाही मचाए। इसलिए वहां पर चुनाव कराने बहुत जरुरी है जिससे लोग चैन की सांस ले सकें। स्पीकर साहब, मेरी सरकार से दरखास्त है कि वहां पर यह ईमानदान अफसर भेजे, भ्रष्टाचारी अफसरो को वहां न भेजा जाए।

श्री राम बिलास भार्मा(महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक द्वारा सरकार फरीदाबाद कौम्पलैक्स के मुख्य अधिकारी को पांच लाख रुपये की बजाए दस लाख रुपए खर्च करने की पावर दे रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बे तक यह सीमा बढा दी जाए लेकिन सरकार इस सदन मे यह आ वासन दे कि फरीदाबाद मे नगरपालिका के चुनाव भीघ्नाति पीड करारए जाएंगे। स्पीकर साहब, फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है ओर दिल्ली के पडोस में है। इसलिए वहां पर प्र तासन चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए। मैं यह आ वासन चाहता हूं कि वहां जल्दी से जल्दी

चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद चाहे वहां पर आप कार्पोरेट बनाने दें और चाहे नगरपालिका बना दें तो अच्छी बात होगी। फरीदाबाद एक औद्योगिक नगर है। बार बार चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किए जाने वाले खर्च की सीमा बढ़ाने से फरीदाबाद के लोग दिक्कत महसूस करते हैं। आप एक अफसर को इतना पैसा खर्च करने की पावर इस तरह से डेलीगेट कर रहे हैं जिस तरह से कि पार्लियामेंट में लोक लेखा अनुदान पे 1 किया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि स्थानीय प्रशासन मंत्री जी इस बिल में ऐसी कोई क्लॉज जोड़े और हमें विवास दिलाएं कियह जो अमैडमेंट कर रहे हैं यह अंतिम होगी।

स्थानीय भासन मंत्री (श्री कान्ति प्रकाश भल्ला): अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रशासक को इस समय पांच लाख रुपए तक खर्च करने और ठेके अनुबन्धित करने की पावर है। चूंकि आजकल सामान वगैरह के रेट्स बढ़ गए हैं जिसके कारण से कामों पर ज्यादा पैसा खर्च होता है इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम पांच लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख करने जा रहे हैं ताकि हमें बार बार सरकार की ऐप्रुवल न लेनी पड़े और कामों में भी किसी प्रकार की कोई रुकावट न आने पाए। इस में कोई ऐसी बात नहीं है जिस के लिए किसी सदस्य महोदय को कोई ऐतराज हो। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए क्योंकि यह जो हम करने जा रहे हैं, यह सारा

जनता के हितों में है। मेरे विचार में इस संबंध में किसी माननीय सदस्य को कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(viii) दि पंजाब टाउन इम्प्रूमेंट (हरियाणा अमैडमेंट) बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार लोकल गवर्नमेंट पंजाब टाउन इम्प्रूमेंट (हरियाणा अमैडमेंट) बिल, 1991 को इंट्रोडयूस करेंगे।

Minister of State for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir, I beg to introduce the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Bill, 1991.

Mr. Speaker: Hon Members, I have received a notice for disapproval of the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 3 of 1990) If the House agrees, this motion and the motion for consideration of the Bill be considered together and voted upon separately.

Voices: Yes.

Shri Hira Nand Aryan: Sir, I beg to move-

That this House disapproves the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 3 of 1990)

Minister of State for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir, I beg to move-

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, मेरी यह दरखास्त है कि जब यह हाउस बैठ रहा था तो यहां इस आर्डिनैन्स को लाने की क्या ऐमरजेंसी थी। अगर ये बिल ले कर आते और उस पर डिस्कान हो जाती तो अच्छा होता। ट्रस्टीज को लगाने व हटाने की पावर्ज तो पहले ही सरकार के पास है, इस आर्डिनैन्स को यहां लाने की क्या जरूरत थी? इसलिए मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि अगर इस को वापिस ही लें ले तो बेहतर रहेगा। इस आर्डिनैन्स की कोई जरूरत नहीं थी। नया जो ढांचा खड़ा करने जा रहे हैं, इससे और पैसा खराब होगा।

डा० हरना सिंह (गाहबाद): अध्यक्ष महोदय, भाहरो में इलैक्ट्रिक म्यूनिसिपल कमेटीज है। एक तरफ तो सरकार के पास रिसोर्सिज की कमी है दूसरे हम इम्प्रूवमेंट के नाम पर नया ढांचा खड़ा करने जा रहे हैं, इससे पैसे की बर्बादी है। अगर म्यूनिसिपल

कमेटीज को ही और पैसा इसकी जगह दे दिया जाए तो मेरे विचार में बेहतर रहेगा। नये आदमी नामजद करने से ज्यादा पैसा खर्च करना पडेगा। इसलिए मेरी रिकवैस्ट है कि इस तरह न करके पैसा बचाया जाए और दूसरे इम्प्रूमेंट के कामो पर खर्च किया जाए जिससे जनता का हित हो।

श्री राम बिलास भार्मा(महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय, इस बिल को यहां लाने की जरूरत नही थी। इम्प्रूमेंट ट्रस्ट का Chairman is appointed by the State Government on its pleasure. He can be removed from the Chairmanship at any time without pre-condition. Therefore, the Bill seems to be very superfluous. There was no need to bring such a bill. जब नगरपालिकाओ के चुनाव हो गए थे तो उसके ऊपर इम्प्रूमेंट ट्रस्ट बनाने की क्या जरूरत थी? It's all extravagance. इससे एक तो नगरपालिकाओ को ग्रांटस कम मिली और दूसरा तरफ इम्प्रूमेंट ट्रस्ट का जो इंस्टीच्यू इन है उसको मँटेन करने के लिए सरकार को नगरपालिकाओ से भी ज्यादा खर्चा करना पडता है। नगरपालिकाओ के चुने हुए जो चेयरमैन ओर सदस्य है they are accountable to the people, to the citizens of the State. इम्प्रूमेंट ट्रस्ट जो बनाए गए है इनमें राजनैतिक लोगो केचहेते लोग लगाए जाते है जिनकी कोई अकाउंटेबिल्डी नही होती। इसलिए इस बिल की कोई जरूरत नही है। मै चाहता हूं कि इम्प्रूमेंट ट्रस्ट के इंस्टीच्यू इन को खत्म किया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That the House disapproves the Punjab Town improvement (Haryana Amendment) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 3 of 1990).

The Motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Town Improvement (Haryana Amendment) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2 to 5

Mr. Speaker: Question is-

That the clause 2 to 5 stand part of the Bill.

the motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That the clause 1 stand part of the Bill.

the motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

the motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move th Bill be passed.

Minister of State for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(viii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैडमेंट) बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार लोकल गवर्नमेंट हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैडमेंट) बिल, 1991 को इन्ट्रोड्यूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मोान मूव करेंगे।

Minister of Stte for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1991.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री राम बिलास भार्मा(महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन मे रखा है मै इसका विरोध करने के लिए खडा हुआ हूँ। यह जो टोल टैक्स वाली बात है, इसके बारे में निवेदन है कि पहले ही हरियाणा में काफी टैक्सिज है। इसके स्टेटमेंट आफ आबजैक्टस एंड रीजंज में लिखा है—

“To enable the Transport Department to levy toll tax on motorized vehicles.....”

श्री कान्ति प्रका । भल्ला: स्पीकर साहब, यह टोल टैक्स वाला बिल नहीं है वह तो आगे आ रहा है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मेरे पास जो बिल की कापी है उसके स्टेटमेंट आफ आबजैक्टस एंड रीजंज मे टोल टैक्स के बारे में लिखा है। या तो इसमें प्रिंटिंग की मिस्टेक रह

गई है। (विधन) चलो जब वह बिल आएगा तो मैं उस समय बोल लूंगा।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the bill clause by clause.

Sub-Clause 2 and 3 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That sub-clauses (2) and (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker: Question is-

That clauses 2 & 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Minister of State for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ix) दि हरियाणा पब्लिक वफकस (ऐक्सटैन्शन आफ लिमिटेड) बिल, 1991

12:00 बजे

Mr. Speaker: Now the Minister of State for Wakfs will introduce the Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill, 1991 and also move for its consideration.

Minister of State for wakfs (Shri Hasan Mohammad): Sir, I beg to introduce the Haryana Public Wakfs (Extention of Limitation) Bill, 1991.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Public Wakfs (Extension of imitation) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Public Wakfs (Extension of imitation) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द (लोहारु): अध्यक्ष महोदय, इस वक्फ बोर्ड की नालायकी के परिणामस्वरूप यह अमैडमेंट बार बार लाई जा रही है। 1947 से कर आज तक कम से कम 10 बार अमैडमेंट लाई जा चुकी है। हर बार समय बढ़ाने के लिए अमैडमेंट ले आते हैं और यह अमैडमेंट करने की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि वक्फ बोर्ड की जितनी प्रोपर्टी है जि पर वह क्लेम करता है उसका पता लगाया जा सके। वक्फ बोर्ड को यह पता ही नहीं है कि उसकी

प्रोपर्टी कहां कहां पर है और किस तरह से है। यदि वक्फ बोर्ड इतना लायक होता तो उसको अपनी प्रोपर्टी का पता लगा लेना चाहिए था। लेकिन वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी पर लोगो ने 20-20, 40-40 साल से कब्जा कर रखा है। 40 साल के बाद तो नई पीढी आ जाती है इसलिए अब तो उसपर दूसरी पीढियो का कब्जा हो गया है उस प्रोपर्टी पर दूसरी पीढी के लोग अपना अपना जीवन निर्वाह कर रहे है। अब किस किस को कहे कि यह प्रापर्टी आपकी नही है। यह कैसे पता लगाएं कि वह प्रापर्टी किसके पास है। किसने उस पर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड मे जो कर्मचारी हैं वे भी लोगो के साथ ठगी करते है। वे लोगो से पैसा ले लेते है इसलिए लोग प्रोपर्टी नही छोडते ओर जिन लोगो ने वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी पर नाजायज कब्जा कर रखा है वे उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते है। इसलिए मै मंत्री जी से गुजारि । करुंगा किवे यह आ वासन दे कि भविश्य में इस तरह की अमैडमेंट की जरुरत नही पडेगी।

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 and

Mr. Speaker: Question is-

That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Minister of State for Wakfs (Shri Hasan Mohammed): Sir, I beg to move-

The motion was carried.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(x) दि हरियाणा मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्ज (टोल) बिल, 1991

Mr. Speaker: Now the Minister of State for Transport will introduce the Haryana Motor Transport Vehicles (Toll) Bill, 1991.

परिवहन राज्य मंत्री (श्री वेद सिंह मलिक): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा मोटर परिवहन यान (पथकर) विधेयक, 1991 प्रस्तुत करता हूँ।

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice for disapproval of the Haryana Motr Vehicles (Toll) ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 5 of 1990) from Shri HiraNand Aryan, M.L.A. If the House agree this motion and the

motion for consideration of the Bill be considered together and voted upon separately.

Voices: Yes.

Shri Hira Nand Arya: Sir, I beg to move-

That the House disapproved the Haryana Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 5 of 1990)

Mr. Speaker: Motion moved-

That the House disapproved the Haryana Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 5 of 1990)

Minister of State for Transport (Shri Ved Singh Malik): Sir, I beg to move-

That the House disapproved the Haryana Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 5 of 1990)

Mr. Speaker: Motion moved-

That the House disapproved the Haryana Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 5 of 1990)

श्रीमती कमला वर्मा(यमुनानगर): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक तपो भूमि रहा है, देव भूमि रहा है। इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और इसी धरती पर महाभारत का धर्मयुद्ध हुआ। इस प्रदेश की भाौर्य गाथाएं सुन

करके हमें बड़ा गौरव होता है। लेकिन इसी हरियाणा में कुछ विभिन्न घटनाएं चाहे वे आया राम गया राम की हो, चाहे मेहम की वजह से हुई या लोकतंत्र की हत्या की बात हो, भ्रष्टाचार व जमीन पर अवैध कब्जों की बात हो हरियाणा काफी बदनाम हुआ है। (गोर एवं व्यवधान) कर्जा माफी और वृद्धावस्था पेंशन की जो स्कीम आई थी उससे हरियाणा के लोगों में कुछ आशा जगी थी लेकिन उस आशा को भी पिछले एक वर्ष से धूमिल कर दिया जगजग लोगों को समय पर पेंशन मिलती नहीं और कर्जें भी सब लोगों के माफ नहीं हुए। मैं अब इस नए बिल की बात करती हूँ जिसने हरियाणा को और बदनाम कर दिया है। (गोर एवं व्यवधान) (लोक निर्माण मंत्री की ओर से विघ्न)

Mr. Speaker: Jagan Nath Ji, she is respected sister. Please take your seat and let her complete her speech.

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, आज इन्होंने चप्पे चप्पे पर बैरियर्ज खोल रखे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

डा० रघुबीर सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, सरकार का एक जिम्मेवार मंत्री बार बार किसी के बोलने पर खड़ा हो जाता है, यह अच्छी बात नहीं है। पता नहीं इनके पेट में क्या गडबड है जिसकी वजह से ये बार बार खड़े हो जाते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: This is no point of order. Please take your seat.

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, इन्होन इस बिल के अन्दर 200 रुपये तक टोल टैक्स लगाने की बात कही है लेकिन फिलहाल ये सिर्फ 100 रुपये लगा रहे है। इस बारे में मैं इनको बताना चाहती हूँ कि जब किसी ट्रक को नै इनल परमिट दिया जाता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन के वक्त जो प्रान्त उस परमिट में शामिल होता है उनका पूरा ट्रक्स ले लिया तो फिर ये 100 रुपये टोल टैक्स के रूप में लगाने की क्या आवश्यकता थी? अब इन्होने इस बिल के जरिए यह प्रावधान किया है कि जब भी किसी दूसरी स्टेट का कोई ट्रक हरियाणा में प्रवेश करेगा उससे 100 रुपया लिया जायेगा। तो उसका क्या परिणाम होगा वह भी मैं आपको बता देती हूँ। इस टोल टैक्स के लगने से कितना भ्रष्टाचार बढेगा इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते है। आज हरियाणा के अन्दर चप्पे चप्पे पर इन्होने बैरियर्ज खोले हुए है। इन बैरियर्ज पर पहले ही ड्यूटी देने वाले कर्मचारी रात के अन्धेरे में टार्च लेकर ट्रक वालो को कहते है कि कागजात दिखाओ या कोई भी गलती निकाल कर रोक लेते है। कुछ ट्रक वालो के साथ पैसे बांधे हुए है। यह एक नया टोल टैक्स लगने से हरियाणा बैरियर्ज पर और अधिक भ्रष्टाचार बढेगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं जानती हूँ यह ट्रक हरियाणा के बाहर के होंगे। (ट्रेजरो बैंच के कुछ सदस्यो तथा लोक निर्माण मंत्री श्री जगननाथ की तरफ से विघ्न)

Mr. Speaker: This is not the way. I won't permit the Treasury Benches to behave like this. Mr. Jagan Nath ji, you

are a minister. You should not behave like this. I do not like it. let the Hon. Member proceed.

श्रीमती कमला वर्मा: स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहती हूँ कि जो ट्रक बाहर से आते हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन फी तो दी हुई होती है। ट्रक ने इनल परमिट ले कर स्टेट में आते हैं फिर यह नया कर भार क्यों? यह जो टैक्स उनसे लिया जा रहा है इसका असर तो ट्रक वालों पर नहीं बल्कि डायरेक्ट कन्ज्यूमर्स पर पड़ेगा। जनता को पहले ही काफी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और परिवहन पर इस अतिरिक्त खर्च के कारण महंगाई में और भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि ट्रक में सामान जो भी लाया या भेजा जाएगा, यह खर्च उपभोक्ता को ही देना होगी जो उचित नहीं। स्पीकर साहब, मैं इस बिल का विरोध करती हूँ तथा यह अनुरोध करती हूँ कि इस बिल को वापिस ले लिया जाए (धन्यवाद)।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, यह जो व्हीकल्स पर 200 रुपये का टैक्स बेरियान पर लगाने का प्रावधान किया गया है, मैं इसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप जरा सोचिए कि एक ट्रक कमीर से चलता है पंजाब से गुजरेगा और फिर हरियाणा में प्रवेश करेगा और फिर दिल्ली पहुंचेगा उसे सब जगह 200 रुपये देने होंगे (विघ्न) बैरियर्स पर ट्रकों से जो पैसा आएगा उसमें 100 हजारों रुपया जेबों में जाएगा। 100 या 200 की ट्रकों की पर्ची काट दी तो काट दी नहीं काटी तो

न सही। बैरियर्ज पर तो पहले ही बहुत ज्यादा करणान होती है। यह 200 रुपये और वसूल करने से इस करणान से बढ़ोतरी होगी। हरियाणा को इस बात के लिये माना जाता रहा है कि यहां बैरियर्ज पर कम टैक्स है, इसी कारण सारे देश में व्हीकल्ज वाले इसे अच्छा समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस टैक्स का भार साधारण उपभोक्ता पर ही पड़ेगा और इससे भ्रष्टाचार को भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। (विघ्न) स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल जी ने "भ्रष्टाचार बन्द" का नारा दिया था लेकिन इस बिल के द्वारा तो सरकार भ्रष्टाचार बन्द करने की बजाए भ्रष्टाचार का प्रबंध कर रही है। (विघ्न)

Mr. Speaker: Thank you very much, Arya Ji. Please take your seat now.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं इस बिल का विरोध करता हूँ और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री विठ्ठल प्रसाद(अम्बाला भाहर): स्पीकर साहब, ऐमरजेंसी के बाद सन् 1977 में विपक्ष की पहली सरकार केन्द्र में आई थी जिस ने करणान को खत्म करने के लिए कदम उठाए थे। जैसे ही सारे देश से बैरियर सिस्टम सरकार ने खत्म किया तो सारी करणान और बेईमानी खत्म हो गई। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस टैक्स को लगाने से सरकार को बहुत ज्यादा आमदनी हो जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि इससे

करण और बेईमानी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। यहां तक कि जो खाली ट्रक गुजरेगें उनसे भी जबरदस्ती पैसा वसूल किया जाएगा। स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है सरकार इस टैक्स को वापस ले ले तथा मेरा यह भी कहना है कि इन्सपैक्टरी राज को जितना खत्म किया जाए उतना ही अच्छा है। स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री राम बिलास भामा(महेन्द्रगढ़): स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया। इस बिल के उद्देश्य और कारणों से माननीय मंत्री जी ने खुद फरमाया है कि स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए पथ कर से सड़क द्वारा माल ले जाने वाले वाहनों की परिचालन कार्यकुशलता प्रभावित हुई है। बहुत अच्छी बात इन्होंने यहां पर कही है कि जब लाईन लगती है तब लोगोंको असुविधा होती है। पहले पर्वी वहां पर 2-4 रुपए की होती थी लेकिन अब यह कर 200 रुपये तक लगाया जा सकता है। कम से कम जो उन्होंने उद्देश्य और कारणों में दिया है, कि उनको 4 रुपये देते हुए असुविधा होती थी यह तो न लिखते। अब तो इन्होंने एक ही नाउ से उनका कत्ल कर दिया। क्या अब उनको 200 रुपये देने से सुविधा हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार पब्लिक प्रोपर्टी की कस्टेडियन होती है। हरियाणा में जो बाकी कर है, चाहे वह बिजली के रेट्स हो या दूसरे टैक्स हो, कई बार बढ़ चुके हैं। बिजली के रेट्स तो तीन बार बढ़े हैं। बसों के भाड़े भी तीन बार

बढाये गये है। इसलिए अब लोगो को यह भावना है कि ये जो पब्लिककी प्रापर्टी के रखवाले है, ये खुद खा गये है। करोडो रुपये की सौ सौ करोड की प्रोपर्टी जलवा दी। यह जो जजिया कर लगा रहे है। हरियाणा के अन्दर ऐसा करके इन्होने एक नयी परम्परा डाली है। चौधरी वेद सिंह मलिक एक अच्छे घर से संबंध रखने वाले है, मै चाहूंगा कि वे इस बिल को वापिस ले लें।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): अध्यक्ष महोदय, यह एक नयी परम्परा भुरु करने जा रहे है। हरियाणा सरकार का यह कहना कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का टोल टैक्स पहले से ही था यह उचित नही है। लोगो को पहले ही बडी घबराहट होती थी। जगह जगह टैक्स देने के लिए रुकना पडता है। यह एक बडी ही लज्जाजनक बात है। साथ ही दस बिल मे यह भी लिखा हुआ है कि 200 रुपये से ज्यादा यह टैक्स नही होगा। मै इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि एक व्हीकल के एक बार हरियाणा में प्रवेश करने के बाद दूसरी बार उससे टैक्स नही लिया जाएगा, ऐसा किया जाना चाहिए। इसमें तो यह है कि एक दिन में दूसरी बार नही लिया जाएगा। हो सकता है कि एक दिन में वह हरियाणा की टैरेटरी पार न कर सके। लम्बे सफर का कोई ट्रक हो और वह हरियाणा में रुक जाये तो उसकी तो दूसरी बार टैक्स देना पडेगा। इसलिए मै इसका विरोध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इसको पास नही किया जाना चाहिये।

परिवहन राज्य मंत्री(श्री वेद सिंह मलिक): स्पीकर साहब, मेरे साथी इस बिल का विरोध कर रहे थे। मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि यह केवल हरियाणा स्टेट में ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी यह टैक्स लगा हुआ है, मध्य प्रदेश में भी 100 रुपये का यह टैक्स लगा हुआ है, जहाँ पर हमारे इन भाइयों की सरकार है। यू0 पी0 में भी है और इसके अलावा और कई स्टेट्स में यह टैक्स है। हरियाणा में जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, उन पर तो कोई टैक्स नहीं है लेकिन जो गाड़ियाँ बाहर की हैं, उन पर यह टैक्स लगता है। इससे 10 लाख से लेकर 14 लाख रुपया रोजाना हमारे खजाने में आता है। यह सारी की सारी गाड़ियाँ जब हरियाणा में रजिस्टर हो जाएगी तब इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस टैक्स से सरकार को काफी फायदा होगा। इसका 10 प्रतिशत हिस्सा हम उन म्यूनिसिपल कमिटीज को देंगे जिनके नाके वहाँ पर होंगे क्योंकि हमने राहदारी खत्म कर दी है। इन भाइयों के साथ मेरी यह प्रार्थना है कि इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That this house disapproves the Haryana Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance 1990 (Haryana Ordinance No. 5 of 1990)

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That this house disapproves the Haryana Motor Transport Vehicles (Toll) Ordinance 1990 (Haryana Ordinance No. 5 of 1990)

The motion was lost.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was lost.

Clauses 2 to 14

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 to 14 stand part of the Bill

The motion was lost.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was lost.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was lost.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Minister of State for Transport (Shri Ved Singh Malik): Sir, I beg to move-

That the bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the bill be passed.

The motion was lost.

(xii) दि पंजाब विलेज कौमन लैण्डज (रेगुले ान)

हरियाणा अमैडमेंट बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब डिवैल्पमेंट मिनिस्टर पंजाब विपेज कौमन लैण्डज (रैगुले ान) हरियाणा अमैडमेंट बिल, 1991 को इंट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मो ान मूव करेंगे ।

Development Minister (Shri Subhas Chand Katyal): Sir, I beg to introduce the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1991.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, यह अमैडमेंट इसलिए लाई जा रही है कि यदि ग्राम पंचायत की जमीन पर, भामलातदेह जमीन पर किसी ने नाजायज कब्जा किया हुआ हो तो उस जमीन को नाजायज कब्जे से छुड़ाया जा सके। इस अमैडमेंट के जरिए असिस्टैन्ट क्लैकटर को पावर्ज दी जा रही है कि ऐसे मामलो में वह अपनी पावर्ज का इस्तेमाल करके उस पंचायत की जमीन को नाजायज कब्जे से छुड़ा सकता है। मैं इसका स्वागत करता हूं। स्पीकर साहब, मैं इस संबंध में एक बात विस्तार से कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में बहुत सी भामलात

जमीनें, पंचायत की जमीनें और आबादी देह की जमीनें खासतौर पर गुडगांव और फरीदाबादके अधिकारियों, कर्मचारियों और सत्ताधारियों ने मिलकर मुस्तरका मालिकान के रूप में बदली है। लगभग अठारह बीस गावों में हजारों एकड़ जमीन पंचायतों के अधिकारियों ने, उस वक्त के एस० डी० एम० डिप्टी कमि नर और पटवारी ने रातों रात इन्तकाल दर्ज किए और रातों रात उन पंचायत की जमीनों पर और भामलात देह की जमीनों पर कब्जे किए और रातों रात करोड़ों रुपये की खरीद फरोख्त हो गई। यह काम इतनी जल्दी में किया गया जैसे की लुटपाट हो रही हो। यह जो कुछ किया वह राजनैतिक संरक्षण से किया गया। कुछ राजनैतिक लोग भी हैं जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं और अपने आपको सुपर मुख्य मंत्री समझते हैं। ऐसे व्यक्ति भी उनमें शामिल हो गए। मैं समझता हूँ कि बिल में अमैडमेंट करके भामलात देह जमीनों के लिए, पंचायत की जमीनों के लिए नाजायज कब्जों से प्रोटैक्टान दे रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि आप हाउसकी एक कमेटी बनाएँ और वह कमेटी इस चीज की इन्क्वायरी करे कि किन लोगों ने गलत तरीके से ऐसी जमीनों पर कब्जे किए हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को, जिन्होंने करोड़ों रुपये की जमीनों का घपला किया है और नाजायज कब्जा किया है, सरकार उनको कहे कि वे सुओमोटो उस जमीन को छोड़ दें और वह जमीन पंचायतों को वापिस दी जाए। स्पीकर साहब, जब समय आएगा तो ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और ऐसे लोगों से जवाब मांगा जाएगा।

श्री राम बिलास भार्मा(महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय, जो लोग पावर में होते हैं उनको गलतफहमी हो जाती है कि वे सदा रहने वाले हैं और कई बार उसी गलतफहमी के कारण ऐसे गलत कानून बन जाते हैं जो बाद में खुद को तकलीफ में डाल देते हैं। स्पीकर साहब, इस सदन में बहुत से लोग किसान हैं। स्पीकर साहब, आप खुद एक किसान हैं और बहुत बड़े और काबिल वकील हैं। स्पीकर साहब, बिल प्रोवाइजो में कहा गया है कि गांवों में वटबन्दी से पहले, चकबन्दी से पहले जो भूमि वाले किसान थे उनकी कुछ जमीनें भामलात देह से अलग बची हुई थीं। खातो के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी थी। थोकवाइज वे उसके मालिक होते थे। अब ये इस कानून के तहत तो मुस्तरका मालिकान है, जुमला मालिकान है उनकी सारी जमीन को भामलात देह में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये ए० डी० सी० और बी० डी० पी० ओ० को पावर देना चाहते हैं कि जो जुमला मालिकान है, मुस्तरका मालिकान है उनकी इच्छा के विरोध में सरकार जब चाहे उसका अधिग्रहण कर ले। बी० डी० पी० ओ० जब चाहे किसी राजनैतिक आदमी के इतारे पर उसका अधिग्रहण कर ले। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, बिल के ऊपर बड़ी गम्भीरता से चर्चा हो रही है और हम उनको ऐसे सुझाव दे रहे हैं जिसमें लोगों को फायदा है। मंत्री का काम अध्यक्ष महोदय, बड़ा जिम्मेवारी का होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री सुभाष कटियाल स्वयं एक किसान हैं, उनके गांव में भी जमींदार रहते हैं। उनके स्वयं के

पास भी जमीन है। मैं उनके गांव में गया हुआ हूँ। उनको मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि वे जो करने जा रहे हैं इससे गांव में झगडा बढेगा। अध्यक्ष महोदय, इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ए० डी० सी० व बी० डी० पी० ओ० तो हमें ठाँ रहने वाली नहीं है। वे तो चले जाते हैं। परन्तु मुस्तरका मालिकान तो वहाँ पर हमें ठाँ ही रहने वाले हैं। यह एक परम्परा रही है कि जुमला मालिकान की जो जमीन होती है, उसको सभी मिलकर गांव की भलाई के लिए दे देते हैं। इसलिए इस क्लोज को यहाँ लाने का कोई लाभ नहीं है। मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय यदि दोबारा इस पर विचार कर लें तो बेहतर रहेगा।

विकास मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, इसबिल को इसलिए यहाँ पर लाया गया है ताकि कोई भामलात देह जमीन को न दबा सके और उसपर डैटरेंट ऐक्ट ठान हो सके। इन लोगों ने इस बारे में जो अपने विचार रखे हैं, वे उचित नहीं हैं। हमने जो बिल रखा है, वह बिल्कुल सही रखा है। इसके साथ साथ मैं हाउस को यह भी बताना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष के लोगो ने कहीं पर किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है और न ही किसी से करवाया है। यह इनका कहना बिल्कुल निराधार है। धन्यवाद।

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice of an amendment to this clause from Shri Harnam Singh, M.L.A. he may please move his amendment.

Dr. Harnam Singh: Sir, I beg to move-

That in clause 3 of the amending Bill sub-section (5) of section 7 be deleted.

Mr. Speaker: Motion moved-

That in clause 3 of the amending Bill sub-section (5) of section 7 be deleted.

डा० हरनाम सिंह(गाहबाद): स्पीकर साहब, मेरी अमैडमेंट का मतलब यह है कि जहां तक भामलात देह जमीन का सवाल है, उससे नाजायज कब्जा हटना चाहिये। स्पीकर साहब, सब सैक्शन (5) आफ सैक्शन (7) में यह कहा गया है कि Any person who is found in wrongful or unauthorized possession of the land or other immovable property in shamlat deh and is ordered to be ejected under sub-section (1), he shall be

punishable with imprisonment for a term which may extend to two years. मैं अर्ज करना चाहूंगा कि पहले यह प्रावधान किया गया है कि हम जमीन से बेदखल करें। चल व अचल संपत्ती का जहां तक सवाल है, उससे तो बेदखल होना ही चाहिये लेकिन मैं इस बात को दुरुस्त नहीं समझता कि बेदखली के साथ साथ उसे सजा भी दी जाए। बेदखली तक तो हमारा मकसद रहना चाहिए लेकिन सजा देना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। अब हम एक आदमी को बेदखल कर सकते हैं तो फिर उसको सजा देने का प्रावधान क्यों रखा जाए? इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बतलाना चाहता हूँ कि जो मकानों पर, दीवारों पर नारे लिख देते हैं, पेस्टिंग कर देते हैं, इसके लिए एन्टी डिफेसमेंट ऐक्ट बनाया गया था यह देखने के लिए कि कौन डिफेसमेंट करता है। लेकिन जब मैं सड़को पर आता हूँ तो देखता हूँ कि दीवारों पर जगह जगह जन संदेश लिखा हुआ है कि जो सरकार की अपनी पार्टी का अखबार है। मैं इन से पूछता हूँ कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ इन्होंने कोई केस दर्ज किया? बिल्कुल नहीं किया है। इसलिए मैं अन्त में इतना ही कहूंगा कि केवल बेदखली की बात ही होनी चाहिये और जहां तक सजा देने की बात है, उसको इसमें से डिलीट कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is-

That in clause 3 of amending Bill, sub-section (5) of section 7 be deleted.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was lost.

Clause 4 to 6

Mr. Speaker: Question is-

That clause 4 to 6 stand part of the Bill.

The motion was lost.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was lost.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The motion was lost.

Title

Mr. Speaker: Question is-

The Title be the Title of the Bill.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

विकास मंत्री (श्री सुभाश चन्द कटियाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xii) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैडमेंट) बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब होम मिनिस्टर हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैडमेंट) बिल, 1991 को इन्ट्रोडयूस करेंगे।

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1991.

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice of disapproval for the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No.2) of 1990 from Shri Hira Nand Arya, M.L.A. If the House agrees, this motion and the motion for consideration of the Bill be considered together and voted upon separately.

Voices: Yes.

Shri Hira Nand Arya: Sir, I beg to move-

That this House disapproves the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 2 of 1990).

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House disapproves the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 2 of 1990).

Home Minister (Prof Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहार): अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जो आर्डिनैस सरकार ने जारी किया था यह आर्डिनैस कोई पहली बार जारी नहीं किया गया है। इसको जारी करने से पहले जनरल सेल्ज टैक्स ऐक्ट की सैक्शन 9 को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रोक डाउन कर दिया था। उसके बाद दोबारा उसको अमेंड करने के लिए और जजमेंट नलीफाई करने के लिए सरकार ने यह आर्डिनैस जारी किया। उस दौरान सरकार ने यह पाया कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और हो गया। उसके बाद यह जो आर्डिनैस

किया यह भी गलत है, गैर कानूनी है और यह भी स्टैंड नहीं कर पाएगा। अब इन्होंने जो बिल पे 1 किया है उसको और अमैंड करके पे 1 किया है। आप देखेंगे कि किस प्रकार गलत तरीके से और जल्दबाजी में ये इस प्रकार के अध्यादेश जारी करते हैं और कितनी कितनी अमैंडमेंट करते हैं। इसमें एक विशेष बात यह है कि पहले जो आर्डिनैस द्वारा अमैंडमेंट की थी उसमें यह किया था कि टैक्स ऑन सेल्ज एण्ड परचेजिज होगा। लेकिन अब यह और ही अमैंडमेंट आ गई। मैं गुजारि 1 करूंगा कि ऐसे बिल लाने में यह सरकार जल्दबाजी न करे ताकि रोज रोज अमैंडमेंट न करनी पड़े। जो व्यापारी हैं उन्होंने पता नहीं किस प्रकार से पैसा इकट्ठा किया है इसलिए उनके अधिकारों पर डाका न पड़े। यह सरकार बताए कि जिन जिन व्यापारियों का सेल्ज टैक्स का ज्यादा पैसा जमा हो जाएगा तो क्या उन व्यापारियों को वह पैसा रिफण्ड किया जाएगा। उनको यह पैसा रिफण्ड करने के लिए रिफण्ड वाउचर बनाने पड़ेंगे और रिफण्ड वाउचर बनाते वक्त यह भी देखना पड़ेगा कि किसका कितना पैसा किस खजाने में जमा है। यह बहुत लम्बा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बिल को पास करवाने की बजाय सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाए वरना यह जो बार बार अमैंडमेंट की जा रही है और जो अब की है यह भी स्टैंड नहीं करेगी, स्ट्रक डाउन हो जाएगी। जब भी किसी ने इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो यह ठहर नहीं पाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि रोज रोज लोगों को अदालतों में न जाना पड़े और सरकार का पैसा भी लिटिगेशन में खर्च न हो

बेहतर यह होगा कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये और सिलैक्ट कमेटी की रिक्मेंडे ांज के बाद इस पर विचार किया जाए। This bill has no positive purpose इसको लाने की जरूरत सिर्फ इसलिए पडी क्योंकि हमने कुछ गलत कानून बनाया हुआ था उसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया और सरकार के खिलाफ कुछ बात कह दी। उस गलती का रिट्रोस्पैक्टिवली सुधार करने के लिए यह विधेयक के रूप में लाए है। इससे पहले आर्डिनैस भी जारी किया गया था। अध्यक्ष महोदय, यह एक गलती सी परम्परा पडती जा रही है कि अपनी जरूरत के मुताबिक कानून में सं ाोधन करते जाएं। कानून बनने से पहले उस कानून को गहराई तक जाना चाहिए और उसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में एक परम्परा सी बनी हुई है कि हम टैक्सज लगा रहे है, सक कुछ बढा रहे है। सरकार को अपना वि ालेशण करना चाहिए कि what is the rate of realization. जो टैक्सज लगातार बिना किसी से सलाह किए लगाए जा रहे है उनका रियलाइजे ान रेट क्या है। हरियाणा में एक पैरलल सिस्टम चल रहा है। to collect the taxes. जो एक वैधानिक सरकार है उससे भी अधिक टैक्सज इकट्ठे किए हुए है। डिप्टी कमि नर, डी० ई० टी० सी० और बी० डी० ओ० जनसंदे ा के लिए ऐडवर्टाइजमेंट इकट्ठी कर रहे है। इसके अलावा जो टैक्स महकमे के अधिकारी है उनको यह टारगेट दिया जाता है कि इस साल टैक्स की रियलाइजे ान उतनी होनी चाहिए जिसको

व्यापारी सहन कर सके और यह सरकार खुद मान चुकी है कि सरकार का रेट आफ टैक्स रियलाइजे 1 न कम है। अध्यक्ष महोदय, आपने हरियाणा में सरकार के पास काबिल आफिसर्ज है। पोजिटिव कानून बनाए जाए ताकि हमें सुप्रीम कोर्ट में न जाना पड़े। मेरे ख्याल से हरियाणा सरकार का एक करोड रुपया तो दिल्ली और हरियाणा एडवोकेट्स ले जाते है। वह पैसा पोजिटिव कामो पर खर्च हो, दवाईयो पर, पढाई पर खर्चा हो लेकिन यह सरकार खर्चा कर रही है दूसरे कामो पर तो कानून बनाने से पहले उस पर गहराई से विचार होना चाहिए। उसके बारे में गहराई से अध्ययन करना चाहिए। लेकिन यह जो अमैडमेंट लाई गई है यह इसलिए लाई गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार को मार पड गई। उस पिटाई से बचने के लिए कानून ही बदल दिया। सरकार ने माना कि हां यह गलत था और फिर उसके बाद एक गलती और कर रहे है। इसलिए मै गुजारि 1 करुंगा कि इस पर बहुत गहराई से विचार होना चाहिए और जल्दबाजी में यह विधेयक पास नही होना चाहिए।

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, यह मेरी समझ में नही आत कि ये इस अमैडमेंट का विरोध क्यों कर रहे है? स्पीकर साहब, मै इन्हे बताना चाहता हूं कि यह एक अच्छी बात है कि वैल्यू आफ परचेज जो है वह ग्रास टर्न ओवर में नही मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐक्ट की सैक्शन 9 को स्ट्रक डाउन कर दिया था इसलिए हमें ये अमैडमेंट लानी पडी। इसमें

एक तरह का स्टेट का ही इंट्रस्ट है क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष से कोई पैसा लेकर सरकार उनको लोगो की भलाई के लिए खर्च करेगी। फिर मेरी समझ में यह नहीं आता कि ये इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? जिस व्यक्ति विशेष से पैसा लेकर सरकार लोगो पर खर्च करेगी उसका यह पक्ष क्यों लेना चाहते हैं।

Shri Ram Bilas Sharma: Sir, my speech was specific. I said that Supreme Court rejected their pleas.

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, इस अमैडमेंट का मकसद सिर्फ इतना है कि इसमें एक तरफ एक पार्टी है और दूसरी तरफ स्टेट है। हम जो यह पैसा उस पार्टी से वसूल करेंगे वह लोगो की भलाई के लिए ही खर्च होगा इसलिए इस अमैडमेंट को लाने की जरूरत पडी। (विधन) न जाने ये किस पार्टी के पक्ष में बोलना चाहते हैं? स्पीकर साहब, मैं तो यही कहूंगा कि इस बिल को पास करने में जितनी देर होगी उतना ही हरियाणा का नुकसान होगा। इसलिए मेरी हाउस से प्रार्थना है कि इसे जल्दी से जल्दी पास कर दिया जाना चाहिए।

Mr. Speaker: Question is-

That this House disapproves the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 2 of 1990.)

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is-

That this House disapproves the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Ordinance, 1990 (Haryana Ordinance No. 2 of 1990.)

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2 to 15

Mr. Speaker: Question is-

That clause 2 to 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Home Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(xiii) दि हरियाणा श्री माता मनसा देवी भाराइन बिल, 1991

Mr. Speaker: Now the Minister of State for Local Government will introduce the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrina Bill, 1991 and also move for its consideration.

Minister of State for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir, I beg to introduce Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrina Bill, 1991.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrina Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrina Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrina Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2 to 41

Mr. Speaker: Question is-

Clause 2 to 41 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Minister of State for Local Government (Shri Kanti Parkash Bhalla): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

श्री राम बिलास भार्मा(महेन्द्रगढ): अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की नजरें इनायत अभी तक तो सरकारी और पंचायतो की

जमीन की तरफ ही थी लेकिन अब इनकी नजर मन्दिरों तक भी जा पहुँची है यानि अब इन्होंने मन्दिरों को भी नहीं बख्खा है। (विघ्न)

स्पीकर साहब, यह बहुत ही अच्छी बात है कि आदरणीय भल्ला जी की नजर भी माता के मन्दिरों पर पड़ी है और इन्होंने इन मन्दिरों को अपना लिया है। कुछ मन्दिरों की व्यवस्था ठीक नहीं है जिस कारण जो श्रद्धालु आते हैं उनमें देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा में कमी होती है। स्पीकर साहब, यह बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार की नजर धर्म-कर्म के कार्यों पर भी गई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस नीयत से आदरणीय भल्ला जी इस बिल को लेकर आए हैं इसे पारित करने के बाद उसी भावना से लागू भी किया जाना चाहिए। यह बात सही है कि कुछ स्थानों पर मन्दिरों की व्यवस्था ठीक नहीं है। स्पीकर साहब, 16 मार्च से नवरात्रे भुरु हो रहे हैं और मनसा देवी के मन्दिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने हेतु आएंगे। (विघ्न) इस सम्मानित सदन का कोई माननीय साथी वहाँ जाता है या नहीं इस बारे में तो मुझे पता नहीं है लेकिन अफसर गैलरी में बैठे कई अफसर तो वहाँ पर जरूर जाते हैं। (विघ्न) जिस व्यवस्था के लिए यह विधान बनाया जा रहा है, मैं यह चाहूँगा कि दक्षिण में जा कर तिरुपति मन्दिर की व्यवस्था को देख कर इसे लागू किया जाए। वहाँ जा कर देखना चाहिए कि किस गजब के ढंग से वहाँ पर काम चल रहा है। उस मन्दिर की आय से युनिवर्सिटी चल रही है, उस पैसे से ट्रांसपोर्ट चल रही है और गरीबों के लिए हस्पताल

चल रहा है। इस बिल को लागू होने के बाद कहीं ऐसा न हो कि 10 रु की मजदूरी करने वाला मजदूर वहाँ पर श्रद्धा से जो सवा रुपया चढा कर आए और उस पैसे को भल्ला जी की सरकार खर्च करके बसे खरीदे और खुद ही उसे जलवा दें। इन्हें तिरुपति जा कर मन्दिरों की व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए और जो पैसा इकट्ठा हो उसकी ठीक व्यवस्था करनी चाहिए तथा श्रद्धालुओं और पब्लिक को दी जाने वाली सुविधाओं पर ही इस पैसे को खर्च किया जाना चाहिए।

स्थानीय भासन राज्य मंत्री (श्री कान्ति प्रकाश भल्ला):

स्पीकर साहब, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा के साथ लगते हुए हिमाचल प्रदेश में जितने भी मन्दिर हैं उन सबके बोर्ड बना दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मेरे आदरणीय साथी राम बिलास जी की पार्टी की सरकार है जहाँ ज्वाला जी और चिंतपूर्णी मन्दिरों की व्यवस्था के लिए बोर्ड बनाए गए हैं। जम्मू में भी मन्दिर की व्यवस्था बोर्ड ही करता है। स्पीकर साहब, जो आय होगी उससे जनहित के कार्य किए जाएंगे, इंस्टीच्यू ांज खोले जाएंगे, लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी तथा मन्दिरों के रख-रखाव का उचित प्रबन्ध किया जाएगा।

Mr. Speaker: Question is-

That the bill be passed.

The motion was carried.

(xiv) दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली

(अलाउंसिज एण्ड पेंशन ऑफ मैम्बरज) अमैडमेंट बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब फाइनेंस मिनिस्टर हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 1991को इन्ट्रोड्यूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे।

Finance Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Member) Amendment Bill, 1991.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Member) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Member) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker Question is-

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Member) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker Question is-

The clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker Question is-

The clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was lost.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was lost.

(xv) दि पंजाब सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर्ज (हरियाणा अमैडमेंट) बिल, 1991

श्री अध्यक्ष: अब रैवेन्यू मिनिस्टर पंजाब सिक्योरिटी आफ लैंड टैन्योर्ज (हरियाणा अमैडमेंट) बिल, 1991 को इन्ट्रोडयूस करेंगे तथा उसे कंसिडर करने के लिए मोान मूव करेंगे।

Revenue Minister (Shri Sachdev Tyagi): Sir, I beg to introduce the Punjab Security of Land Tenures (Haryana Amendment) Bill, 1991.

Sir, I also beg to move-

That the Punjab Security of Land Tenures (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Security of Land Tenures (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Security of Land Tenures (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister will move that the Bill be passed.

Revenue Minister (Shri Sachdev Tyagi): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

डा० हरनाम सिंह (गहबाद): स्पीकर साहब, मैं आपकी सेवा में यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह बिल पढने से तो बडा प्रोग्रैसिव लगता है लेकिन इसमें कई एक कमियां है। मैं उनके बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि यह बात ठीक है कि पहले तो एक मुजारे को नोन-पेमेंट आफ रेंट के आधार पर ही बेदखला किया जाता था। लेकिन अब उसको नही किया जा सकेगा। अब उसको एक मौका मिल जाएगा कि वह रेंट जमा करा कर बेदखली से बच जाएगा। कानून तो यह कहता है कि उसके पास रेंट की रसीद होनी चाहिए लेकिन मालिक रसीद नही देते। जब तीन साल पूरे हो जाते है तो

वे इकट्ठा तीन साल के रेंट का दावा कर देते हैं। 6 फसलो का रेंट यानि इतनी बडी रकम वह दोबारा देकर बेदखली से बच सकता है। इसलिए जो यह रसीद नही मिलती इसका भी कोई न कोई इलाज होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि इसके लिये सरकार जिस तरह से भी हो सके एक साल से ज्यादा का रैन्ट उसकी तरफ नही होना चाहिए। अक्वल में तो एक फसल का रेंट और ज्यादा से ज्यादा एक साल को रेंट उसे वसूलने का अधिकार होना चाहिए। रसीद न देकर वे मुजारे के खिलाफ अदालत में चले जाते हैं। रसीद उसके पास होती नही, उसको दोबारा पेमेंट करनी पडती है। इसके लिए कोई न कोई प्रोवीजन होना चाहिए ताकि वह मुजारा रेंट का पैसा खजाने में जमा करा सके। उसको दोबारा वह पैसा न देना पडे। इसलिए मेरी दरखास्त यह है कि इसके लिये बे एक ऐसा कर दें कि वह मुजारा एक एप्लीके ान तहसीलदार को दे, तहसीलदार उस पर आर्डर कर दे और वह पैसा जमा करा दें। तभी इस बिल का सही में ा पूरा हो सकेगा। नही तो इसमें यही रहेगा कि तीन साल तक तो वह पैसा भी दे दे और बेदखली के लिए भी तैयार रहे। अगर आप उसको पूरा फायदा देना चाहते हो, उसको पूरा इन्साफ दिलवाना चाहते हो और इस बिलको प्रोग्रेसिव करना चाहते हो तो मैने जो यह तजवीज दी है, इसको भी इस बिल में जोडने पर विचार किया जाना चाहिये।

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

सरकारी संकल्प—

जल (प्रदूषण—निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 1988
(1988 का अधिनियम 53) को ग्रहण करने संबंधी

Mr. Speaker: Now the Finance Minister will move for consideration of the Official Resolution.

Finance Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir I beg to move-

Whereas the Parliament enacted the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988) on the basis of the resolution passed by the Legislative Assemblies of the States of Himachal Pradesh and Tripura, to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, to overcome administrative and practical difficulties in effectively implementing the provision of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

And whereas the same difficulties are being experienced in effectively implementing the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act 6 of 1974), and the Legislature of the State of Haryana considers it necessary by passing a resolution to adopt the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988) in pursuance of the provisions of Article 252 of the Constitution of India.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Article 252 of the Constitution of India, the Legislature of the State of Haryana hereby resolved to adopt the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988).

Mr. Speaker: Motion moved-

Whereas the Parliament enacted the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988) on the basis of the resolution pass by the Legislative Assemblies of the States of Himachal Pradesh and Tripura, to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, to overcome administrative and practical difficulties in effectively implementing the provision of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

And whereas the same difficulties are being experienced in effectively implementing the provisions of the Water (Prevention and Control of pollution) Act, 1974 (Act 6 of 1974), and the Legislature of the State of Haryana Considers it necessary by passing a resolution to adopt the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988) in pursuance of the provisions of Article 252 of the Constitution of India.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Article 252 of the Constitution of India, the Legislature of the State of Haryana hereby resolved to adopt the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988).

Mr. Speaker: Question is-

Whereas the Parliament enacted the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988) on the basis of the resolution pass by the Legislative Assemblies of the States of Himachal Pradesh and Tripura, to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, to overcome administrative and practical difficulties in effectively implementing the provision of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974;

And whereas the same difficulties are being experienced in effectively implementing the provisions of the Water (Prevention and Control of pollution) Act, 1974 (Act 6 of 1974), and the Legislature of the State of Haryana Considers it necessary by passing a resolution to adopt the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988) in pursuance of the provisions of Article 252 of the Constitution of India.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Article 252 of the Constitution of India, the Legislature of the State of Haryana hereby resolved to adopt the Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Act, 1988 (Act 53 of 1988).

The motion was carried.

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव—

- (i) वर्ष 1989-90 के लिये हरियाणा राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड कर वार्षिक रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, there is a motion under Rule 84 from Sarvshri Hira Nand Arya and Rattan Lal Kataria, M.L.A's for the discussion of the Annual Report of Haryana State Board for the Prevention & Control of Water Pollution for the year 1989-90. which was laid on the Table of the House on the 5th March, 1991. श्री हीरा नन्द आर्य मोशन मूव करें।

Shri Hira Nand Arya: Sir I beg to move-

That the Annual Report of Haryana State Board for the Prevention & Control of Water Pollution for the year 1989-90. which was laid on the Table of the House on the 5th March, 1991, be discussed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Annual Report of Haryana State Board for the Prevention & Control of Water Pollution for the year 1989-90. which was laid on the Table of the House on the 5th March, 1991, be discussed.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान हरियाणा राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह ठीक है कि अभी जो सरकारी संकल्प पेश किया गया था वह एक जरूरी संकल्प था। उस में सभी प्रकार के प्रदूषण चाहे वह जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, का जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, दोनों प्रकार के प्रदूषणों के लिए जा कानून है उनके तहत

हरियाणा में एका बोर्ड बना हुआ है। जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए पार्लियामेंट ने सब से पहले 1974 में एक ऐक्ट बनाया। उसके बाद 1981 और 1986 में इस ऐक्ट में अमैडमेंट की गईं जिनको कि हरियाणा प्रदेश ने एडोप्ट किया। लेकिन फिर भी इस ऐक्ट तथा बाद में की गईं अमैडमेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ऐडमिनिस्ट्रेटिव और प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आईं जिनके समाधान के लिए पार्लियामेंट ने एक और अमैडमेंट की। अब उस रेजोल्यूशन द्वारा 1988 में की गईं अमैडमेंट को एडोप्ट करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज प्रदूषण जिस प्रकार से फैल रहा है वह केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पेड़-पौधों के लिए भी एक गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। अध्यक्ष महोदय, हम सांस लेते हैं और गन्दी हवा छोटते हैं। उस गन्दी हवा को पेड़ पौधे अपने में समेट लेते हैं और हमारे जीने के लिए शुद्ध हवा छोटते हैं। इस रिपोर्ट में विशेष रूप से दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में जो कारखाने जल प्रदूषण फैला रहे हैं और वायु प्रदूषण फैला रहे हैं उन पर विशेष जोर दिया गया है लेकिन हरियाणा के अंदर जो बोर्ड है, उसका जो उद्देश्य था वह भाग्यद पूर्ण नहीं हो पा रहा है। हरियाणा के अन्दर जहाँ जहाँ जिस प्रकार का प्रदूषण हो रहा है, वह किस प्रकार का हो रहा है, उस प्रदूषण के मामले में अब तक सरकार के पास या कोई सुझाव आये हैं। अगर आये हैं तो उन सुझावों पर सरकार ने क्या कोई कार्यवाही की है? मेरे विचार में अब तक हमारे बोर्ड ने एक काम अवश्य किया है कि बोर्ड के

अधिकारी किसी के पास गये और रिक्कायत पर नोटिस दे दिया। नोटिस देने के बाद अगर उनकी जेब गर्म हो गई तो ठीक है और आगे से छुट्टी हो गयी। इस प्रकार एक प्रदूषण को रोकने के लिये भ्रष्टाचार का दूसरा प्रदूषण फैल रहा है। इसक ऊपर हमें बड़ी ही गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये।

स्पीकर साहब, अब हमारे सामने एक बड़ा अहम सवाल है कि सरकार ने कितनी इकाईयो को प्रदूषण से संबंधित नोटिस जारी किये है और अब तक कितनी इकाईयो के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट में आगरा और गुडगांव नहरो के जल प्रदूषण की बात कही गई है। इसमें केन्द्रीय बोर्ड की परियोजना में भाग लेने ओर अन्तर्राज्यीय प्रदूषण को रोकने के लिए सहयोग देने की बात कही गयी है। इसमें हिमाचल के परवाणु के उद्योगो का हवाला भी दिया गया है लेकिन हरियाणा के अन्दर जितना प्रदूषण फैल रहा है, उसके बारे में जितनी कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए थी, वह नहीं हो रही है। इसकी रोकथाम के लिये कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रदूषण की रोकथाम के साथ साथ जो भ्रष्टाचार वाला प्रदूषण फैल रहा है, उसको रोकने की ज्यादा जरूरत है। यह बड़ा महत्वपूर्ण विशय है, इस पर सरकार को अब य ध्यान देना चाहिये।

श्री रतन लाल कटारिया (रादौर, अनुसूचित जाति):
स्पीकर साहब, मे इस विशय में यह कहना चाहता हूं कि आज

प्रदूषण के कारण सारी मानव जाति को बहुत खतरा पैदा हो गया है आपने देखा होगी कि पिछे जो गल्फ बार चली उसके कारण प्रदूषण का वातावरण फैल गया। उस से काली बरसात हुई और मानव जाति के साथ साथ पंक्षियों को भी उसका िकार होना पडा। हरियाणा प्रदेा के अन्दर भी 2000 इकाईयों को सरकार ने डिटैक्ट किया है जिनके कारण प्रदूषण फैल रहा है। वैस्टर्न यमुना कैनल के अन्दर यमुनानगर और जगाधरी की बडी बडी फैंक्टरीयों का पानी आता है और उस पानी को गन्दा बनाता है। सैकडो गांव जो इस कैनल के साथ लगते है, वहां के लोग उस पानी को पीते है जिस कारण से उन्हे तरह तरह की बीमारियो का सामना करता पडता है।

इसी तरह से गन्ने की मिलो का भी बुरा हाल है। भाहबाद के अन्दर एक भुगर मिल है जिसका पानी बबैन की तरफ जाता है जिस कारण से उस इलाके में बडी गन्दी बदबू होती है। इसलिए मै सरकार से यह निवेदन करुंगा कि जो इस तरह के वास्तविक केसिज है, उनको डिटैक्ट करके उनका समाधान किया जाए और लोगो की प्रदूषण से होने वाली बीमारियो से छुटकारा दिलवाया जाए। इन भाब्दो के साथ मै आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं। जय हिन्द।

(ii) वर्ष 1987-88 के लिए हरियाणा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक वित्तीय लेखे

Mr. Speaker: Hon. Members, there is a motion under Rule 84 from Shri Hira Nand Arya, M.L.A. for the discussion of the Annual Financial Accounts of Haryana Khadi and Villages industries Board for the year 1987-88, which was laid on the Table of the House on the 5th March, 1991. He may please move his motion.

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मैं इसे मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

(iii) हरियाणा पिछडा वर्ग आयोग, 1990 जिसकी अध्यक्षता न्यायाधी । गुरनाम सिंह ने की थी की रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, there is a motion under Rule 84 from Sarvshri Hira Nand Arya, Bhag Mal, Rattan Lal Kataria and Ram Bilas Sharma, M.L.A. for the discussion of the Report of Haryana Backward Classes Commission, 1990, headed by Justice Gurnam Singh, which was laid on the Table of the House on the 5th March, 1991. Shri Hira Nand Arya may please move the motion.

Shri Hira Nand Arya: Sir, I beg to move-

That the Report of Haryana Backward Classes Commission, 1990, headed by Justice Gurnam Singh, which was laid on the Table of the House on the 5th March, 1991, be discussed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Report of Haryana Backward Classes Commission, 1990, headed by Justice Gurnam Singh, which was laid on the Table of the House on the 5th March, 1991, be discussed.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारु): अध्यक्ष महोदय, इस पर चर्चा करने से पहले मैं एक बात आपके द्वारपा सरकार को बताना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट जी पे 1 की गई है इसके साथ सरकार ने जो गजट नोटिफिके 1न की है उसकी कापी नहीं है। इसें टर्म्ज एण्ड रैफरेंसिज तो द रखे है। जब तक गजट नोटिफिके 1न की कापी इसके साथ नहीं होगी तो इस रिपोर्ट को डिस्कस करना कोई मायने नहीं रखता। इसलिए सरकार बताए कि यह एज इट इज है या नोटिफिके 1न हुई है दूसरी बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट देते वक्त चेयरमैन ने तो कुछ कहा है और जो मैम्बर है उन्होने उससे अलग से रिपोर्ट दी है। अब सरकार यह बताए कि अगर कोई गजट नोटिफिके 1न किया है वह चेयरमैन की रिपोर्ट के बेस पर किया है या मैम्बरो की रिपोर्ट के बेस पर किया है या दोनो से अलग किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर राजपूत इसमें भामिल नहीं है। पहले सरकार स्थिती स्पष्ट कर दे उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा।

श्री बनारसी दास गुप्ता(भिवानी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से केवल एक बात रखना चाहता हूं कि गुरनाम सिंह कमि 1न की जो रिपोर्ट आई, इसमे जिन जिन जातियो को बैकवर्ड में भामिल किया, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन

मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अपर कास्ट को जो पांच परसेंट रिजर्वेंशन दी गई है वह बहुत कम है। ब्राहमण के साथ गरीब भावद जुडा हुआ है। लोग कहे है कि बेचारा गरीब ब्राहमण है। (विधन) बनियो मे भी जो गरीब है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बनिए की मिसाल बताता हूँ। मेरे पास एक बनिया आया। वह ऐडहाक पर चपडासी लगा हुआ था और उसकी आठ साल की सर्विस हो चुकी थी। उसने कहा कि मेरी सर्विस हटा दी है। उसने बताया कि मेरे घर में पांच मैम्बर है ओर वे मेरी ही तन्खाह पर डिपैन्ड करते है। मेरी कमाई का कोई और साधन नही है। तो ऐसे बनिए भी बहुत है और ब्राहमण भी बहुत है। पंजाबीयो के अन्दर भी बहुत सारे ऐसे है। वी० पी० सिंह जी ने भी पार्लियामेंट के अन्दर यह कहा था कि अपर कास्ट मे दस से पन्द्रह परसेन्ट तक रिजर्वेंशन दी जाए। तो यह रिजर्वेंशन पांच परसेन्ट से बढा कर 15 प्रतिशत होनी चाहिए।

श्री रतन लाल कटारिया (रादौर, अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, गुरनाम सिंह रिपोर्ट में जिन जिन जातियो के बारे में उन्होंने अपने रिमार्कस दिए है उनके बारे में मेरा कोई मतभेद नही है। स्पीकर साहब, यह महान सदन जानता है कि हिन्दुस्तान की हजारो सालो तक गुलामी सहनी पडी।

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब, मुझे इलैबोरेशन नही चाहिए। आप इसी रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहे वह कहें। आपको सिर्फ पांच मिनट बोलने के लिए मिलेंगे।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैं पांच मिनट ही बोलूंगा, छटा मिनट नहीं लूंगा। स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान को हजारों साल गुलामी सहनी पड़ी लेकिन जब इस देश के नेताओं और भाषीदों ने इस देश को आजाद कराया और उसके बाद जब संविधान बना तो उसमें इस बात की व्यवस्था की गई थी कि आजाद मुल्क के अन्दर जो लोग हजारों सालों तक पीड़ित रहे उनको समाज में बराबर के हक दिए जाएं। जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग दलित हैं, जो लोग आर्थिक दृष्टी से बैकवर्ड हैं ऐसे लोगों को आरक्षण की सुविधाएं देनी चाहिए। चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे कोई ऋण देने का मामला हो और चाहे उनका सोशल स्टेटस उपर उठाने का मामला हो।

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब, आप पिछली बातों पर न जाएं आप इसी रिपोर्ट से संबंधित बोलें।

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैं इसी पर आ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब, आप अपनी बात दो मिनट में खत्म करें।

श्री रतन लाल कटारिया: ठीक है जी, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर देता हूँ। हरियाणा सरकार ने जिन जातियों को इसमें बैनिफिट देने के लिए प्रावधान किया है पहले उन जातियों के बारे में हरियाणा सरकार ने सर्वे किया होगा। सर्वे

करने के बाद ही यह पता लगा होगा कि ये जातियां डिजर्व करती हैं, लेकिन कई बार इस प्रकार की उंगलियां उठ जाती हैं कि जो जातियां अपने आपको मा ल रेस कहलाया करती थीं और जिन्होंने इस देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दीं उन मा ल रेसिज को इसमें सम्मिलित किया गया है। आप जानते हैं कि इस देश में गरीबी फैली हुई है उससे जाट, राजपूत, ब्राहमण और बनिया भी पीड़ित हो सकते हैं। उनके लिए जो 5 परसेंट आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसके बारे में मेरी प्रार्थना है कि अगर कुछ देना ही है तो कम से कम उनको भी 15 परसेंट आरक्षण दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब, आप बैठिए। श्री राम बिलास भार्मा।

श्री राम बिलास भार्मा(महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन के पटल पर रखा गया है जिसके ऊपर सदन से बाहर भी बड़ी भारी चर्चा हुई है। इसी सरकार ने इसी सदन में कहा है कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट का बड़ा भारी विरोध हुआ और उस विरोध के तैवर बहुत ऊपर थे। इस छोटे से प्रान्त में इस सदन की सूचना के अनुसार 18 लोगो ने आत्म हत्याएं की ओर 42.6 करोड रुपए की हानि इस प्रदेश में हुई स्वीकार की गई। अध्यक्ष महोदय, कभी भी चाहे किसी का रहा, कुल प्रशासक और इतिहासकार ने लिखा है कि जिसने अपने विरोध की जांच स्वयं की, लोगो की ग्रीवेंसिज को दूढ़ करके पता

किया, चाहे वह विक्रमादित्य राजा था, चाहे वह राजा रामचन्द्र था वह कामयाब रहा। राजा रामचन्द्र ने तो छाजू नाम के एक छोटे से गरीब आदमी के कहने से अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ली थी। उन्होंने कहा था कि राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि अगर प्रजा का एक आदमी भी मेरी किसी बात का विरोध करता है तो मेरे लिए उस विरोध की कीमत है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने गुरनाम सिंह कमिशन बनाया। इस सरकार ने इस सदन में कहा कि जो मण्डल कमिशन की रिपोर्ट थी वह गलत समय पर लागू कर दी गई और उस रिपोर्ट को लागू करने से पहले किसी से सलाह नहीं की गई। इन्होंने तो कह दिया कि हमारी 9 तारीख की रैली से हिंदुस्तान के गरीबों में एक चेतना आनी थी, उससे बचने के लिए बी० पी० सिंह ने 7 अगस्त को वह मण्डल कमिशन की रिपोर्ट जारी कर दी। हमारे मित्रों ने मण्डल कमिशन की रिपोर्ट से बचने के लिए भायद गुरनाम सिंह कमिशन बना दिया। अध्यक्ष महोदय, जो प्रयासक होता है वह न सुनने का आदि नहीं होता। हमारे गांवों में एक कहावत है कि घर की बही और काको लिखणियो चाहे किमे लिख लो। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नर सिंह ढांडा की बारात में गया था। नर सिंह ढांडा मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं।

श्री अध्यक्ष: कौन सी बारात में? (हंसी)

श्री राम बिलास भार्मा: पहली बारात में। मैं वैसे तो पेड़ों से किसान हूँ, खेती करता हूँ परन्तु जन्म से मेरे जिम्मे एक जिम्मेदारी और भी है कि अगर मेरा कोई जजमान अटका रह जाए,

उसका ब्याह न होता हो तो उसका मैं ब्याह भी करवाता हूँ?
(हंसी)

खाद्य एवं पूर्ति मंत्री (श्री नर सिंह ढांडा): स्पीकर साहब, भार्मा जी मेरी भाादी के बारे में कह रहे हैं। इन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी आदमी का ब्याह नहीं होता हो तो मैं यह भी करवता हूँ। हमारे बहुत ही आदरणीय डाक्टर मंगल सैन जी भगवान को प्यारे हो गए, इन्होंने उसका ब्याह क्यों नहीं करवाया।
(विघ्न)

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, हम नर सिंह ढांडा जी की भाादी में बडे बढ-चढ कर के गए और इनकी भाादी करवा कर लाए। भाई को घोडी पर बैठा कर लाए। उसके बाद मुझे इनके घर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। (गोर) स्पीकर साहब, उसके बाद गुरनाम सिंह कमि ान की रिपोर्ट लागू करने के बाद जब ये घर गए तो मुझे भी इनके घर जाने का मौका मिला। उसी समय इनकी चौधरन कहने लगी कि मैं मालिकां की छोरी हूँ अब तू पंडे को हाथ नहीं लगाना क्योंकि अब तुम बैकवर्ड हो गए हो। (हसी) स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस रिपोर्ट को लागू करके इन्होंने घर-घर में झगडे भुरु करवा दिए हैं और विवाद पैदा कर दिए हैं। स्पीकर साहब, एक दिन मैं रोहतक में किंगजवे कैम्प में था (विघ्न)

पुपालन राज्य मंत्री (श्री कुलबीर सिंह मलिक):
स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। इन्होने कहा था
कि ढाडा साहब की भादी इन्होने कराई थी। मै पूछना चाहता हू
कि क्या इनकी कराई हुई भादी टूटेगी तो नहीं? (हंसी)

श्री राम बिलास भार्मा: हमारी कराई हुई भादी तो जरूर
टिकेगी लेकिन जो तुम लोग कोर्ट में जाकर भादी करने लगे हो
वह जरूर टूटेगी। (हंसी)

श्री मनी राम: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर
सर। स्पीकर साहब, मै पंडितो की एक बात आपको बताना चाहता
हू। एक बार भादियो का सीजन जोरो से चल रहा था। उस समय
एक पंडित जी ने बहुत सारी भादियां कराये जाने का जिम्मा अपने
उपर ले लिया। एक दो भादी ठीक कराये जाने के बाद अन्य
भादियो को कराये जाने के चक्कर में वह किसी भादी में एक
फेरा करा कर भादी खत्मकर देता और किसी में दो फेरे या तीन
फेरे कराकर भादी को खत्म कर देता। जब एक जाट की भादी
वह कराने पहुंचा तो वहां पर भी एक दो फेरे करवा कर जब
भादी खत्म करने लगा तो वह जाट कहने लगा कि पंडित जी
भादी तो 7 फेरो में पूरी होती है, आप दो तीन फेरो में पूरी
भादी कैसे कर रहे है।? इस पर पंडित कहने लगा कि अगर इसने
टिकना है तो दो फेरो में भी टिक जाएगी नहीं तो फिर यह 7
फेरो में भी नहीं टिकेगी (हंसी) स्पीकर साहब, मेरे कहने का
मतलब यह है कि इन द्वारा कराई गई भादी क्या टिकेगी? (हंसी)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैने तो पहले ही कहा है कि हमारी कराई हुई भादी तो जरूर टिकेगी। (विघ्न)

श्री कुलबीर सिंह मलिक: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, इसी तरह से एक बार एक पंडित किसी भादी में फेरे करा रहा था और साथ में गणे 1 जी की मूर्ती रखी हुई थी। फेरे कराते कराते वह कहने लगा कि एक रुपया गणे 1 जी के नाम का। भादी वाला एक रुपया रख देता था। थोड़ी देरी बाद फिर कहने लगा कि रख एक रुपया तो वह फिर रख देता था। इसी प्रकार वह 5 रुपये रख चुका था। उस आदमी ने बाद में तंग आकर पंडित का गणे 1 चुरा लिया। जब थोड़ी देर बाद पंडित फिर कहने लगा कि रख एक रुपया तो वह आदमी कहने लगा कि पंडित तो गणे 1 तो पहले ही मेरे पांच रुपए चुरा कर भाग गया अब किस नाम के पैसे? (हंसी)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, इन रिपोर्ट का मलिक साहब को भी दुःख है क्योंकि इस रिपोर्ट के आने से इन पर भी असर पडा है। स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गुरनाम सिंह की रिपोर्ट आई है वह राजनीति से प्रेरित है, गरीब लोगो की भलाई के लिए नहीं है। प्रिंसिपल आफ इक्वैलिटी के हिसाब से भी यह गलत है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट गलत है और दूसरी तरफ खुद सरकार द्वारा गुरनाम सिंह आयोग उसी तरह का बैठाया जाता है। (विघ्न) यह आयोग क्यों बैठाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आर्डर

कर रखे है कि कोई भी स्टेट 50 प्रति तात से अधिक रिजर्वे तान नहीं कर सकती? स्पीकर साहब, रिजर्वे तान की बात कहां से आई वह भी मै बता देता हू। राजनीति में एक प्रतिस्पर्धा, एक कम्पीटी तान होता है टैलेंट को परमोट करने का। दुनिया के जिन दे ता ने विकास की चरम सीमा को छुआ है उन दे ता ने टैलेंट को परमोट किया है यह आज तक हमने नहीं देखा कि कोई स्टेट गवर्नमेंट टैलेंट को परमोट करने की बजाये उसे डिमोट करे। राजनीति की बात अलग है लेकिन हमने टैलेंट को डिमोट होते नहीं देखा। स्पीकर साहब, इसमें गरीब के कल्याण की भावना नहीं है। (विघ्न) गरीबो के कल्याण की बजाए यह तो राजनैतिक स्वार्थ की बात है। अध्यक्ष महोदय, एक कमि तान मुकर्रर होता है (विघ्न) यह कमि तान 17सितम्बर को विधिवत् रूप से कान्सटीच्यूट हुआ और एक माननीय रिटायर्ड न्यायधी ता श्री गुरनाम सिंह को इस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले मेहम की एक जनसभा में दे ता के डिप्टी प्राईम मिनिस्टर ने यह घोशणा की कि हम फलां-फलां जातियो को रिजर्वे तान दे रहे है। (विघ्न) उप प्रधान मंत्री जी ने कहा अरे बावलो थाने के बेरा कि हरियाणा का राज कौन चलावे। आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 हरियाणे का राज चलावे इनकी गिनी 200 सै। इन दो सौ मे से 70 बनिया, 70 पंजाबी और 70 पंडित है। किसी ने कहा कि यह तो 210 हो गये तो उप प्रधान मंत्री जी ने जवाब दिया कि 10-20 का मेरी संख्या मे कोई फर्क नहीं पडता अध्यक्ष महोदय, गुरनाम सिंह कमी तान से पहले ही बाप-बेटे ने जगह जगह घोशणा कर दी कि हम

नौकरियों में फला-फलां जातियों को रिजर्वे इन दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो एक राजनैतिक नारा है, गरीबों के भले की इसमें कोई बात नहीं है।

Mr. Speaker: Please wind up now.

श्री राम बिलास भार्मा: कमी इन के सैक्रेटरी हमारे योग्य अफसर डा० सुखबीर सिंह जी ने हम को चिट्ठियां लिखी जिनका हमने जवाब दिया। वे चिट्ठियां इस रिपोर्ट में इनकार्पोरेट की गई हैं। हमारे जनता दल के साथी राव राम नारायण ने भी कमी इन को चिट्ठी लिखी थी। बैकवर्ड क्लासिज को आईडेंटिफाई करने के लिए दो बार नोटिफिके इन हुई जिसे इस कमी इन के कान्सटीच्यू इन में माना गया है। पहले नोटिफिके इन में यह कहा गया है That this Commission is constituted to identify backward classes whether they may be educationally backward or socially backward. Then they incorporated the second terms of reference regarding economically backwardness. कई इकनोमिकली बैकवर्ड लोग भी हैं जिनको इसमें शामिल किया जाए। हमारे योग्य अफसर डा० सुखबीर सिंह जी ने जिन लोगों को पत्र लिखे उनमें से एक के जवाब में हमारे साथी राव राम नारायण ने पत्र लिखा था जिस बिरादरी से वे हैं उसे भी इसमें शामिल किया गया है। हमें इस बात की खुशी है। राव राम नारायण जी ने जो पत्र लिखा उस में उन्होंने सच्चाई बयान की है। उस में यह कहा गा है कि जो गौड ब्राहमण, राजपूत, जाट जातियां हैं, they are forward. They are

not socially backward. They are socially forward as far as services quots is concerned and as far as their social status is concerned. आज हरियाणा में जो पिछड़े लोग है उनको सहारा मिले तो यह अच्छी बात है। यदि सरकार उनको कुछ मदद देती है तो हम उसका स्वागत करते है। भारत के संविधान में बाबा भीम राम अम्बेडकर जी ने हरिजनो और पिछड़े लोगो की सहायता के लिए, उनको सुविधा देने के लिए एक परम्परा जोडी थी जिसके कारण गरीबो और हरिजनो को रिजर्वे इन की सुविधा दी गई थी जिसके कारण गरीबो और हरिजनो को रिजर्वे इन की सुविधा दी गई थी ताकि भाताब्दियो तक उनका जो भाशण होता रहा, उनका भी सामाजिक स्तर उंच उठ सके। अध्यक्ष महोदय, यह जो गुरनाम सिंह कमी इन की रिपोर्ट है यह तो उन गरीबो के हितो को चोट पहुंचाने की एक साजिा है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि आज का युग अथ्रप्रधान युग है। चाहे कोई कितना भी बडा विद्वान हो, उसके पुरखे चाहे कितने भी बडे रहे हो लेकिन आज अगर उसके पास गांव में जमीन नही है, उसके पास पैसा नही है तो समाज मे उसका कोई स्थान नही, कोई सम्मान नही। आज अगर कोई रामलीला का उदघाटन भी करवाना चाहता है तो किसी गरीब विद्वान को नही ढूंढा जाता बल्कि ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाता है जो कम से कम 100 रुपये दे। अध्यक्ष महोदय, मै यह कहना चाहता हूं कि आज का युग अर्थ-प्रधान युग है इसलिए इसका जो कार्टेरिया होना चाहिए था वह आर्थिक ही होना चाहिए था। चौधरी राम नारायण सिंह जो एम0 पी0 थे और हरियाणा के

काबिल आई० ए० एस० अफसर रहे थे। He also asserted my point. His sentiments have been incorporated in this Report. He opined that-

The true measure of judging backwardness should be the social, educational and economic status of the person or the group of persons concerned.

Therefore, Sir, the basic principle to identify backwardness should be the economic status of the person.

Mr. Speaker Please take your seat now.

श्री राब बिलास भार्मा: यह जो गुरनाम सिंह कमी इन रिपोर्ट है इसके पीछे अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक नारे के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह सामाजिक तनाव पैदा करने के लिए है। इसके अलावा यह कुछ भी नहीं है। इनको इसमें आर्थिक आधार बेसिज रखना चाहिये था। लेकिन यह सब कुछ गरीबों के हितों को ताक पर रख कर किया गया है। धन्यवाद।

गृह मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, 7 सितम्बर 1990 को यह गुरानाम सिंह कमी इन बनाया गया और रिटायर्ड जस्टिस श्री गुरनाम सिंह इसके चेयरमैन बनाए गए। मेरे साथी राम बिलास जी ने और दूसरे कई साथियों ने भी यह कहा कि मंडल कमी इन के विरुद्ध यह गुरनाम सिंह कमी इन बिठाया गया। स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है। मंडल कमी इन के बाकायदा हम पक्षधर हैं। हमारे नेता चौधरी देवी लाल जी ने इसकी रिपोर्ट को लागू कराने के लिए बाकायदा जेले काटी है और इनके लिए

बकायदा संघर्ष करते रहे हैं। हमने बकायदा इसको स्पोर्ट किया है। अब इन्होंने यह कहा कि यह हो गया, वह हो गया, तनाव हो गया। जब ऐसी बात हुई तो हमने उससे एक्सपीरियेंस लिया। अनुभव का फायदा लिया कि कोई भी रिपोर्ट लागू करनी हो तो बकायदा सोच कर लागू करनी चाहिये। हमने ऐसा सोचा की पहले लोगो में अपनी बात को ले जाए। लोगो को हम समझाएं। अखबारो के माध्यम से समझाएं, जलसो के माध्यम से समझायें, लोगो तक यह बा जानी चाहिये कि सरकार क्या करने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंडल कमी इन रिपोर्ट इस तरह से लागू नहीं हुई। हालांकि सारे इसको चाहते हैं लेकिन जब यह मंडल कमी इन की रिपोर्ट आयी तो हम लोग किसी भी आदमी को यह समझानही पाये कि यह रिपोर्ट क्या है। जैसे राम बिलास जी ने कहा, अकेले हरियाणाके अन्दर ही नन्हे नन्हे बच्चे और बच्चियां 18 के करीब सुसाईड कर गए। उनकी इस नादानी से हमको नुकसान हुआ। लेकिन वे नादान इसको समझ नहीं पायें कि इससे उनको कोई नुकसान नहीं होना था। इसके साथ ही स्टेट की प्रोपर्टी का भी नुकसान हुआ है। सारी बातें इस प्रकार से हुई हैं। अब सरकार ने इसलिए बार बार मिटिंगज करी, लोगो की बातें सुनी। हर जिले के अन्दर वह कमी इन गया । उसने लोगो कीबातें सुनी। रिप्रेजेटे इन लोगो से लिये। अखबारो में उसका जिक भी आया। जलसो में और पब्लिक मीटिंगज के द्वारा जैसे उन्होंने यह कहा कि बाबू-बेटा इसका समर्थन कर रहे थे, हमने बकायदा इसका समर्थन किया, प्रचार किया कि ये चीजे हम चाहते

है। सरकार की यह इंटेंशन है। अगर हमें यह कमीशन रिपोर्ट दे देता है तो सरकार उसको लागू करेगी, यू ही नहीं किया है। जाने अनजाने में लागू नहीं किया है। हमने बकायदा सोच समझ कर इसे लागू किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा सोच कर किया गया कि ऐसी कम्यूनीटीज भी हैं जो आर्थिक तौर पर सामाजिक तौर पर और शिक्षा के तौर पर बड़ी बैकवर्ड हैं। उनकी बहुत बुरी दशा है। अकेली चौधराहट से बात नहीं बनने वाली। जैसे राम बिलास भार्मा जी ने कहा कि आज अर्थ की कीमत है। अर्थ का मतलब यह है कि उन लोगों की आर्थिक दशा सुधारी जाए। हमने उनकी आर्थिक दशा सुधारनी चाही है। गुरनाम सिंह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में प्वायंट आउट किया है कि इन कम्यूनीटीज को रिजर्वेशन दी जाये ताकि ये नौकरियों में आ पायें। (व्यवधान एवं भाोर) स्पीकर साहब, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कोई प्रोवीजन नहीं था कि लोगों को पढाया कैसे जायेगा, जब पढे लिखे लोग ही नहीं होंगे तो नौकरी में कैसे आयेंगे। आप उनको कैसे नौकरी दे पाआगे। लेकिन इसमें दोनो बातें हैं। स्पीकर साहब, कैसे उनको नौकरियां दी जाएगी और कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सारी चीजे इसमें प्वायंट आउट की गयी हैं। दोनो चीजों का इसमें प्रोवीजन है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अन्दर और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के अन्दर भी नके लिए रिजर्वेशन है कि अगर उनको ट्रेनिंग मिलने के बाद नौकरी नहीं मिलती है तो कैसे किया जायेगा। यह बात नहीं है कि टोटल जातिको ही रिजर्वेशन दी जायेगी। एक परिवार में एक

आदमी आई० ए० एस० है। कोई बहुत बड़ा जमींदार है या बहुत बड़ा बिजनैसमैन है और चांस है कि वह बैकवर्ड क्लासिज या रिजर्वे इन दी जायेगी क्योंकि वह सदिया से पीडित रहे है। इसलिए बैकवर्ड क्लासिज और रिजर्वे इन के लिए जो रिजर्वे इन दी हुई है, वह तो ठीक है लेकिन अदर दैन बैकवर्ड क्लासिज यानि ओ० बी० सी० के अन्दर अगर सब के लिए रिजर्वे इन कर दी जाती तो यह एक बहुत बड़ा अन्याय होता जैसे की पहले ही रहा है। स्पीकर साहब, एक परिवार में दस दस आदमी रिजर्वे इन का फायदा उठा रहे है। पब्लिक स्कूलों में जिनके बच्चे पढ रहे है और वे आफिसर है वे लोग भी रिजर्वे इन का फायदा ले रहे है। कमी इन की इस रिपोर्ट में ऐसी बात नहीं है। इस रिपोर्ट में कुछ कंडी शर्त रखी है कि कौन कौन से लोग रिजर्वे इन के फायदे के अधिकारी नहीं होंगे। स्पीकर साहब, मैं बताता हूं कि कौन कौन लोग इस फायदे के अधिकारी नहीं होंगे। क्लास वन, क्लास टू के अधिकारियों को फायदा नहीं होगा। जो लोग प्राइवेट जाब में है और क्लासवन और क्लास टू के अधिकारियों के बराबर तन्खाह ले रहे है उनको फायदा नहीं होगा। डाक्टर, लायर्ज, चार्टिड अकाउंटेंट, इंजीनियर इनको फायदा नहीं होगा। जो इंकम टैक्स देते है और जो सेल्ज टैक्स असैसी है उनको फायदा नहीं होगा। जिन लोगो के पास आठ एकड से ज्यादा जमीन है उनको फायदा नहीं होगा। लैक्चर है, प्रोफैसर्ज है उनको फायदा नहीं होगा। स्पीकर साहब, इतनी कैटेगरीज है

जिनको रिजर्वे इन का फायदा नहीं होगा। पूरी तरह से सोचकर यह रिपोर्ट लागू की गई है ताकि गरीब आदमी को इससे फायदा हो।

(iv) वर्ष 1988-89 के लिए हरियाणा कृषि उद्योग लिमिटेड की

21वीं वार्षिक रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon'ble Members, there is a motion under Rule 84 from Shri Hira Nand Arya, M.L.A for the discussion of the 21st Annual Report and Accounts of Haryan Agro-Industries Corporation Ltd. for the year 1987-88. He may please move his motion.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं इसको मूव नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

(v) वर्ष 1988-89 के लिए हरियाणा कृषि उद्योग लिमिटेड की

22वीं वार्षिक रिपोर्ट

Mr. Speaker: Hon' Members, there is a motion under Rule 84 from Shri Hira Nand Arya, M.L.A for the discussion of the 22nd Annual Report and Accounts of Haryana Agro-Industries Corporation Ltd. for the year 1988-89. He may please move his motion.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मै इसको मूव नही करना चाहता।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

वक्तव्य—

गृह मंत्री द्वारा मंडल आयोग विरोधी आंदोलन के दौरान श्री सूरज भान, एम0 एल0 ए0 के घर पर हुए हमले संबंधी

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, इस सै ान के दौरान चौधरी सूरज भान के मकान को आग लगाने के बारे में कई बार चर्चा हुई थी और 4-3-1991 को तारांकित प्र न सं0 1220 पर हुए सप्लीमेंटरी का जवाब देते हुए मैने कहा था कि इसी सै ान के दौरान मै सदन को इस केस की जानकारी दूंगा। इसलिए मै इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। स्पीकर साहब, 21-9-1990 को एक भीड ने चौधरी सूरज भान के मकान पर अटैक किया था। सवाल यह था कि केस दर्ज हुआ या नही। मै सदन को बताना चाहता हूं कि केस एफ0 आई आर0 नं0 319 दिनांक 21-9-1990 को अन्डर सैव ान 147, 148, 149, 151, 152, 427, 332, 353, 354, 380, 435, 436, 477, 186, 188, दर्ज हुआ था। स्पीकर साहब, यह केस अम्बाला कैंटमें दर्ज हुआ था। इस केस में तीन आदमी गिरफ्तार किए जा चुके है और कुछ लोगो को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसलिए स्पीकर साहब, यह केस अभी अन्डर इंवैस्टीगे ान है।

श्री सूरज भानः स्पीकर साहब, मैने कहा था कि ए० एस० आई० को मैने जो स्टेटमेंट लिखवाया था उसमें तीन आदमियो के नाम लिखवाये थें। उनको मै पहचानता हूं। उनके हाथ में तेल के पीपे थे। वे आदमी थे संजय मिततल, सुखलाल और अर्जुन लाल कालडा। मै जानना चाहता हूं कि क्या इन तीनों आदमियो को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और क्या इनके खिलाफ एफ० आई० आर० दज की गई और क्या इनको गिरफ्तार किया गया है?

प्र० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, बकायदा इन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी उसको लिखा गया था। इन तीनों को थाने में बुलाया गया। इनमें से एक संजय मिततल को गिरफ्तार किया गया। दूसरे के बारे में जांच चल रही है कि आया ये लोग भी उसमें इन्वाल्व थे। स्पीकर साहब, तीस आदमी टोटल अरैस्ट किए गए हैं।

श्री राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि तीस आदमी गिरफ्तार किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य ने अपने स्टेटमेंट में तीन लोगों के नाम लिखवाए और कहा कि मै इन तीनों आदमियो को पहचानता हूं। इन तीनों के नाम बताए। एक का नाम अर्जुन लाल कालडा लिखवाया। उस आदमी ने चुनाव लडा लेकिन उसको फिर सर्विस में ले लिया और पानीपत में नगरपालिका सैक्रेटरी लगा

दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, केवल मात्र नाम लेना ही काफी नहीं जिसके आधार पर उसको गिरफ्तार किया जाए। बकायदा तीस आदमी गिरफ्तार किए गए और केस की फरदर इन्वैस्टीगेशन पेंडिंग है।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I am thankful to all sections of the House for the cooperation extended to me in conducting the proceedings of the House.

अब हाउस साइने डाइ ऐडजर्न किया जाता है।

13:34 बजे

(तत्पश्चात् सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ।)